



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]
No. 289]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2012/ज्येष्ठ 30, 1934
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012/JYAISTHA 30, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 33/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 466(अ).—अभिहित प्राधिकारी, यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय) (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2905 42 के अंतर्गत आने वाले एंटारीओटोल (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 10 अप्रैल, 2012 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/43/2010 डीजीएडी, तारीख 10 अप्रैल, 2012 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि:—

- (क) संबद्ध माल भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है संबद्ध देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था, जिसके कारण पाटन हुआ था;
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध माल पर वास्तविक क्षति हुई थी; और
- (ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी और यह क्षति संबद्ध देश से उदगमित या निर्यातित पाटित आयातों के कारण हुई थी;

और संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तरम् (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त 2012/6/20

सारणी के स्तंभ (7) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्त्वानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित करेसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्त्वानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्त्वानी प्रविष्टि में इगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है

सारणी

क्रम सं०	उपशीर्ष (2)	माल का विवरण (3)	विशिष्टता (4)	उदगम देश (5)	देश का निर्यातक (6)	उत्पादक (7)	निर्यातक (8)	राशि (9)	इकाई (10)	करेसी (11)
1	2905 42	पेटाएरीश्ट्रिटोल	कोई	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	मै. पर्सटोरप केमिकल जीएमबीएच	मै. पर्सटोरप केमिकल जीएमबीएच	379	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	2905 42	पेटाएरीश्ट्रिटोल	कोई	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	कोई	कोई	490	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	2905 42	पेटाएरीश्ट्रिटोल	कोई	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	कोई	कोई	490	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	2905 42	पेटाएरीश्ट्रिटोल	कोई	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	कोई (चाइना और ताईवान के सिवाय)	कोई	कोई	490	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	2905 42	पेटाएरीश्ट्रिटोल	कोई	कोई (चाइना और ताईवान के सिवाय)	यूरोपियन संघ (स्वीडन के सिवाय)	कोई	कोई	490	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खंडन, अधिकांत और सशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दित की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/7/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिव्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 33/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 466(E).—Whereas, in the matter of import of Pentaerythritol (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2905 42 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said customs Tariff Act), originating in, or exported from European Union (excluding Sweden)(hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its final findings No. 14/43/2010-DGAD dated the 10th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th April, 2012, had come to the conclusion that-

- (a) The subject goods have entered the Indian market from the subject countries below associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods;
- (b) The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and
- (c) The material injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description

of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said

Table:-

TABLE

Sl. No.	Sub- heading	Description of goods	Specifica- tion	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	290542	Pentaerythritol	Any	European Union (excluding Sweden)	European Union (excluding Sweden)	M/s. PERSTORP CHEMICALS GMBH	M/s. PERSTORP CHEMICALS GMBH	379	MT	US\$
2.	290542	Pentaerythritol	Any	European Union (excluding Sweden)	European Union (excluding Sweden)	M/s. PERSTORP CHEMICALS GMBH	Any	490	MT	US\$
3.	290542	Pentaerythritol	Any	European Union (excluding Sweden)	European Union (excluding Sweden)	Any	Any	490	MT	US\$
4.	290542	Pentaerythritol	Any	European Union (excluding Sweden)	Any excluding China and Taiwan	Any	Any	490	MT	US\$
5.	290542	Pentaerythritol	Any	Any excluding China and Taiwan	European Union (excluding Sweden)	Any	Any	490	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, amended and superseded earlier) from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/7/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 25/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 467(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (साजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सेवा कर तारीख 17 मार्च, 2012 को, जो भारत के संज्ञपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 210(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह समाधान हो जाने पर की लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित करारेय सेवाओं को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ख. के अधीन उन पर उद्दलक्षीय संपूर्ण सेवा से छूट देती है, अर्थात्:—

1. संयुक्त राष्ट्र या किसी विनिर्विष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रदान की गई सेवाएं;
2. किसी नैदानिक स्थान, किसी प्राधिकृत विकिल्सा व्यवसायी या पर्स-विकिल्सकों द्वारा दी गई स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं;
3. पशुओं या पक्षियों के स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में किसी पशु-विकिल्सा क्लीनिक द्वारा दी गई सेवाएं;
4. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई द्वारा पूर्ण क्रियाकलापों के रूप में दी गई सेवाएं;
5. किसी व्यक्ति द्वारा—
 - (क) सर्वसाधारण के लिए अमिश्र विक्सी धार्मिक स्थान की परिसीमाओं को क्रियाएं पर देकर; या
 - (ख) किसी धार्मिक समाजेव के संबलन द्वारा दी गई सेवाएं;

6. निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त सेवाएँ-

(क) किसी मध्यस्थता अधिकरण द्वारा निम्नलिखित को -

(i) कारोबारी संगठन से इतर किसी व्यक्ति को; या

(ii) किसी कारोबारी संगठन को जिसका कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए तक रहा हो;

(ख) ऐडवोकेट के रूप में किसी व्यक्ति को या किसी साझेदारी फर्म से कानूनी सेवाओं के रूप में निम्नलिखित को,-

(i) किसी ऐडवोकेट को या ऐडवोकेट्स के किसी साझेदारी फर्म को जो कानूनी सेवाएँ प्रदान करती है,-

(ii) कारोबारी संगठन से इतर किसी व्यक्ति को; या

(iii) किसी कारोबारी संगठन को जिसका कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए तक रहा हो; या

(ग) किसी व्यक्ति को जिसने किसी मध्यस्थता अधिकरण से किसी मध्यस्थता अधिकरण पर प्रतिनिधित्व किया हो;

7. नए रूप में विकसित औषधियों का, जिनमें टीके और हर्बल उपचार भी हैं, भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा नैदानिक परीक्षक करने के लिए अनुमोदित किसी नैदानिक अनुसंधान संगठन द्वारा मानव भागीदारों पर तकनीकी परीक्षण या विश्लेषण के रूप में दी गई सेवाएँ;

8. कला, संस्कृति या क्रीड़ा से संबंधित आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोरिंग के रूप में दी गई सेवाएँ;

9. सेवाकर से छूट प्राप्त किसी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से निम्न वैज्ञानिक संस्थान द्वारा या को प्रदत्त सेवाएँ-

(क) सहायक शैक्षणिक सेवाएँ; या

(ख) अचल सम्पत्ति को किरण पर देना;

10. किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को-

(क) किसी व्यष्टि द्वारा किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा संबलित किसी स्पोर्टिंग इवेंट में खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में;

(ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा दी गई सेवाएँ;

11. (क) किसी ऐसे राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघ या उसके सहबद्ध परिसंघों द्वारा, जहां मान लेने वाली हीमें या व्यष्टि किसी जिले, राज्य या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर-विश्वविद्यालय क्रीड़ा बोर्ड, भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, अखिल भारतीय मूक क्रीड़ा परिषद्, भारत प्रशासनिक समिति, विशेष ओलम्पिक भारत द्वारा;

(ग) केंद्रीय सिविल सेवा संस्कृति और क्रीड़ा बोर्ड;

(घ) भारत ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में; या

(ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान खड़ीक के अधीन;

आयोजित स्पोर्टिंग इवेंट के प्रत्यायोजन के रूप में दी गई सेवाएँ;

12. सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को नवीकरण या परिवर्तन के रूप में दी गई सेवाएँ—

- (क) प्रमुखतः गैर-ओद्योगिक, गैर-व्यापक उपयोग, गैर-व्याबसाय या गैर-प्रफेशन के लिए अभिप्रेत किसी सिविल संस्थाना या किसी अन्य मूल संकर्म;
- (ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अधीन विनिर्विष्ट किसी ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातत्त्वीय स्थल या सांस्कृतिक महत्व के अवशेष, पुरातत्त्वीय उत्खनन या पुरावस्तु;
- (ग) प्रमुखतः (i) किसी शैक्षिक, (ii) नैदानिक, या (iii) किसी कला या सांस्कृतिक स्थापन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत किसी संस्थाना;
- (घ) नहर, डैम या अन्य सिंचाई संकर्म;
- (ङ) (i) जल प्रदाय (ii) जल अभिक्रियान्वयन (iii) मलवहन अभिक्रियान्वयन या व्ययन के लिए पाइपलाइन, कंड्यूट या संयंत्र;
- (च) ऐसे आवासिक काम्पलेक्स के, जो प्रमुख रूप से स्वयं के उपयोग के लिए या उनके कर्मचारियों के उपयोग के लिए या उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड 44 के स्पष्टीकरण में विनिर्विष्ट अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं;

13. निर्माण, परिनिर्माण, कमिशनिंग, संस्थापन, समापन, फिलिंग आउट, मरम्मत, रख-रखाव, नवीकरण या परिवर्तन के रूप में दी गई सेवाएँ—

- (क) जनसाधारण के उपयोग के लिए सङ्केत परिवहन हेतु सङ्केत, पुल, सुरंग या ट्रॉमिनल के लिए;
- (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण भिशन अथवा राजीव आवास योजना के अंतर्गत एक सिविल संरचना मूल कार्य या किसी अन्य सेवानियत योजना के तहत की गयी कार्य;
- (ग) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत एकक द्वारा स्वामित्वाधीन भवन और मुख्यतः आम जनता द्वारा धार्मिक उपयोग के लिए हैं;
- (घ) कारखाना के भाग के रूप में अवस्थित के सिवाय प्रदूषण नियंत्रण या निःस्राव उपचार संयंत्र; या
- (ङ) क्रिया कर्म, संलेपन या मृत व्यक्ति के दाह-संस्कार के लिए आशयित कोई संरचना;

14. निम्नलिखित से संबंधित मूल कार्यों की स्वना, संनिर्माण, कमिशनिंग या संस्थापन के माध्यम से सेवाएँ—

- (क) विषानपत्तन, पत्तन या रेलवे, मोनोरेल या भेट्रो रेल सहित;
- (ख) अन्यथा रिहायशी काम्पलेक्स के भाग के रूप में एकल रिहायशी इकाई;
- (ग) भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा विरचित 'भागीदारी में पहुंच आवास स्कीम' के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी आवास परियोजना में 60 मीटर प्रति मकान के कारपेट क्षेत्र तक का कम लागत मकान;

(घ) ऐसे प्रयोजनों के लिए शीत भंडारण सहित कृषि उत्पाद के लिए फसल-पश्चात् भंडारण और अवसंरचना ; या

(ङ) एल्कोहोलिक पेय को छोड़कर खाद्य वस्तु के रूप में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण यूनिटों के लिए यांत्रिक खाद्य अनाज रखरखाव प्रणाली, मशीनरी या उपकरण ;

15. मूल साहित्य, नाटक, संगीत, कलाकृति या सिनेमोटोग्राफी फिल्म से संबंधित भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन आने वाले किसी प्रतिलिप्याधिकार के उपयोग या उपयोग का अस्थायी अंतरण या अनुज्ञात किया जाना ;

16. ब्रांड एंबेसडर के रूप में ऐसे कलाकार द्वारा दी गई सेवाओं को छोड़कर (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) थियेटर के लोक या शास्त्रीय कला के रूप में कृत्य करने वाले कलाकार की सेवाएं ;

17. स्वतंत्र पत्रकार, भारतीय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारतीय यूनाइटेड न्यूज द्वारा समाचारों को एकत्रित करने या उपलब्ध कराने के माध्यम से सेवाएं ;

18. आवासीय या रहने के प्रयोजनों के लिए किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब, कैंप स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, किसी आवास इकाई का घोषित टैरिफ प्रतिदिन 1000 रुपए से कम या समतुल्य है, के किराए के माध्यम से सेवाएं ;

19. किसी रेस्त्रां द्वारा खाद्य या पेय की सेवाओं के संबंध में, खानपान केंद्र या मैस, जिनके पास (i) वर्ष के दौरान किसी समय अस्थापन के किसी भाग में एयरकंडेशनिंग या सेंट्रल एयर हीटिंग की सुविधा से मिन्न स्थान और (ii) जिसमें अल्कोहोलिक पेय प्रदान करने की अनुज्ञाप्ति है, के संबंध में दी गई सेवाएं ;

20. निम्नलिखित मालों का भारत में रेल या यान द्वारा परिवहन के माध्यम से सेवाएं—

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 2710 और 2711 के अधीन आने वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद ;

(ख) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा दुर्घटना या अनिष्ट के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ;

(ग) स्क्षा या सेना उपकरण;

(घ) घरेलू प्रभाव;

(ङ) डाक मेल या मेल थैला;

(च) समाचार पत्र रजिस्ट्रार के धास रजिस्ट्रीकृत समाचास-पत्र या मैगजीन;

(छ) रेल उपकरण या सामग्री;

(ज) कृषि उत्पाद;

(झ) खाद्य सामग्री, जिसके अंतर्गत आटा, चाय, काफी, जैगरी, चीनी, दुध उत्पाद, नमक और खाद्य तेल है, एल्कोहोलिक पेय को छोड़कर ; या

(ञ) रासायनिक उर्वरक और खली ;

21. निम्नलिखित के परिवहन के माध्यम से किसी माल परिवहन अधिकरण द्वारा दी गई सेवाएं—

(झ) माल बहन में फल, सब्जी, अंडे, दुध, खाद्य अनाज या जूँड़ों ;

(झ) माल बहन में फल, सब्जी, अंडे, दुध, खाद्य अनाज या जूँड़ों ;

(ख) ऐसा माल, जहां एकल माल वहन में परेषण पर प्रभारित कुल रकम 1500 रुपए से अधिक नहीं है ; या

(ग) ऐसे माल, जहां माल वहन में एकल प्रेषिती के लिए सभी ऐसे माल के परिवहन के लिए प्रभारित कुल रकम 750 रुपए से अधिक नहीं है ;

22. आँडे पर देकर दी गई सेवाएं—

(क) 12 यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए राज्य परिवहन उपक्रम का कोई मोटरयान ; या

(ख) मालों के परिवहन के लिए कोई माल परिवहन अभिकरण ;

23. निम्नलिखित द्वारा बस्तुओं के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन —

(क) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य या पश्चिमी बंगाल स्थित बागडोगरा में अवास्थित विमानस्थलों में वायुयान द्वारा चढ़ाना या उतारना ; या

(ख) घर्यटन, संचालित यात्रा, चार्टर या भाड़ा को छोड़कर यात्रियों के परिवहन के लिए कोई संविदा वहन ;

24. ऐसी पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसी अस्तित्व को जगह पट्टे पर देने को छोड़कर जनसाधारण को यान पार्किंग के माध्यम से सेवाएं ;

25. निम्नलिखित के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को दी गई सेवाएं—

(क) जल आपूर्ति, जन-स्वास्थ्य, सफाई, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन या गन्दी बस्ती सुधार और उन्नयन के संबंध में किसी भी गतिविधि को चलाने या किसी भी प्रकार का कार्य जो नगरपालिका को साधारणता दीया गया हो;

(ख) जलयान या विमान की मरम्मत या रख-रखाव;

26. निम्नलिखित स्कीमों के अधीन प्रदान की गई साधारण बीमा कारबार सेवाएं—

(क) झोपड़ी बीमा स्कीम ;

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (पूर्व में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात) के अधीन पशु बीमा ;

(ग) जनजातियों के बीमे के लिए स्कीम ;

(घ) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी ;

(ङ) स्व.नियोजित महिलाओं के लिए अमूह व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी ;

(च) कृषि पंप सेट और असफल कुंआ बीमा ;

(छ) निर्यात प्रत्यय बीमा पर संगृहीत प्रीमियम ;

(ज) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम ;

(झ) जन आरोग्य बीमा पालिसी ;

(ञ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ;

(ट) बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम ;

(ठ) केंद्रीय सेक्टर पशु बीमा योजना ;

(ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ;

(ढ) राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना ; या

(ण) नारियल ताड़ बीमा योजना ;

27. किसी वित्तीय वर्ष में कुल पचास लाख रुपए के आवर्त तक किसी इंक्यूबेटी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की गई सेवाएँ, अर्थात् :-

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारबाहर आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हुआ था ; और

(ख) इंक्यूबेटी के रूप में करार करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यपगत नहीं हुई है ;

28. किसी अनिगमित निकाय या गैर-लाभ हस्ती रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई द्वारा अपने सदस्यों को प्रभारों के प्रतिपूर्ति या अंशदान के शेयर द्वारा--

(क) व्यापार संघ के रूप में ;

(ख) इकाई द्वारा किसी भी गतिविधि को चलाने जो छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए ; या

(ग) किसी आवासन सोसाइटी या किसी आवासिक काम्पलेक्स में उसके सदस्यों के सामान्य

उपयोग के लिए पर व्यक्ति माल या सेवाओं के स्रोत के लिए प्रति सदस्य पांच हजार रुपए की रकम तक ;

दी गई सेवा ;

29. निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अपनी-अपनी हैसियत में दी गई सेवाएँ--

(क) किसी सब-ब्रोकर या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्टाक ब्रोकर को ;

(ख) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु विनियम के सदस्यों को ;

(ग) किसी म्यूचुअल फंड अभिकर्ता द्वारा किसी म्यूचुअल फंड अस्ति प्रबंध कंपनी को;

(घ) किसी वितरक म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंध कंपनी को;

(ঙ) लाटरी टिकटों के विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा किसी वितरक या किसी विक्रय

अभिकर्ता को ;

(চ) सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन वाउचर के किसी विक्रय अभिकर्ता या वितरक द्वारा ; या

(छ) किसी कारबार फेसलिटेटर या कारबार संपर्की द्वारा किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैंककारी कंपनी या किसी बीमा कंपनी को ;

(ज) उप-ठेकेदार जो दूसरे ठेकेदार को सेवा मुक्त कार्य संविदा प्रदान कर रहे हैं;

30. निम्नलिखित के संबंध में जॉब कार्य के रूप में मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया करने के लिए—

(क) कृषि, मुद्रण या टेक्सटाइल प्रसंस्करण ;

(ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले कर्तित और पालिङ्ग किए हुए हीरे और रत्न ; या स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं के सादे और जड़े हुए आभूषण ;

(ग) ऐसा कोई माल, जिस पर मूल विनिर्माता द्वारा उचित शुल्क संदेय है ; या

(घ) किसी वित्तीय वर्ष में एक हजार पचास लाख रुपए की विनिर्दिष्ट संक्रियाओं की कुल करारधेय सेवा तक साइकिल या सिलाई मशीन के पूर्जों के विनिर्माण के अनुक्रम में इलैक्ट्रोपलेटिंग, जस्ता प्लेटिंग, एनो डाइजिंग, उष्म अभिक्रिया, पाउडर कोटिंग पैटिंग्स जिसमें स्प्रे पैटिंग या स्वतः काला होना भी है, की संक्रियाएं इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक हजार पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था ;

31. किसी आयोजक द्वारा भूम्ल से बाहर आयोजित किसी कारबार प्रदर्शनी की बाबत किसी व्यक्ति को दी गई सेवाएं ;

32. (क) विभागीय रूप से चलने वाले सार्वजनिक टेलीफोन ;

(ख) केवल लोकल काल के प्रवालन के लिए गारंटीकृत सार्वजनिक टेलीफोन ; या

(ग) विमानपत्तन और अस्पतालों में निःशुल्क टेलीफोन, जहां कोई बिल जारी नहीं किया जाता है ;

से टेलीफोन करने के रूप में दी गई सेवाएं ।

33. गौ-जातिय पशुओं के वध के रूप में दी गई सेवाएं ;

34. किसी अकरारधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी सेवा प्रदाता से—

(क) उद्योग, कारबार या वाणिज्य से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी व्यष्टि ; या

(ख) पूर्त क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक्ष के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई ;

(ग) गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित कोई व्यक्ति.

द्वारा प्राप्त सेवाएं ।

35. सार्वजनिक पुस्तकालय की इस प्रकार की उधार देने वाली पुस्तकों, प्रकाशन या किसी अन्य ज्ञान विकास तंत्र से अन्य सामग्री।

36. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन शासित व्यक्तियों को कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 (1948 के 34);

37. गोइंग कंसर्न के अंतरण, सम्पूर्ण या उसके एक भाग;

38. सार्वजनिक रूप में इस प्रकार की सुविधाओं के प्रावधान में बाथरूम, शौचालयों, या पेशाब घर;

39. सरकारी प्राधिकरण द्वारा दी गई सेवाएं जो नगरपालिका को संविधान के अनुच्छेद 243W के अंतर्गत साधारणत सेवा गया हो;

2. परिमाण— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिवक्ता” का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है ;

(ख) “समुचित शुल्क” से वह शुल्क अभिप्रेह है जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन विनिर्माण या उत्पादन पर संदेय है किंतु इसमें शुल्क की ‘शून्य’ दर या संपूर्णतः शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है ;

(ग) “माध्यस्थम् अधिकरण” का वही अर्थ है जो उसका माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 2 के खंड (घ) में है ;

(घ) “प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी” से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेह है जो आयुर्विज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त पद्धति की किसी परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत है और इसमें वह चिकित्सा व्यवसायी आता है, जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार आयुर्विज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त पद्धति में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित अर्हता है ;

(ङ) “प्राधिकृत व्यक्ति” ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे या तो किसी स्टाक ब्रोकर द्वारा, जिसमें व्यापार सदस्य सम्मिलित है या किसी वस्तु विनिमय के सदस्य द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है और जो किसी स्टाक एक्सचेंज या किसी वस्तु विनिमय के व्यापार प्लेटफार्म तक स्टाक ब्रोकर के अभिकर्ता या वस्तु विनिमय के सदस्यों के रूप में पहुंच प्रदान करता है ;

(च) “महायक शैक्षणिक सेवाएं” का अर्थ वह सेवा है, जो किसी कौशल, ज्ञान या पाठ्यक्रम के विकास या किसी अन्य जानकारी - विस्तार गतिविधि से संबंधित है, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो या संकाय के लिए या किसी अन्य सेवाओं के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएं सामान्यतः स्वयं चलाती हैं लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं जिसमें ऐसे संस्थानों में प्रवेश, परीक्षा के संचालन, सरकार द्वारा प्रायाजित किसी मध्याहन भोजन योजना में विद्यार्थियों को खिलाने से संबंधित या ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों, संकाय या स्टाफ के परिवहन से संबंधित सेवाएं शामिल हैं;

(छ) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ है जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है ;

(ज) “ब्रांड अंबेस्डर” का अर्थ वह व्यक्ति है, जो किसी माल, सेवा, संपत्ति या नीलामी योग्य दावे के संवर्धन या विपणन, समारोह या नाम के पृष्ठांकन में संलग्न है जिसमें व्यापारिक नाम, लोगों या किसी व्यक्ति का हाउस मार्क शामिल है;

(ज) “कारबार फेसलिटेटर या कारबार संपर्की” से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन किसी बैंककारी कंपनी या किसी बीमा कंपनी द्वारा कारबार फेसलिटेटर आदर्श या कारबार संपर्की आदर्श के अधीन नियुक्त किया गया मध्यवर्ती अभिप्रेत है ;

(ज) “क्लीनिकल स्थापन” से बीमारियों की नैदानिक या जांच सेवाओं के लिए किसी स्वतंत्र इकाई या किसी स्थापन की भाग के रूप में स्थापित स्थान या ऐसा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, आरोग्य निवास या संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसमें बीमारी, क्षति, विकृति, अतिविरुप्तता और गर्भावस्था के लिए नैदानिक या उपचार या देखरेख सुविधाओं की सेवाएं प्रस्थापित करता है ;

(ट) “पूर्ति क्रियाकलाप” से—

(i) (क) (i) गंभीर शारीरिक या मानसिक अशक्तता से अन्त्य बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों की देखरेख या परामर्श, (ii) एचआईवी या ऐडस से प्रभावित व्यक्तियों, या (iii) निर्भरता गठित करने वाले पदार्थ जैसे स्वापक औषधि या एल्कोहल के आदि व्यक्तियों ; या

(ख) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एचआईवी संक्रमण के निवारण के लिए लोक जागरूकता ;

के रूप में लोक स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत है ।

(ii) धर्म या आध्यात्मिकता के अभिवर्धन ;

(iii) (क) परित्यक्त, अनाथ या बेघर बालकों ;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से तंग और आघात व्यक्ति ;

(ग) कैदी ; या

(घ) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति ;

से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम या कुशलता विकास के अभिवर्धन ।

(iv) पर्यावरण, जिसमें जलसंभर, वन और अन्य जीव हैं, के परिष्कार ; या

(v) (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 में अठारह लाख 75 हजार रुपए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे क्रियाकलापों का कुल मूल्य के दौरान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं था ;

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में पच्चीस लाख रुपए के मूल्य तक जनसाधारण उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के अभिवर्धन के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी क्रियाकलापों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं था ;

(ठ) “वस्तु विनियम” से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2(ज) में परिभाषित है और उसकी धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त है ;

(ड) “संविदा वाहक” का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड 7 में है ;

(ढ) “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास की इकाई में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) प्रदान की गई सभी सुख-सुविधाओं जैसे फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या किन्हीं अन्य सुख-सुविधाओं के लिए प्रभार आते हैं किंतु इसमें ऐसी इकाई के लिए प्रकाशित प्रभारों पर दी गई कोई छूट नहीं है ;

(ण) “वितरक या विक्रय अभिकर्ता” का वही अर्थ है जो सर्वाभारत सरकार के गैर-मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और भारत के राजपत्र, ३ भाग २, खंड ३, उपखंड गशित लाटरी (विनियमन)

(५) में सा.का.नि. सं. 278(अ) तारीख १ अप्रैल, २०१० के नियम २ के खंड (ग) में है लाटरी आयोजक राज्य द्वारा प्राधिकृत वितरक या विक्रय अभिकर्ता आएगा ;

(त) “साधारण बीमा कारबार” का वही अर्थ उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1772 (1972 का 57) की ध. ३ के खड (छ) में है ;

(थ) “जनसाधारण उपयोगिता” से व्यापक रूप से ऐसा व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जो लोक या व्यक्तित्वहीन प्रकृति की कुछ सामान्य क्वालिटी द्वारा पर्याप्त रूप से परिभाषित है ;

(द) “माल वाहक” का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खड (14) में है ;

(ध) “सरकारी प्राधिकरण” का अर्थ कोई बोर्ड, या कोई प्राधिकरण या कोई अन्य निकाय है जिसपर इक्कीं या नियंत्रण के माध्यम से सरकार की 905 या अधिक भागीदारी हो और जिसे संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के माध्यम से उन कार्यों को करने के लिए स्थापित किया गया हो जो नगरपालिका को संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत सौंपा गया है;

(न) “स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं” से आयुर्विज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त पद्धति में बीमारी, क्षति, विकृति, अतिविरुप्ता और गर्भावस्था के लिए नैदानिक या उपचार या देखरेख के रूप में दी गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत रोगी को क्लीनिकल स्थान से और तक परिवहन के रूप में दी गई सेवाएं आती हैं किन्तु इसमें बाल रोपण या प्रसाधन या प्लास्टिक सर्जरी नहीं आती है सिवाय जब वह जन्मजात दोषों, विकासात्मक अतिरूपता, क्षति या आघात के कारण प्रभावित शरीर-रचना या शारीरिक कृत्यों को बनाए रखने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है,

(प) “इन्कुबेटी” से ऐसा उद्यमी अभिप्रेत है जो किसी प्रौद्योगिक कारबार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास बोर्ड (इन्डियन स्टीमिंग बोर्ड) द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा इन्कुबेटर (टी.बी.आई.) या विज्ञान या प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (एस.टी.ई.पी.) में अवस्थित है और जिसने उच्च-तकनीकी और नवीन उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए रखने को समर्थ बनाने हेतु कोई काश्यक है किया है ।

() “बीमा कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार कर रही है ;

(ब) “कानूनी सेवा” का अर्थ वह सेवा है, जो कानून की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में किसी भी तरीके से प्रदान की जाती है जिसमें किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में दी जाने वाली प्रतिनिधित्व सेवा शामिल है

(भ) “जीवन बीमा कारबार” का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 11 में है ;

(म) “मूल कार्य” का वही अर्थ है जो उसका सेवाकर (मूल्य का अवधारण) नियम, 2006 की धारा 2क में है

(य) “मूल विनिर्माता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति से अपने खाते में माल विनिर्मित या प्रसंस्कृत करता है ;

(यक) “मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय” से अभिप्रेत है (i) भारतीय ओलम्पिक संघ, (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण, (iii) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त कोई राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघ और उसके सहबद्ध परिसंघ, (iv) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीड़ा संवर्धन संगठन (v) अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक संघ या अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परिसंघ या (vi) ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल को विनियमित करता है ;

(यख) “धार्मिक स्थान” से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो प्रमुख रूप से किसी धर्म से संबंधित प्रार्थना, पूजा या आध्यात्मिकता करने के लिए अभिप्रेत है ;

(यग) “आवासिक काम्पलेक्स” से ऐसा भवन या ऐसे भवनों वाला कोई काम्पलेक्स अभिप्रेत है, जिसमें एक से अधिक एकल आवासिक इकाईयां हैं ;

(यघ) “ग्रामीण क्षेत्र” से भू-राजस्व अभिलेखों में यथापरिभाषित किसी ग्राम में राज्यविष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें किसी नगरपालिका, नगर निगम, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधीन क्षेत्र ; या ऐसा क्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपवर्जित है ;

(यड) “एकल आवासीय इकाई” का अर्थ स्वतःपूर्ण कोई आवासीय इकाई है जिसकी अभिकल्पना पूर्ण या आंशिक रूप से किसी एक परिवार के आवास के लिए की गयी हो

(यच) “विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन” से केंद्रीय सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्नुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में घोषित कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम के अनुसूची के उपर्यंथ लागू होते हैं ;

(यछ) “राज्य परिवहन उपक्रम” का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 2988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में है ;

(यज) “सब-ब्रोकर” का वही अर्थ है जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियम, 1992 के खंड 2 के उपखंड (छग) में है ;

(यझ) “व्यापार संघ” का वही अर्थ है जो उसका व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई 2012 को ही प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 25/2012-Service Tax

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification number 12/2012- Service Tax, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 210 (E), dated the 17th March, 2012, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following taxable services from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act, namely:-

1. Services provided to the United Nations or a specified international organization;
2. Health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics;
3. Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds;
4. Services by an entity registered under section 12AA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) by way of charitable activities;
5. Services by a person by way of-

- (a) renting of precincts of a religious place meant for general public; or
- (b) conduct of any religious ceremony;

6. Services provided by-

- (a) an arbitral tribunal to -
- (i) any person other than a business entity; or

(ii) a business entity with a turnover up to rupees ten lakh in the preceding financial year;

(b) an individual as an advocate or a partnership firm of advocates by way of legal services to,-

(i) an advocate or partnership firm of advocates providing legal services ;

(ii) any person other than a business entity; or

(iii) a business entity with a turnover up to rupees ten lakh in the preceding financial year; or

(c) a person represented on an arbitral tribunal to an arbitral tribunal;

7. Services by way of technical testing or analysis of newly developed drugs, including vaccines and herbal remedies, on human participants by a clinical research organisation approved to conduct clinical trials by the Drug Controller General of India;

8. Services by way of training or coaching in recreational activities relating to arts, culture or sports;

9. Services provided to or by an educational institution in respect of education exempted from service tax, by way of,-

(a) auxiliary educational services; or
 (b) renting of immovable property;

10. Services provided to a recognised sports body by-

(a) an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organized by a recognized sports body;

(b) another recognised sports body;

11. Services by way of sponsorship of sporting events organised,-

(a) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, state or zone;

(b) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;

(c) by Central Civil Services Cultural and Sports Board;

(d) as part of national games, by Indian Olympic Association; or

(e) under Panchayat Yuva Kreedha Aur Khel Abhiyaan (PYKKA) Scheme;

12. Services provided to the Government, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of -

(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;

(b) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(c) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment;

(d) canal, dam or other irrigation works;

(e) pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal; or

(f) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in the *Explanation 1* to clause 44 of section 65 B of the said Act;

3. Services provided by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,-

(a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public;

(b) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv Awaas Yojana;

- (c) a building owned by an entity registered under section 12 AA of the Income tax Act, 1961(43 of 1961) and meant predominantly for religious use by general public;
- (d) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or
a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased;

14. Services by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,-

- (a) an airport, port or railways, including monorail or metro;
- (b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex;
- (c) low- cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India;
- (d) post- harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storages for such purposes; or
- (e) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages;

15. Temporary transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clauses (a) or (b) of sub-section (1) of section 13 of the Indian Copyright Act, 1957 (14 of 1957), relating to original literary, dramatic, musical, artistic works or cinematograph films;

16. Services by a performing artist in folk or classical art forms of (i) music, or (ii) dance, or (iii) theatre, excluding services provided by such artist as a brand ambassador;

17. Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India;

18. Services by way of renting of a hotel, inn, guest house, club, campsite or other commercial places meant for residential or lodging purposes, having declared tariff of a unit of accommodation below rupees one thousand per day or equivalent;

19. Services provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess, other than those having (i) the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year, and (ii) a licence to serve alcoholic beverages;

20. Services by way of transportation by rail or a vessel from one place in India to another of the following goods -

(a) petroleum and petroleum products falling under Chapter heading 2710 and 2711 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(b) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap;

(c) defence or military equipments;

(d) postal mail or mail bags;

(e) household effects;

(f) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers;

(g) railway equipments or materials;

(h) agricultural produce;

(i) foodstuff including flours, tea, coffee, jaggery, sugar, milk products, salt and edible oil, excluding alcoholic beverages; or

(j) chemical fertilizer and oilcakes;

21. Services provided by a goods transport agency by way of transportation of -

(a) fruits, vegetables, eggs, milk, food grains or pulses in a goods carriage;

(b) goods where gross amount charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single goods carriage does not exceed one thousand five hundred rupees; or

(c) goods, where gross amount charged for transportation of all such goods for a single consignee in the goods carriage does not exceed rupees seven hundred fifty;

22. Services by way of giving on hire -

- (a) to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than twelve passengers; or
- (b) to a goods transport agency, a means of transportation of goods;

23. Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by -

- (a) air, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;
- (b) a contract carriage for the transportation of passengers, excluding tourism, conducted tour, charter or hire; or
- (c) ropeway, cable car or aerial tramway;

24. Services by way of vehicle parking to general public excluding leasing of space to an entity for providing such parking facility;

25. Services provided to Government, a local authority or a governmental authority by way of -

- (a) carrying out any activity in relation to any function ordinarily entrusted to a municipality in relation to water supply, public health, sanitation conservancy, solid waste management or slum improvement and upgradation; or
- (b) repair or maintenance of a vessel or an aircraft;

26. Services of general insurance business provided under following schemes -

- (a) Hut Insurance Scheme;
- (b) Cattle Insurance under Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojna (earlier known as Integrated Rural Development Programme);

- (c) Scheme for Insurance of Tribals;
- (d) Janata Personal Accident Policy and Gramin Accident Policy;
- (e) Group Personal Accident Policy for Self-Employed Women;
- (f) Agricultural Pumpset and Failed Well Insurance;
- (g) premia collected on export credit insurance;
- (h) Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme, approved by the Government of India and implemented by the Ministry of Agriculture;
- (i) Jan Arogya Bima Policy;
- (j) National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana);
- (k) Pilot Scheme on Seed Crop Insurance;
- (l) Central Sector Scheme on Cattle Insurance;
- (m) Universal Health Insurance Scheme;
- (n) Rashtriya Swasthya Bima Yojana; or
- (o) Coconut Palm Insurance Scheme;

27. Services provided by an incubatee up to a total turnover of fifty lakh rupees in a financial year subject to the following conditions, namely:-

- (a) the total turnover had not exceeded fifty lakh rupees during the preceding financial year; and

- (b) a period of three years has not been elapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee;

28. Service by an unincorporated body or a non- profit entity registered under any law for the time being in force, to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution -

- (a) as a trade union;
- (b) for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of service tax; or

- (c) up to an amount of five thousand rupees per month per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or a residential complex;

29. Services by the following persons in respective capacities -

- (a) sub-broker or an authorised person to a stock broker;
- (b) authorised person to a member of a commodity exchange;
- (c) mutual fund agent to a mutual fund or asset management company;
- (d) distributor to a mutual fund or asset management company;
- (e) selling or marketing agent of lottery tickets to a distributor or a selling agent;
- (f) selling agent or a distributor of SIM cards or recharge coupon vouchers;
- (g) business facilitator or a business correspondent to a banking company or an insurance company, in a rural area; or
- (h) sub-contractor providing services by way of works contract to another contractor providing works contract services which are exempt;

30. Carrying out an intermediate production process as job work in relation to -

- (a) agriculture, printing or textile processing;
- (b) cut and polished diamonds and gemstones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);
- (c) any goods on which appropriate duty is payable by the principal manufacturer; or
- (d) processes of electroplating, zinc plating, anodizing, heat treatment, powder coating, painting including spray painting or auto black, during the course of manufacture of parts of cycles or sewing machines upto an aggregate value of taxable service of the specified processes of one hundred and fifty lakh rupees in a financial year subject to the condition that such aggregate value had not exceeded one hundred and fifty lakh rupees during the preceding financial year;

31. Services by an organiser to any person in respect of a business exhibition held outside India;

32. Services by way of making telephone calls from -

- (a) departmentally run public telephone;
- (b) guaranteed public telephone operating only for local calls; or

(c) free telephone at airport and hospital where no bills are being issued;

33. Services by way of slaughtering of bovine animals;

34. Services received from a provider of service located in a non-taxable territory by—

(a) Government, a local authority, a governmental authority or an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession;

(b) an entity registered under section 12AA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) for the purposes of providing charitable activities; or

(c) a person located in a non-taxable territory;

35. Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge-enhancing content or material;

36. Services by Employees' State Insurance Corporation to persons governed under the Employees' Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

37. Services by way of transfer of a going concern, as a whole or an independent part thereof;

38. Services by way of public conveniences such as provision of facilities of bathroom, washrooms, lavatories, urinal or toilets;

39. Services by a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 243 W of the Constitution.

2. Definitions. - For the purpose of this notification, unless the context otherwise requires, —

(a) "Advocate" has the meaning assigned to it in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(b) "appropriate duty" means duty payable on manufacture or production under a Central Act or a State Act, but shall not include 'Nil' rate of duty or duty wholly exempt;

(c) "arbitral tribunal" has the meaning assigned to it in clause (d) of section 2 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);

(d) "authorised medical practitioner" means a medical practitioner registered with any of the councils of the recognised system of medicines established or recognized by law in India and includes a medical professional having the requisite qualification to practice in any recognised system of medicines in India as per any law for the time being in force;

(e) "authorised person" means any person who is appointed as such either by a stock broker (including trading member) or by a member of a commodity exchange and who provides access to trading platform of a stock exchange or a commodity exchange as an agent of such stock broker or member of a commodity exchange;

(f) "auxiliary educational services" means any services relating to imparting any skill, knowledge, education or development of course content or any other knowledge – enhancement activity, whether for the students or the faculty, or any other services which educational institutions ordinarily carry out themselves but may obtain as outsourced services from any other person, including services relating to admission to such institution, conduct of examination, catering for the students under any mid-day meals scheme sponsored by Government, or transportation of students, faculty or staff of such institution;

(g) "banking company" has the meaning assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(h) "brand ambassador" means a person engaged for promotion or marketing of a brand of goods, service, property or actionable claim, event or endorsement of name, including a trade name, logo or house mark of any person;

(i) "business facilitator or business correspondent" means an intermediary appointed under the business facilitator model or the business correspondent model by a banking company or an insurance company under the guidelines issued by Reserve Bank of India;

(j) "clinical establishment" means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent

entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(k) "charitable activities" means activities relating to -

(i) public health by way of -

(a) care or counseling of (i) terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, (ii) persons afflicted with HIV or AIDS, or (iii) persons addicted to a dependence-forming substance such as narcotics drugs or alcohol; or

(b) public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection;

(ii) advancement of religion or spirituality;

(iii) advancement of educational programmes or skill development relating to,-

(a) abandoned, orphaned or homeless children;

(b) physically or mentally abused and traumatized persons;

(c) prisoners; or

(d) persons over the age of 65 years residing in a rural area;

(iv) preservation of environment including watershed, forests and wildlife; or

(v) advancement of any other object of general public utility up to a value of,-

(a) eighteen lakh and seventy five thousand rupees for the year 2012-13 subject to the condition that total value of such activities had not exceeded twenty five lakhs rupees during 2011-12;

(b) twenty five lakh rupees in any other financial year subject to the condition that total value of such activities had not exceeded twenty five lakhs rupees during the preceding financial year;

(l) "commodity exchange" means an association as defined in section 2 (j) and recognized under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952);

(m) "contract carriage" has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(n) "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air-conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit;

(o) "distributor or selling agent" has the meaning assigned to them in clause (c) of the rule 2 of the Lottery (Regulation) Rules, 2010 notified by the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 278(E), dated the 1st April, 2010 and shall include distributor or selling agent authorised by the lottery- organising State;

(p) "general insurance business" has the meaning assigned to it in clause (g) of section 3 of General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);

(q) "general public" means the body of people at large sufficiently defined by some common quality of public or impersonal nature;

(r) "goods carriage" has the meaning assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(s) "governmental authority" means a board, or an authority or any other body established with 90% or more participation by way of equity or control by Government and set up by an Act of the Parliament or a State Legislature to carry out any function entrusted to a municipality under article 243W of the Constitution;

(t) "health care services" means any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(u) "incubatee" means an entrepreneur located within the premises of a Technology Business Incubator (TBI) or Science and Technology Entrepreneurship Park (STEP)

recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India and who has entered into an agreement with the TBI or the STEP to enable himself to develop and produce hi-tech and innovative products;

(v) "insurance company" means a company carrying on life insurance business or general insurance business;

(w) "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority;

(x) "life insurance business" has the meaning assigned to it in clause (11) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(y) "original works" means has the meaning assigned to it in Rule 2A of the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006;

(z) "principal manufacturer" means any person who gets goods manufactured or processed on his account from another person;

(za) "recognized sports body" means - (i) the Indian Olympic Association, (ii) Sports Authority of India, (iii) a national sports federation recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government, and its affiliate federations, (iv) national sports promotion organisations recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government, (v) the International Olympic Association or a federation recognised by the International Olympic Association or (vi) a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating a sport in India;

(zb) "religious place" means a place which is primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion, meditation, or spirituality;

(zc) "residential complex" means any complex comprising of a building or buildings, having more than one single residential unit;

(zd) "rural area" means the area comprised in a village as defined in land revenue records, excluding—

the area under any municipal committee, municipal corporation, town area committee, cantonment board or notified area committee; or any area that may be notified as an urban area by the Central Government or a State Government;

(ze) "single residential unit" means a self-contained residential unit which is designed for use, wholly or principally, for residential purposes for one family;

(zf) "specified international organization" means an international organization declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply;

(zg) "state transport undertaking" has the meaning assigned to it in clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(zh) "sub-broker" has the meaning assigned to it in sub-clause (gc) of clause 2 of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992;

(zi) "trade union" has the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926).

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 26/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 468(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) (तत्पश्चात उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, लोकहित में इसकी अपेक्षा से संतुष्ट होने पर, एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण की कर योग्य सेवाओं को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत लगने वाले सेवाकर से उस सीमा तक छूट प्रदान करती है जो उपर्युक्त तालिका के कालम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के समकक्ष अपर्युक्त तालिका के कालम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संभव शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्—

तालिका

क्रम सं०	कर योग्य सेवा का विवरण	प्रतिशतला	शर्ते
1	2	3	4
1	उपकरण लीजिंग तथा हॉयर परचेज सहित वित्तीय लीजिंग से संबंधित सेवाएं	10	शून्य
2	रेलवे द्वारा माल दुलार्डि	30	शून्य
3	रेलवे द्वारा यात्रियों को उनके साथ चलने वाले सामान के साथ अथवा उसके बिना लाने ले जाने,	30	शून्य

4	(होटल, कन्वेशन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना अथवा अन्य कोई स्थान सहित किसी परिसर में खाद्यन की आपूर्ति अथवा मानवीय उपभोग की अन्य किसी वस्तु की आपूर्ति संबंधी एकजुट सेवा, विशेषकर किसी समारोह) के आयोजन हेतु जिसमें ऐसे परिसर को किराए पर दिया जाना शामिल हो ।	70	(i) केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत वर्गीकृत किसी मद जिसका कर योग्य सेवा प्रदान करने में उपयोग किया गया है, पर सेनेट क्रेडिट, सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है ।
5	हवाई जहाज द्वारा उनके साथ चलने वाले सामान के साथ अथवा उसके बिना यात्रियों का लाने- ले जाने	40	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है ।
6	आवासीय अथवा लोजिंग के उद्देश्य से होटल, सराय, गेस्ट हाऊस, क्लब, कैम्प साइट अथवा व्यावसायिक स्थानों को किराए पर देना	60	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है ।
7	मदों की आवाजावी के संबंध में माल ढुलाई अभिकरणों की सेवाएं ।	25	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है ।
8	चिट के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं	70	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली,

			2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है।
9	यात्रियों को लाने ले जाने हेतु डिजाइन किए गए मोटर वाहनों को किराए पर देना	40	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है।
10	वेसल (नौका) में सामान ढुलाई	50	कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है।
11	किसी टूर आपरेटर द्वारा निम्न के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं (i) पैकेज टूर	25	(i) कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। (ii) इस उद्देश्य हेतु जारी बिल ऐसे टूर हेतु लिए गए प्रभार को भी दर्शाते हैं।
	(ii) कोई टूर, यदि टूर सचालक केवल टूर के संबंध में किसी व्यक्ति हेतु आवासीय स्थान का प्रबंध करने संबंधी सेवा मुहैया कराता है	10	(i) कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। (ii) इनवाइस बिल अथवा चालान जो जारी किया गया

			है ऐसे आवासीय स्थल हेतु लिए गए प्रभार को दर्शाता है। (iii) छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें दूर आपरेटर द्वारा दूर के संबंध में जारी इनवाइस, बिल अथवा चालान में केवल किसी व्यक्ति के लिए आवासीय स्थल के प्रबंध करने हेतु लिया गया प्रभार ही शामिल है तथा उसमें ऐसे आवास स्थल हेतु लागत को शामिल नहीं किया गया है।
12	किसी कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल ढांचे अथवा उसके किसी भाग का निर्माण जिसे किसी खरीदार को पूर्णतया अथवा अंशतः बेचने की मंशा से निर्मित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्प्लीशन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद मिलने वाली राशि को छोड़कर	25	(i) कर योग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयोग किए गए इनपुट तथा कैपिटल गुड्स पर सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लिया गया है। (ii) सेवा प्राप्त करने वाले से जमीन का मूल्य किसी भी रूप में अलग से वसूल नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण:

(क) क्रम सं0 1 में छूट के उद्देश्य से -

- ली गई कुल राशि वह राशि होगी जिसमें ब्याज अर्थात् लीज राशि के भुगतान हेतु दी गई किस्तें तथा ऐसी किस्तों में निहित मूलधन राशि के बीच का अंतर;
- छूट उस राशि पर लागू नहीं होगी जो सेवा प्रदाता द्वारा ब्याज के रूप में ली गई राशि हो, जैसे लीज प्रबंध शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, डाक्युमेंटेशन चार्ज तथा प्रशासनिक शुल्क।

(ख) क्रम सं0 4 में छूट के उद्देश्य से -

यह राशि कुल प्रभार के रूप में लिया गया कुल योग होगी तथा किसी भी प्रकार के खाने-पीने अथवा किसी भी मानवीय उपभोग हेतु अन्य कोई वस्तु अथवा पेय (चाहे नशे वाला हो अथवा नहीं हो), चाहे उसी संविदा अथवा किसी अन्य संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की गई हो, के संबंध में ली जाने वाली मर्दों अथवा सेवाओं का समुचित मूल्य में निम्न कटौती करके-

i. ऐसी मर्दों अथवा सेवाओं हेतु लिए जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो; तथा

ii. मूल्यवर्धित कर अथवा बिक्री कर, यदि कोई हो, जो लिया गया हो:

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि इस प्रकार दी जाने वाली सेवाओं अथवा मर्दों का समुचित मूल्य आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित होगा।

(ग) क्रम सं0 12 में छूट के उद्देश्य से -

यह राशि कुल प्रभार के रूप में लिया गया कुल योग जो संविदाकारी तथा आपूर्ति किए जाने वाले सामान अथवा मर्दों के समुचित मूल्य के रूप में लिया गया हो, चाहे उसी संविदा अथवा किसी अन्य संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की गई हो, के संबंध में ली जाने वाली मर्दों अथवा सेवाओं का समुचित मूल्य में निम्न कटौती करके-

i. ऐसी मर्दों अथवा सेवाओं हेतु लिए जाने वाला प्रभार, यदि कोई हो; तथा

ii. मूल्यवर्धित कर अथवा बिक्री कर, यदि कोई हो, जो लिया गया हो:

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि इस प्रकार दी जाने वाली सेवाओं अथवा मर्दों का समुचित मूल्य आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित होगा।

2. इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, जब तक कि परिप्रेक्ष्य में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क. "चिट" एक ऐसा लेनदेन है जिसे चिट, चिटफंड, चिटी, कुरी अथवा अन्यथा किसी ओर नाम द्वारा अथवा जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या के व्यक्तियों से एक प्रकार का समझौता करता है कि उनमें से प्रत्येक एक निश्चित राशि सब्सक्राइब करेगा (अथवा गेहूं की एक निश्चित मात्रा) जिसे वे एक निश्चित अवधि तक आवधिक आधार पर किस्तों के रूप में देंगे तथा ऐसा प्रत्येक सब्सक्राइबर, उनकी बारी आने पर, जैसाकि नीलामी अथवा पासा फेंकने अथवा किसी संविदा अथवा ऐसी कोई पद्धति जो चिट समझौते में विनिर्दिष्ट की गई हो, किसी इनामी राशि का हकदार होगा।

ख. "पैकेज टूर" एक ऐसा टूर है जिसमें आना-जाना रुकने, खाने, टूरिस्ट गाइड, ऐतिहासिक स्थलों पर प्रविष्टि तथा अन्य ऐसी ही सेवाएं किसी टूर के संबंध में टूर करने वाले व्यक्तियों को टूर आपरेटर द्वारा एक पैकेज टूर के अंश के रूप में मुहैया कराई जाती हैं।

ग. "टूर आपरेटर" टूर आपरेटर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टूर की योजना, समय-सारणी, टूर व्यवस्था (जिसमें रहने अथवा साइट अमण अथवा अन्य ऐसी सेवाएं की व्यवस्था शामिल हो सकती है) किसी यातायात माध्यम द्वारा तथा इसमें टूर आपरेट करने के व्यवसाय से जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल होता है,

3. यह अधिसूचना एक नुलाई, 2012 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 26/2012-Service Tax

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of notification number 13/2012- Service Tax, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 211 (E), dated the 17th March, 2012, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of the description specified in column (2) of the Table below, from so much of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act, as is in excess of the service tax calculated on a value which is equivalent to a percentage specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, of the amount charged by such service provider for providing the said taxable service, unless specified otherwise, subject to the relevant conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely;

TABLE

Sl. No.	Description of taxable service	Percent-age	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Services in relation to financial leasing including hire purchase	10	Nil.
2	Transport of goods by rail	30	Nil.
3	Transport of passengers, with or without accompanied belongings by rail	30	Nil.

4	Bundled service by way of supply of food or any other article of human consumption or any drink, in a premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organizing a function) together with renting of such premises	70	(i) CENVAT credit on any goods classifiable under Chapters 1 to 22 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.
5	Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings	40	CENVAT credit on inputs and capital goods, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.
6	Renting of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes.	60	Same as above.
7	Services of goods transport agency in relation to transportation of goods.	25	CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.
8	Services provided in relation to chit	70	Same as above.
9	Renting of any motor vehicle designed to carry passengers	40	Same as above.
10	Transport of goods in a vessel	50	Same as above.
11	Services by a tour operator in relation to,— (i) a package tour	25	(i) CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004. (ii) The bill issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges for such a tour.

	(ii) a tour, if the tour operator is providing services solely of arranging or booking accommodation for any person in relation to a tour	10	(i) CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004. (ii) The invoice, bill or challan issued indicates that it is towards the charges for such accommodation. (iii) This exemption shall not apply in such cases where the invoice, bill or challan issued by the tour operator, in relation to a tour, only includes the service charges for arranging or booking accommodation for any person and does not include the cost of such accommodation.
	(iii) any services other than specified at (i) and (ii) above.	40	(i) CENVAT credit on inputs, capital goods and input services, used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004. (ii) The bill issued indicates that the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour.
12.	Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, intended for a sale to a buyer, wholly or partly except where entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority	25	(i) CENVAT credit on inputs used for providing the taxable service has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004. (ii) The value of land is included in the amount charged from the service receiver.

Explanation. —

A. For the purposes of exemption at Serial number 1 -

(i) The amount charged shall be an amount, forming or representing as interest, i.e. the difference between the installments paid towards repayment of the lease amount and the principal amount contained in such installments;

(ii) the exemption shall not apply to an amount, other than an amount forming or representing as interest, charged by the service provider such as lease management fee, processing fee, documentation charges and administrative fee, which shall be added to the amount calculated in terms of (i) above.

B. For the purposes of exemption at Serial number 4 -

The amount charged shall be the sum total of the gross amount charged and the fair market value of all goods and services supplied in or in relation to the supply of food or any other article of human consumption or any drink (whether or not intoxicating) and whether or not supplied under the same contract or any other contract, after deducting-

(i) the amount charged for such goods or services supplied to the service provider, if any; and

(ii) the value added tax or sales tax, if any, levied thereon:

Provided that the fair market value of goods and services so supplied may be determined in accordance with the generally accepted accounting principles.

C. For the purposes of exemption at Serial number 12 -

The amount charged shall be the sum total of the amount charged for the service including the fair market value of all goods and services supplied by the recipient(s) in or in relation to the service, whether or not supplied under the same contract or any other contract, after deducting-

(i) the amount charged for such goods or services supplied to the service provider, if any; and

(ii) the value added tax or sales tax, if any, levied thereon:

Provided that the fair market value of goods and services so supplied may be determined in accordance with the generally accepted accounting principles.

2. For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires,-

a. "chit" means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuri, or by whatever name by or under which a person enters into an agreement with a specified number

of persons that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical installments over a definite period and that each subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to a prize amount,

- b. "package tour" means a tour wherein transportation, accommodation for stay, food, tourist guide, entry to monuments and other similar services in relation to tour are provided by the tour operator as part of the package tour to the person undertaking the tour,
- c. "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours,

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 27/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 469(आ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान के शासकीय प्रयोग के लिए या उसमें तैनात राजनयिक अभिकर्ताओं या वृत्ति कौसलीय अधिकारियों के व्यक्तिगत प्रयोग या उनके कुटुंब के सदस्यों के प्रयोग के लिए प्रदान की गई उक्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) यह कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान या उसमें तैनात राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी व्यतिकरिता के सिद्धांत के आधीर पर इस प्रकार सेवा कर से छूट के हकदार हैं जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में अनुबंधित है ;
- (ii) यह कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान में तैनात राजनयिक अभिकर्ताओं या वृत्ति कौसलीय अधिकारियों के मामले में विदेश मंत्रालय का प्रोटोकाल प्रभाग या संबंधित राज्य का प्रोटोकाल विभाग ऐसे प्रत्येक राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी को ऐसा पहचान कार्ड जारी करता है, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक है और जिसमें ऐसे राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी का फोटोग्राफ और नाम तथा भारत में ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान का नाम है, जहां वह तैनात है ।

(iii) यह कि विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय स्थान का प्रमुख या ऐसे मिशन या स्थान का उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कराधेय सेवा के प्रदाता को ऐसे प्रमाण-पत्र की उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति देगा जिसके साथ उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा मूल वचनबंध होगा जिस पर वित्तीय वर्ष से आरंभ होने वाला चालू क्रम संख्यांक होगा और यह कथन होगा कि प्राप्त की गई सेवाएं उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय स्थान के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उसके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए है और उसमें उसे जारी किए गए पहचान कार्ड में दिए गए विशिष्ट पहचान संख्यांक का उल्लेख होगा और यह कथन होगा कि प्राप्त की गई सेवाएं उक्त राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी के उपयोग के लिए या उसके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए है ;

(iv) यह कि विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान का प्रमुख या प्राधिकृत व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए वचनबंधों का लेखा रखेगा और लेखे में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,—

(क) वचनबंध का क्रम संख्यांक और जारी करने की तारीख ;

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान में तैनात राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारयों के व्यक्तिगत उपयोग के मामले में उस राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी का, जिसके पक्ष में वचनबंध जारी किया गया है, नाम, पदनाम और विशिष्ट पहचान संख्यांक ;

(ग) कराधेय सेवा के प्रदाता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ; और

(घ) कराधेय सेवा का ब्यौरा और बीजक संख्यांक ।

(v) बीजक या, यथास्थिति, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 4क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जारी किए गए बिल या चालान में उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित जानकारी के अतिरिक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान के उक्त प्रमुख द्वारा दिए गए वचनबंध का क्रम संख्यांक और तारीख या भारत में ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान में तैनात राजनयिक अभिकर्ताओं या वृत्ति कौसलीय अधिकारियों के मामले में, कौसलीय-स्थान में तैनात राजनयिक अभिकर्ताओं या वृत्ति कौसलीय अधिकारी का विशिष्ट पहचान संख्यांक अंतर्विष्ट होगा ; और

(vi) यह कि कराधेय सेवा का प्रदाता सत्यापन के प्रयोजनों के लिए जारी किए गए बीजक की द्वितीय प्रति सहित शर्त सं. (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रतिधारित करेगा ।

2. यदि विदेश मंत्रालय का प्रोटोकाल प्रभाग, यथास्थिति, भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान को प्रमाण जारी करने या किसी राजनयिक अभिकर्ता या वृत्ति कौसलीय अधिकारी को पहचान कार्ड जारी करने के पश्चात् किसी एक या दोनों को बाद में प्रत्याहृत करने का विनिश्चय करता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे प्रमाण-पत्र या पहचान कार्ड के प्रत्याहरण की संसूचना विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान को देगा ।

3. भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौसलीय-स्थान को शासकीय प्रयोजन के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए संपूर्ण सेवा कर से दी गई छूट, यथास्थिति, ऐसे प्रमाण-पत्र या पहचान कार्ड के प्रत्याहरण की तारीख से उपलब्ध नहीं होगी ।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिविजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 27/2012-Service Tax

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services provided by any person, for the official use of a foreign diplomatic mission or consular post in India, or for personal use or for the use of the family members of diplomatic agents or career consular officers posted therein from whole of the service tax leviable under section 66B of the said Act, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to exemption from service tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;
- (ii) that in case of diplomatic agents or career consular officers posted in the foreign diplomatic mission or consular post in India, the Protocol Division of the Ministry of External Affairs or the Protocol Department of the State concerned issues to each of such diplomatic agent or career consular officer an identification card bearing unique identification number and containing a photograph and name of such diplomatic agent or career consular officer and the name of the foreign diplomatic mission or consular post in India, where he is posted;
- (iii) that the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish to the provider of taxable service, a copy of such certificate duly authenticated by him or the authorised person, alongwith an undertaking in original, signed by him or the authorised person, bearing running serial number commencing from a financial year and stating that the services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family mentioning the unique identification number as appearing in the identification card issued to them and stating that the services received are for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

(iv) that the head of the foreign diplomatic mission or consular post or the authorized person shall maintain an account of the undertakings issued during a financial year and the account shall contain:-

- (a) the serial number and date of issue of the undertakings;
- (b) in case of personal use of diplomatic agents or career consular officers posted in the foreign diplomatic mission or consular post in India, the name, designation and unique identification number of the diplomatic agent or career consular officer in favour of whom the undertaking has been issued;
- (c) the name and the registration number of the provider of taxable service; and
- (d) the description of taxable service and invoice number.

(v) The invoice or bill, or as the case may be, the challan issued under the provisions contained in rule 4A of the Service Tax Rules, 1994, shall, in addition to the information required to be furnished under the said rule, contain the serial number and the date of the undertaking furnished by the said head of foreign diplomatic mission or consular post or in case of diplomatic agents or career consular officers posted in such foreign diplomatic mission or consular post in India, the unique identification number of the diplomatic agent or career consular officer, as the case may be; and

(vi) that the provider of taxable service shall retain the documents referred to in the conditions (i), (ii) and (iii) alongwith a duplicate copy of the invoice issued, for the purposes of verification.

2. In case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India or as the case may be, the identification card issued to a diplomatic agent or career consular officer, decides to withdraw any one or both of them subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate or identification card, as the case may be, to the foreign diplomatic mission or consular post.

3. The exemption from the whole of the service tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate or identification card, as the case may be.

4. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 28/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 470(अ).—वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ग की उपधारा (1) और धारा 9 की उपधारा (2) के उपवाक्य (जजज) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 9/2005 सेवाकर, दिनांक 3 मार्च, 2005, जिसे सा.का.नि. 151 (अ), दिनांक 3 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (I) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 11/2006- सेवाकर, दिनांक 19 मई, 2006, जिसे सा.का.नि. 227 (अ), दिनांक 19 मई, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (I) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार सेवा प्रावधानों के स्थान को निर्धारण के प्रयोजन से निम्नलिखित नियम बनती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों के “प्लेस आफ प्रोविजन आफ सर्विस रूल्स, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये 1 जुलाई, 2012 से प्रवर्तन में आयेंगे।

2. परिभाषायें :-

इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

- (क) “अधिनियम” का अभिप्राय वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) से है;
- (ख) “खाता” का अभिप्राय ऐसे खाता से है जिसमें जमाकर्ता का हित निहित हो और इसमें अनिवार्य विदेशी खाता और अनिवासी साधारण खाता भी शामिल है;
- (ग) “बैंकिंग कम्पनी” से अभिप्राय वह है जो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 के उपवाक्य (क) में दिया गया है;
- (घ) “सतत यात्रा” से अभिप्राय ऐसी यात्रा से है जिसके लिए एक ही समय में एक या एक से अधिक टिकट या बीजक जारी किये जाते हैं, ऐसा या तो एक सेवा प्रदाता द्वारा या एक से अधिक सेवा प्रदाता की ओर से काम करने वाले एक एजेंट द्वारा किया जा सकता है और जिसमें ऐसी किसी यात्रा के बीच कोई स्टाप ओवर नहीं होता है जिसके लिए एक या एक से अधिक अलग टिकट या बीजक जारी करना होता है;
- (ड) “वित्तीय संस्थान” से अभिप्राय वह है जो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 अ के उपवाक्य (ग) में दिया गया है

(च) "मध्यस्थ" से अभिप्राय ऐसे दलाल, एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति से है, चाहे इसे जिस नाम से जाना जाय, जो दो या दो व्यक्तियों के बीच सेवा (एतशिमन् पश्चात जिसे 'मुख्य' सेवा कहा गया है) की व्यवस्था करता है या इसमें सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपनी ओर से मुख्य सेवा प्रदान करता है;

(छ) "यात्रा का प्रारम्भ" से अभिप्राय यात्रा के उस भाग से है जिसमें यात्री किसी वाहन पर सवार होते हैं या उससे उतरते हैं, या जहाँ इसे सर्विसिंग या ईंधन भरने के लिए रोका जाता है और जहाँ यह अन्य किसी उद्देश्य के लिए यह रोक दी जाती है

(ज) "सेवा प्रदाता की अवस्थिति" से अभिप्राय-

(क) उस स्थान से है जहाँ कि सेवा प्रदाता ने अपना एकल पंजीकरण प्राप्त किया है, चाहे यह केन्द्रीकृत हो या अन्य प्रकार का, ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

(ख) ऐसे स्थान से है, जहाँ सेवा प्रदाता उपवाक्य (क) के अंतर्गत नहीं आता है

(i) ऐसे स्थान से है जहाँ उसका कारोबार स्थापित है

(ii) ऐसे स्थान से है जहाँ ऐसे स्थान से सेवा प्रदान की जाती है जो कारोबार की स्थापना के स्थान से अलग होता है अर्थात् निर्धारित स्थापना के स्थान से भिन्न अन्य स्थापना स्थान;

(iii) ऐसे स्थान से है जहाँ एक से अधिक स्थापना से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे यह व्यापार या निर्धारित हो, स्थापना ज्यादातर सेवा प्रावधानों से सीधे जुड़े होते हैं; और

(iv) ऐसे किसी स्थान के न होने पर ऐसे स्थान से है जहाँ कि सेवा प्रदाता साधारणतया निवास करता है;

(अ) "सेवा प्राप्तकर्ता की अवस्थिति" से अभिप्राय

(क) ऐसे स्थान से है जहाँ कि सेवा प्राप्त कर्ता ने एकल पंजीकरण प्राप्त किया है, चाहे यह केन्द्रीयकृत हो या अन्य प्रकार का, ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है;

(ख) जहाँ कि सेवा प्राप्तकर्ता उपवाक्य (क) के अंतर्गत नहीं आता है;

(i) ऐसे स्थान से है जहाँ कि उसका कारोबार स्थापना है; या

(ii) जहाँ कि कारोबार संस्थापना के अलावा अन्य स्थान पर सेवाओं का प्रयोग होता है अर्थात् निर्धारित संस्थापना से अन्य स्थान, ऐसी स्थापना की अवस्थिति या .

(iii) जहाँ कि सेवाओं का प्रयोग एक स्थापना से अधिक स्थान पर होता है चाहे यह कारोबारी हो या निर्धारित, ऐसी संस्थापना अधिकतर सेवाओं के उपयोग से सीधे संबंधित होती है और

(iv) ऐसे किसी स्थान के न होने पर, उस स्थान से है जहाँ कि सेवा प्राप्तकर्ता साधारणतया निवास करता है;

स्पष्टीकरण 1 :- उपवाक्य (ज) और (झ) के प्रयोजन के लिए, निगम निकाय के मामले में “ऐसा स्थान जहां पर वह साधारणतया निवास करता है” से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां कि ऐसा निगम निकाय निगमित है या अन्यथा विधिवत संस्थापित है;

स्पष्टीकरण 2. उपवाक्य (झ) के प्रयोजन के लिए, दूर संचार सेवा के मामले में साधारणतया निवास करने वाले स्थान से अभिप्राय बिलिंग के पते से है :-

- (अ) “परिवहन के साधन” से अभिप्राय ऐसे वाहन से है जो माल या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तैयार किये गये हैं;
- (ट) “गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी” से अभिप्राय
 - (i) ऐसे किसी वित्तीय संस्थान से है जो कि एक कंपनी है; या
 - (ii) किसी गैर बैंकिंग संस्थान से है जो कि एक कंपनी है और जिसका एक प्रधान कारोबार है जो किसी योजना या व्यवस्था या अन्य किसी तरीके से ऐसा जमा करती है या अन्य किसी तरीके से उधार देती है;
 - (iii) ऐसे अन्य बैंकिंग संस्थान या ऐसे संस्थानों के बर्ग, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके, विनिर्दिष्ट करे;
- (ठ) “आनलाई इनफार्मेशन एण्ड डाटाबेस एक्सेस आर रिट्रीवल सर्विस” से अभिप्राय किसी व्यक्ति को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक स्वरूप में डाटा या सूचना, चाहे इसे पुनः प्राप्त किया जा सके या नहीं, को उपलब्ध कराने से है;
- (ड) “व्यक्ति जो कर अदा करने के लिए दायी है” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत और सेवाकर नियमावली 1994 के नियम (2) के उपनियम (1) के उपवाक्य (घ) के अंतर्गत कर अदा करने के लिए दायी है;
- (ढ) “प्रदंत” में “जिसे प्रदत्त किया जाना है”, की अभिव्यक्ति भी शामिल है;
- (ण) “प्राप्त” में “जिसे प्राप्त किया जाना है” की अभिव्यक्ति भी शामिल है;
- (त) “पंजीकरण” से अभिप्राय सेवाकर नियमावली 1994 के नियम 4 के अंतर्गत किये जाने वाली पंजीकरण से है;
- (न) “दूरसंचार सेवा” का अर्थ किसी भी प्रकार की सेवा है (इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डेटा सेवाएं, वीडियो टेक्स्ट सेवाएं, रेडियो पेजिंग और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं समेत) जो प्रयोक्ताओं को तार, रेडियो, दृश्य या अन्य विद्युत-चुंबकीय साधनों से किसी संकेत, सिग्नल, लिखित, चित्र और ध्वनि या आसूचना के प्रसारण या रिसेप्शन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
- (प) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु यहां परिभाषित न किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का बहुत अर्थ होगा, जो उन्हें इस अधिनियम में आवंटित किया गया है।

3. सामान्यतः प्रावधान का स्थान - किसी सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा:

शर्त यह है कि कारोबार के सामान्य स्वरूप में प्राप्तकर्ता का स्थान उपलब्ध नहीं है, तो प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा।

4. निष्पादन आधारित सेवाओं के प्रावधान का स्थान - निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहां सेवाओं का वास्तविक निष्पादन किया जाता है, नामशः-

(क) ऐसे माल के संदर्भ में प्रदान की गयी सेवाएं जिनके लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को या सेवा प्रदाता की ओर से काम कर रहे किसी व्यक्ति को, सेवा प्रदान करने के लिए भौतिक रूप से उपलब्ध करान अपेक्षित होता है:

बशर्ते यदि ऐसी सेवाएं किसी सुदूर स्थान से इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपलब्ध करायी जाती हैं, तो प्रावधान का वह स्थान होगा, जहां सेवा के प्रावधान के समय माल स्थित थे: आगे शर्त यह है कि यह उप नियम ऐसे माल के मामले में लागू नहीं होगा यदि माल को भारत में मरम्मत, रिंडिशनिंग या रिइंजीनियरिंग के लिए पुनः निर्यात किया गया हो, उस शर्त के अधीन जैसा इस बारे में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी गयी सेवाएं, जिसे सेवा के प्राप्तकर्ता या सेवा के प्राप्तकर्ता की ओर से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए सेवा के प्राप्तकर्ता या सेवा के प्राप्तकर्ता की ओर से काम करने वाले व्यक्ति की सेवा के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाता के पास भौतिक उपस्थिति आवश्यक है।

5. अचल संपत्ति से संबंधित सेवाओं के प्रावधान का स्थान- किसी अचल संपत्ति के संबंध में सीधे उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के संबंध में, जिसमें विशेषज्ञों या संपदा एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाएं, किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या कैपसाइट, चाहे जो भी नाम दिया जाए, द्वारा होटल आवास का प्रावधान शामिल है, अचल संपत्ति के उपयोग का अधिकार देना, निर्माण कार्य को जारी रखने या समन्वय की सेवाओं जिसमें वास्तुकार या आंतरिक सजूजाकार शामिल हैं, सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा, जहां अचल संपत्ति स्थित होने के लिए आशयित है।

6. समारोह के संबंध में सेवाओं के प्रावधान का स्थान - किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, क्रीड़ा, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजक समारोह या किसी उत्सव, सम्मेलन, मेले, प्रदर्शनी या ऐसे समारोहों में प्रवेश, उसके आयोजन के रूप में, तथा ऐसे प्रवेश में आनुषंगिक सेवाओं के संबंध में सेवाओं के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा, जहां समारोह का वास्तव में आयोजन होता है।

7. एकाधिक स्थान पर प्रदत्त सेवाओं के प्रावधान का स्थान -जहां नियम 4, 5, या 6 में संदर्भित सेवा एकाधिक स्थान पर उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें कराधेय क्षेत्र में स्थित भूभाग शामिल है, इसके प्रावधान का स्थान कराधेय क्षेत्र में स्थित वह स्थान होगा, जहां सेवा की सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध करायी जाती है।

8. सेवाओं के प्रावधान का स्थान जहां प्रदाता और प्राप्तकर्ता कराधेय क्षेत्र में स्थित हैं - जहां सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों कराधेय क्षेत्र में स्थित हैं, वहां सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

9. विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रावधान का स्थान - निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान का स्थान, सेवा प्रदाता का स्थान होगा:-

- (क) किसी बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान, या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सेवाएं;
- (ख) ऑनलाइन सूचनाएं और डेटाबेस अक्सेस या पुनःप्राप्ति सेवाएं;
- (ग) मध्यवर्ती सेवाएं;
- (घ) एक माह की अवधि तक परिवहन के साधनों को किराए पर लेने वाली सेवाएं।

10. माल परिवहन सेवाओं के प्रावधान का स्थान - मेल या कूरियर को छोड़कर, माल परिवहन सेवाओं के प्रावधान का स्थान, माल के गंतव्य का स्थान होगा:

बशर्ते माल परिवहन सेवाओं प्रावधान का स्थान कर अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का स्थान होगा।

11. यात्री परिवहन सेवाओं के प्रावधान का स्थान - यात्री परिवहन सेवाओं के संबंध में प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा, जहां यात्री किसी सतत यात्रा के लिए वाहन पर सवार होता है।

12. किसी वाहन में उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के संबंध में प्रावधान का स्थान.- यात्री परिवहन प्रचालन के दौरान जिसमें वाहन पर रहने के दौरान पूर्णतः या आंशिक रूप से उपभोग की गयी सेवा शामिल है, किसी वाहन पर सवार होने के बाद उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के प्रावधान का स्थान उस यात्रा का प्रथम निर्धारित प्रस्थान बिंदु होगा।

13. कतिपय प्रयोजनों के लिए सेवाओं या परिस्थितियों के विवरण को अधिसूचित करने की शक्तियां- दोहरे कराधान या गैर-कराधान को रोकने के लिए या नियमावली को समान रूप से लागू करने के लिए, केंद्र सरकार के पास ऐसी सेवाओं या परिस्थितियों के विवरण को अधिसूचित करने की शक्तियां होंगी, जिसमें प्रावधान का स्थान सेवा के कारगर प्रयोग और आनंद का स्थान होगा।

14. नियमावली को लागू करने का आदेश - नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रथम दृष्टया, किसी सेवा के प्रावधान को एकाधिक नियम के निबंधनों में निर्धारित किया जा सकता है, इसे उस नियम के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा, जो नियमों में सबसे बाद में आता है जिस पर समान रूप से विचार की जरूरत है।

15. यह अधिसूचना 1 जुलाई 2012 को ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्बिजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 28/2012-Service Tax

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 66C and clause (hhh) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 9/2005-ST, dated the 3rd March, 2005 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 151 (E) dated the 3rd March, 2005 and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 11/2006-ST dated the 19th May, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 227 (E) dated the 19th May, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for the purpose of determination of the place of provision of services, namely:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Place of Provision of Services Rules, 2012.

(2) They shall come into force on 1st day of July, 2012.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
- (b) "account" means an account bearing interest to the depositor, and includes a non-resident external account and a non-resident ordinary account;

- (c) "banking company" has the meaning assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (d) "continuous journey" means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time, either by one service provider or through one agent acting on behalf of more than one service provider, and which involves no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate tickets or invoices are issued;
- (e) "financial institution" has the meaning assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (f) "intermediary" means a broker, an agent or any other person, by whatever name called, who arranges or facilitates a provision of a service (hereinafter called the 'main' service) between two or more persons, but does not include a person who provides the main service on his account.;
- (g) "leg of journey" means a part of the journey that begins where passengers embark or disembark the conveyance, or where it is stopped to allow for its servicing or refueling, and ends where it is next stopped for any of those purposes;
- (h) "location of the service provider" means-
 - (a). where the service provider has obtained a single registration, whether centralized or otherwise, the premises for which such registration has been obtained;
 - (b). where the service provider is not covered under sub-clause (a):
 - (i) the location of his business establishment; or
 - (ii) where the services are provided from a place other than the business establishment, that is to say, a fixed establishment elsewhere, the location of such establishment; or
 - (iii) where services are provided from more than one establishment, whether business or fixed, the establishment most directly concerned with the provision of the service; and
 - (iv) in the absence of such places, the usual place of residence of the service provider.
- (i) "location of the service receiver" means:-

- (a) where the recipient of service has obtained a single registration, whether centralized or otherwise, the premises for which such registration has been obtained;
- (b) where the recipient of service is not covered under sub-clause (a):
 - (i) the location of his business establishment; or
 - (ii) where services are used at a place other than the business establishment, that is to say, a fixed establishment elsewhere, the location of such establishment; or
 - (iii) where services are used at more than one establishment, whether business or fixed, the establishment most directly concerned with the use of the service; and
 - (iv) in the absence of such places, the usual place of residence of the recipient of service.

Explanation:- For the purposes of clauses (h) and (i), "usual place of residence" in case of a body corporate means the place where it is incorporated or otherwise legally constituted.

Explanation 2:- For the purpose of clause (i), in the case of telecommunication service, the usual place of residence shall be the billing address.

- (j) "means of transport" means any conveyance designed to transport goods or persons from one place to another;
- (k) "non-banking financial company" means-
 - (i) a financial institution which is a company; or
 - (ii) a non-banking institution which is a company and which has as its principal business the receiving of deposits, under any scheme or arrangement or in any other manner, or lending in any manner; or
 - (iii) such other non-banking institution or class of such institutions, as the Reserve Bank of India may, with the previous approval of the Central Government and by notification in the Official Gazette specify;
- (l) "online information and database access or retrieval services" means providing data or information, retrievable or otherwise, to any person, in electronic form through a computer network;

(m) "person liable to pay tax" shall mean the person liable to pay service tax under section 68 of the Act or under sub-clause (d) of sub-rule (1) of rule 2 of the Service Tax Rules, 1994;

(n) "provided" includes the expression "to be provided";

(o) "received" includes the expression "to be received";

(p) "registration" means the registration under rule 4 of the Service Tax Rules, 1994;

(q) "telecommunication service" means service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic means but shall not include broadcasting services.

(r) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Place of provision generally.- The place of provision of a service shall be the location of the recipient of service:

Provided that in case the location of the service receiver is not available in the ordinary course of business, the place of provision shall be the location of the provider of service.

4. Place of provision of performance based services.- The place of provision of following services shall be the location where the services are actually performed, namely:-

(a) services provided in respect of goods that are required to be made physically available by the recipient of service to the provider of service, or to a person acting on behalf of the provider of service, in order to provide the service:

Provided that when such services are provided from a remote location by way of electronic means the place of provision shall be the location where goods are situated at the time of provision of service:

Provided further that this sub-rule shall not apply in the case of a service provided in respect of goods that are temporarily imported into India for repairs, reconditioning or reengineering for re-export, subject to conditions as may be specified in this regard.

(b) services provided to an individual, represented either as the recipient of service or a person acting on behalf of the recipient, which require the physical presence of the receiver or the person acting on behalf of the receiver, with the provider for the provision of the service.

5. Place of provision of services relating to immovable property.— The place of provision of services provided directly in relation to an immovable property, including services provided in this regard by experts and estate agents, provision of hotel accommodation by a hotel, inn, guest house, club or campsite, by whatever, name called, grant of rights to use immovable property, services for carrying out or co-ordination of construction work, including architects or interior decorators, shall be the place where the immovable property is located or intended to be located.

6. Place of provision of services relating to events.— The place of provision of services provided by way of admission to, or organization of, a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, or entertainment event, or a celebration, conference, fair, exhibition, or similar events, and of services ancillary to such admission, shall be the place where the event is actually held.

7. Place of provision of services provided at more than one location.— Where any service referred to in rules 4, 5, or 6 is provided at more than one location, including a location in the taxable territory, its place of provision shall be the location in the taxable territory where the greatest proportion of the service is provided.

8. Place of provision of services where provider and recipient are located in taxable territory.— Place of provision of a service, where the location of the provider of service as well as that of the recipient of service is in the taxable territory, shall be the location of the recipient of service.

9. Place of provision of specified services.—The place of provision of following services shall be the location of the service provider:—

- (a) Services provided by a banking company, or a financial institution, or a non-banking financial company, to account holders;
- (b) Online information and database access or retrieval services;
- (c) Intermediary services;
- (d) Service consisting of hiring of means of transport, upto a period of one month.

10. Place of provision of goods transportation services.—The place of provision of services of transportation of goods, other than by way of mail or courier, shall be the place of destination of the goods:

Provided that the place of provision of services of goods transportation agency shall be the location of the person liable to pay tax.

11. Place of provision of passenger transportation service.—The place of provision in respect of a passenger transportation service shall be the place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey.

12. Place of provision of services provided on board a conveyance.—Place of provision of services provided on board a conveyance during the course of a passenger transport operation, including services intended to be wholly or substantially consumed while on board, shall be the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey.

13. Powers to notify description of services or circumstances for certain purposes.—In order to prevent double taxation or non-taxation of the provision of a service, or for the uniform application of rules, the Central Government shall have the power to notify any description of service or circumstances in which the place of provision shall be the place of effective use and enjoyment of a service.

14. Order of application of rules.— Notwithstanding anything stated in any rule, where the provision of a service is, *prima facie*, determinable in terms of more than one rule, it shall be determined in accordance with the rule that occurs later among the rules that merit equal consideration.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 29/2012-सेवा कर

स. 29/2012-सवा क्र. **सा.का.नि. 471(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 24/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (1) में, रा.का.नि. सं0 370(अ), तारीख 22 मई, 2007 का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय जिनका ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर की लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने सेवा कर से जितना उस मूल्य पर संगणित सेवा कर से अधिक है जो ऐसी संपत्ति पर करों अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा उदगृहीत और संगृहीत संपत्ति कर को घटाकर ऐसी स्थावर संपत्ति के किराए के लिए प्रभारित करने के समतुल्य है, स्थावर संपत्ति के किराएं पर देने के कराधेय सेवा से छूट देती है :

कुल रकम के समतुल्य है, रथावर संपत्ति के किरण पर दून या बराबर रहा। इसके अलावा एक अन्य विवरण यह है कि यह रकम को विलंबित संदाय या किसी अन्य कारणों से सेवा प्रदाता द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को परन्तु ब्याज, संपत्ति कर के विलंबित संदाय या किसी अन्य कारणों से सेवा प्रदाता द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को संदर्भ शास्ति जैसी किसी रकम को प्रभारित कुल रकम से कटौती के प्रयोजनों के लिए संपत्ति कर नहीं समझा जाएगा।

जाएगा : परन्तु यह और कि जहां कहीं ऐसी अवधि जिसके लिए संदत्त संपत्ति कर उस अवधि से भिन्न है जिसके लिए सेवा कर संदत्त या संदेय है, वहां उस अवधि जिसके लिए सेवा कर संदत्त या संदेय है के आनुपातिक संपत्ति कर की संगणना की जाएगी और इस प्रकार संगणित रकम को सेवा कर के उद्घरण के प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि के लिए स्थाक संपत्ति को किराए पर देने के लिए प्रभारित कुल रकम से अपवृज्जित किया जाएगा ।

उदाहरण :

अपैल से सितम्बर के लिए संदर्भ संपत्ति कर = 12,000/- रुपए

अप्पैल के लिए प्राप्त किराया = 1,00,000/- रुपए

अप्रैल के लिए ब्राह्मण सेवा की दर = 98,000/- रुपए $(1,00,000 - 12000/6) * \frac{1}{6}$ लागू सेवा कर की दर

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगी ।

फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi; the 20th June, 2012

No. 29/2012-Service Tax

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), and in supersession of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 24/2007-Service Tax, dated the 22nd May, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 370 (E), dated the 22nd May, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service of renting of an immovable property, from so much of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act, as is in excess of the service tax calculated on a value which is equivalent to the gross amount charged for renting of such immovable property less taxes on such property, namely property tax levied and collected by local bodies:

Provided that any amount such as interest, penalty paid to the local authority by the service provider on account of delayed payment of property tax or any other reasons shall not be treated as property tax for the purposes of deduction from the gross amount charged:

Provided further that wherever the period for which property tax paid is different from the period for which service tax is paid or payable, property tax proportionate to the period for which service tax is paid or payable shall be calculated and the amount so calculated shall be excluded from the gross amount charged for renting of the immovable property for the said period, for the purposes of levy of service tax.

Example:

Property tax paid for April to September = Rs. 12,000/-

Rent received for April = Rs. 1, 00,000/-

Service tax payable for April = Rs. 98,000/- (1, 00,000 -12,000/6) * applicable rate of service tax

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 30/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 472(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) 'द्वारा प्रदत्त शक्तियों' का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 15/2012-सेवा कर, तारीख 17 मार्च, 2012 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अधिसूचना सं0 36/2004-सेवा खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 213 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 और अधिसूचना सं0 36/2004-सेवा खंड 3, उपखंड (i) में कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रति सा.का.नि. 849 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उक्त उपधारा के करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमूल से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कराधेय रोवाओं और उन पर संदेय सेवा कर के विरतार को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

I. कराधेय सेवाएं

(अ) (i) बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति के बीमा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत ;

(ii) सङ्क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में किसी माल परिवहन अभिकरण द्वारा वहां प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत, जहां माल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या उसके द्वारा शारीरिक कोई कारखाना है ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी है ;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई सहकारी सोसाइटी है ;

(घ) उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय है ; या

(च) कोई भागीदारी फर्म है जो वाहे किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, जिसमें व्यक्तियों का रांगम सम्मिलित है ;

(iii) किसी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किरी निगमित निकाय या भागीदारी फर्म को प्रायोजन के द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत ;

(iv) द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत ;

(i) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, या

(ii) एक व्यक्तिगत वकील या अधिवक्ताओं के समर्थन सेवाओं के माध्यम से एक फर्म है, या

(iii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या समर्थन सेवाओं के माध्यम को छोड़कर अचल संपत्ति को किराये पर लिया,

किसी भी व्यापार कर योग्य स्वेच्छा में स्थित इकाई;

(v) किसी कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित निगमित निकाय के रूप में रजिस्ट्रीकृत कारबार एकक को किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार के समान पक्षित में नहीं है, किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुरुंब या भारीदारी फर्म द्वारा, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समान भी है, किसी प्रयोजन या संकर्म संविदा के निष्पादन के सेवा भाग के लिए यात्री वहन करने या मानव शक्ति के प्रदाय के लिए डिजाइन किए गए मोटर यान को किराए पर प्रदान करने या प्रदान किए जाने के लिए सहमत;

(आ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है, प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने के लिए सहमत और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी कराधेय रोवा के संबंध में;

(II) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सेवा प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो (I) में विविरित कराधेय सेवाओं के लिए रोवा प्रदान करता है, संदेश सेवा कर कर विस्तार निम्नलिखित राशणी में यथाविविरित होगा, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	सेवा का वर्णन	सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेश सेवा कर की प्रतिशतता	सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेश सेवा कर की प्रतिशतता
1	बीमा कारबार करने वाले किसी व्यक्ति के बीमा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%
2	सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%
3	प्रयोजन के द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%
4	माध्यरथम् अधिकरण के द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%
5	व्यक्ति अधिकर्ता द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में व्यक्तिगत वकील या फर्म के वकील की कानूनी सेवा के माध्यम से	कुछ नहीं	100%
6	सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सहायक सेवा किराये पर ली अचल संपत्ति को छोड़कर के द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%
7	(क) उपशमगित मूल्य पर यात्रियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए मोटर	कुछ नहीं	100%

	यान को किराए पर प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में जो कि व्यापार की समान पक्षिति में नहीं है,		
	(ख) गैर उपशमनित मूल्य पर यात्रियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए मोटर यान को किराए पर प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में जो कि व्यापार की समान पक्षिति में नहीं है,	60%	40%
8	किसी प्रयोजन के लिए मानव शक्ति के प्रदाय के द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	25%	75%
9	संकर्म संविदा के निष्पादन के सेवा भाग के लिए प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में	50%	50%
10	किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित है प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत या कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेवाओं के संबंध में	कुछ नहीं	100%

स्पष्टीकरण 1. ऐसा व्यक्ति जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित और माल वाहक से सङ्क द्वारा गाल के परिवहन के लिए भाड़ा संदाय करता है या संदाय के लिए दायी है ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए सेवा प्राप्त करता है।

आधिसूचना के प्रयोजन के लिए रेवा प्राप्ति के स्पष्टीकरण ॥. काम अनुबंध सेवा में, जहां दोनों सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता कर का गुणात्मक करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है, सेवा प्राप्तकर्ता को मूल्यांकन पढ़ति को चुनने का विकंत्य है जो कि सेवा प्रदाता की मूल्यांकन पद्धति पर निर्भर नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 30/2012-Service Tax

G.S.R. 472(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and in supersession of (i) notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2012-Service Tax, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 213(E), dated the 17th March, 2012, and (ii) notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the following taxable services and the extent of service tax payable thereon by the person liable to pay service tax for the purposes of the said sub-section, namely:—

I. The taxable services,—

- (A) (i) provided or agreed to be provided by an insurance agent to any person carrying on the insurance business;
- (ii) provided or agreed to be provided by a goods transport agency in respect of transportation of goods by road, where the person liable to pay freight is,—
 - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
 - (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India;
 - (c) any co-operative society established by or under any law;

(d) any dealer of excisable goods, who is registered under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder;

(e) any body corporate established, by or under any law; or

(f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons;

(iii) provided or agreed to be provided by way of sponsorship to anybody corporate or partnership firm located in the taxable territory;

(iv) provided or agreed to be provided by,-

- (A) an arbitral tribunal, or
- (B) an individual advocate or a firm of advocates by way of support services, or
- (C) Government or local authority by way of support services excluding,-

 - (1) renting of immovable property, and
 - (2) services specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994,

to any business entity located in the taxable territory;

(v) provided or agreed to be provided by way of renting of a motor vehicle designed to carry passengers to any person who is not in the similar line of business or supply of manpower for any purpose or service portion in execution of works contract by any individual, Hindu Undivided Family or partnership firm, whether registered or not, including association of persons, located in the taxable territory to a business entity registered as body corporate, located in the taxable territory;

(B) provided or agreed to be provided by any person which is located in a non-taxable territory and received by any person located in the taxable territory;

(II) The extent of service tax payable thereon by the person who provides the service and the person who receives the service for the taxable services specified in (I) shall be as specified in the following Table, namely:-

TABLE

Sl.No.	Description of a service	Percentage of service tax payable by the person providing service	Percentage of service tax payable by the person receiving the service
1	in respect of services provided or agreed to be provided by an insurance agent to any person carrying on insurance business	Nil	100%
2	in respect of services provided or agreed to be provided by a goods transport agency in respect of transportation of goods by road	Nil	100%
3	in respect of services provided or agreed to be provided by way of sponsorship	Nil	100%
4	in respect of services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal	Nil	100%
5	in respect of services provided or agreed to be provided by individual advocate or a firm of advocates by way of legal services	Nil	100%
6	in respect of services provided or agreed to be provided by Government or local authority by way of support services excluding,- (1) renting of immovable property, and (2) services specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994	Nil	100%
7	(a) in respect of services provided or agreed to be provided by way of renting of a motor vehicle designed to carry passengers on	Nil	100 %

	abated value to any person who is not engaged in the similar line of business		
	(b) in respect of services provided or agreed to be provided by way of renting of a motor vehicle designed to carry passengers on non abated value to any person who is not engaged in the similar line of business	60%	40%
8.	in respect of services provided or agreed to be provided by way of supply of manpower for any purpose	25%	75 %
9.	in respect of services provided or agreed to be provided in service portion in execution of works contract	50%	50%
10	in respect of any taxable services provided or agreed to be provided by any person who is located in a non-taxable territory and received by any person located in the taxable territory	Nil	100%

Explanation-I. - The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.

Explanation-II. - In works contract services, where both service provider and service recipient is the persons liable to pay tax, the service recipient has the option of choosing the valuation method as per choice, independent of valuation method adopted by the provider of service.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 31/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 473(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इराके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2009-सेवा कर, तारीख 7 जुलाई, 2009 को, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है था करने का लोप किया गया है, माल के निर्यातकर्ता द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्यातकर्ता कहा गया है) प्राप्त की गई और नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल (जिसे इसमें इराके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) के निर्यात के लिए उपयोग की गई कराधेय सेवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट सेवा कहा गया है) को उक्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन उन पर उद्गृहणीय संपूर्ण सेवा कर से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :-

सम्पर्क

क्रम सं.	कराधेय सेवा का वर्णन	शर्त
(1)	(2)	(3)
1.	<p>किसी निर्यातकर्ता को किसी आधान भाड़ा स्टेशन या अंतर्देशीय आधान डिपो से, यथास्थिति, ऐसे पत्तन या वायुपत्तन तक, जहां से माल का निर्यात किया जाता है, किसी माल वाहन से माल परिवहन अभिकरण द्वारा उक्त माल के परिवहन के लिए उपलब्ध कराई गई सेवा ; या</p> <p>किसी निर्यातकर्ता को सीधे उनके हटाए जाने के स्थान से, यथास्थिति, किसी अंतर्देशीय आधान डिपो, किसी आधान भाड़ा स्टेशन,</p>	<p>निर्यातकर्ता को परेषण टिप्पण को, उसके नाम में, चाहे किसी नाम से जारी किया गया हो, प्रत्युत करना होगा ।</p>

किसी पत्तन या वायुपत्तन तक, जहां से माल का निर्यात किया जाता है, किसी माल वाहन से माल परिवहन अभिकरण द्वारा उक्त माल के परिवहन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवा ।		
--	--	--

परंतु यह कि -

(क) छूट ऐसे निर्यातकर्ता को उपलब्ध होगी, जो,-

- (i) उक्त छूट का उपभोग करने से पूर्व यथास्थिति, कारखाने या प्रादेशिक कार्यालय या मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप ईएक्सपी 1 में सूचना देता है ;
- (ii) यथास्थिति, वाणिज्य मंत्रालय या वर्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किसी निर्यात संबंधन परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत है ;
- (iii) आयात-निर्यात संहिता सं. का धारक है ;
- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;
- (v) विनिर्दिष्ट सेवा के लिए सेवा कर नियम, 1984 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) के उपखंड (i) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन सेवा कर का संदाय करने का दायी है ;
- (ख) सेवा प्रदाता द्वारा निर्यातकर्ता को जारी किया गया बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज, जो किसी नाम से ज्ञात हो, जिसपर निर्यातकर्ता, छूट का उपभोग करने का आशय रखता है, यह दर्शित करते हुए कि निर्यातकर्ता, खंड (क) की मद 5 के निबंधनानुसार सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है, निर्यातकर्ता के नाम में जारी किया जाएगा ;
- (ग) छूट का उपभोग करने वाला निर्यातकर्ता, उक्त छह मास की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में प्ररूप ईएक्सपी 2 में विवरणी फाइल करेगा ;
- (घ) निर्यातकर्ता, अर्द्धवार्षिक विवरणी के साथ, प्रमाणन के पश्चात् खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मूल दस्तावेजों और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा ;
- (ङ) विवरणी के साथ सलग्न दस्तावेजों में, निर्यातकर्ता या प्राधिकृत व्यक्ति से इस आशय का कि परिवहन पत्र सं. का उल्लेख करते हुए, माल के निर्यात का उपयोग कर लिया गया है, एक प्रमाणपत्र अंतर्विष्ट होगा ।

(च) जहां निर्यातकर्ता, कोई संबंधित स्वत्वधारी समुत्थान या भागीदारी फर्म है, वहां विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेज स्वयं निर्यातकर्ता द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे और जहां निर्यातकर्ता कोई लिमिटेड कंपनी है वहां विवरणी के साथ संलग्न दस्तावेज, निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना तारीख 2012 को प्रवृत्त होगी ।

प्रस्तुप-ईएक्सपी 1

[पैरा (क) (i) देखें]

क्रम सं

(अधिकारिता रखने वाले सहायक/उपायुक्त के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,

उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

महोदय,

मैं/हम सड़क मार्ग से उक्त माल के परिवहन के लिए सेवाओं के संबंध में, अधिसूचना स. 31/2012-सेवा कर तारीख 20 जून, 2012 के अधीन सेवा कर से छूट का उपभोग करने का आशय रखता हूँ/रखते हैं, जिनका माल के निर्यात के लिए उपयोग कर लिया गया है और सुसंगत विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं

1. निर्यातकर्ता का नाम.....
2. सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.....
3. प्रभाग कमिशनरी.....
4. निर्यात परिषद की सदस्यता सं.....
5. निर्यात परिषद का नाम.....
6. निर्यातकर्ता के रजिस्ट्रीकृत/प्रधान कार्यालय का पता.....
7. निर्यातकर्ता का टेलीफोन नं. और ई-मेल आईडी
8. आयात-निर्यात कोड सं.....
9. बैंक खाते के ब्यौरे (बैंक का नाम, शाखा पता और लेखा संख्यांक)

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त अधिसूचना में अधिकथित और पूर्वोक्त विशिष्टियों में किरी परिवर्तन की दशा में, शर्तों का अनुपालन करूंगा/करेंगे । मैं/हम उसको संसूचित करूंगा/करेंगे ।

तारीख

स्थान

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर और पूरा पता
(मोहर लगाएं)

रसीद (अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त/उपायुक्त के कार्यालय द्वारा दी जाएगी)

..... (निर्यातकर्ता का नाम) द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्तुप ईएक्सपी 1 तारीख प्राप्त किया । उक्त संसूचना स्वीकार की जाती है और अभिस्वीकृति सं..... (ऊपर की क्रम सं.) दी जाती है ।

सहायक/उपायुक्त की ओर से

(मोहर)

प्रस्तुप-ईएक्सप्री 2

[परंतुक का खंड (ग) देखें]

सेवा में,

उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

महोदय,

मैंने/हमने, सेवाओं, अर्थात्, किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा सङ्क मार्ग से उक्त माल के परिवहन के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं और उसका से तक की अवधि के दौरान माल के निर्यात के लिए उपयोग कर लिया है और सुसंगत विशिष्टियां निम्नप्रकार से हैं :—

1. निर्यातकर्ता का नाम
2. निर्यातकर्ता के रजिस्ट्रीकृत/प्रधान कार्यालय का पता.....
3. निर्यातकर्ता का टेलीफोन नं. और ई-मेल आईडी
4. सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.
5. प्रभाग कमिशनरी.....
6. निर्यात परिषद की सदस्यता सं.
7. आयात-निर्यात कोड सं.
8. निर्यात परिषद का नाम.....
9. बैंक खाते के ब्यौरे (बैंक का नाम, शाखा पता और लेखा संख्यांक)

सारणी - क

क्रम सं. को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के दौरान निर्यातित माल के ब्यौरे (जिस पर सेवा कर की छूट का उपभोग किया गया है)							
	पोतपरिवहन बिल/निर्यात बिल के ब्यौरे (कृपया पोतपरिवहन बिल या निर्यात बिल की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें) और निर्यातित माल के ब्यौरे (एक वाणिज्य से अधिक के निर्यात की दशा में कृपया वाणिज्या अनुसार प्रोफार्मा में भरें)							
सं.	तारीख	निर्यात आदेश की तारीख	निर्यात बीजक सं.	तारीख	निर्यातित माल का वर्णन	मात्रा (कृपया यूनिट का उल्लेख करें)	पोत निःशुल्क मूल्य (लाख रुपयों में)	

सारणी - ख

..... को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के दौरान उपयोग की गई छूट के संबंध में सारणी - 'क' में उल्लिखित पोत परिवहन बिल या नियाति बिल के अंतर्गत आने वाले माल के नियाति के लिए उपयोग की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के ब्यौरे				नियाति के लिए ऐसी सेवाओं के उपयोग को दर्शित करने वाले संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे, जिनके ब्यौरे सारणी 'क' में उल्लिखित हैं (स्वयं द्वारा सत्यापित)	छूट के रूप में दावा किए गए सेवा कर की कुल रकम (लाख रुपयों में)
सेवा प्रदाता का नाम	सेवा प्रदाता का पता	बीजक सं.	तारीख		

9. घोषणा -

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि -

- मैंने अधिसूचना सं. 31/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया है ;
- इस आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा हर प्रकार से पूरी है और यह कि मैं नियातकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं ;
- केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन उक्त माल के नियाति के लिए उपयोग की गई विनिर्दिष्ट सेवा पर संदर्भ सेवा कर का कोई केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं है ;
- मैं/हम सभी अपेक्षित दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मैं यह समझता हूं कि सम्यक् रूप से प्रमाणित अपेक्षित दस्तावेज के नियत समय के भीतर विवरणी फाइल करने में असफलता से या अपेक्षित दस्तावेज संलग्न न करने से उपर्युक्त दावा किए गए प्रतिदाय के लिए मैं/ हम वर्जित हो जाऊंगा/हो जाएंगे।

तारीख.....

स्थान.....

संलग्न - उपरोक्तानुसार

नियातकर्ता के हस्ताक्षर और पूरा पता

(मोहर लगाएं)

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 31/2012-Service Tax

G.S.R. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2009-Service Tax, dated the 7th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.490 (E), dated the 7th July, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service received by an exporter of goods (hereinafter referred to as the exporter) and used for export of goods (hereinafter referred to as the said goods), of the description specified in column (2) of the Table below (hereinafter referred to as the specified service), from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act, subject to the conditions specified in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Description of the taxable service (2)	Conditions (3)
(1)		
1.	Service provided to an exporter for transport of the said goods by goods transport agency in a goods carriage from any container freight station or inland container depot to the port or airport, as the case may be, from where the goods are exported; or Service provided to an exporter in relation to transport of the said goods by goods transport agency in a goods carriage directly from their place of removal, to an inland container depot, a container freight station, a port or airport, as the	The exporter shall have to produce the consignment note, by whatever name called, issued in his name.

case may be, from where the goods are exported.	१८
---	----

Provided that—

(a) the exemption shall be available to an exporter who,—

(i) informs the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the factory or the regional office or the head office, as the case may be, in Form EXP1 appended to this notification, before availing the said exemption;

(ii) is registered with an export promotion council sponsored by the Ministry of Commerce or the Ministry of Textiles, as the case may be;

(iii) is a holder of Import-Export Code Number;

(iv) is registered under section 69 of the said Act;

(v) is liable to pay service tax under sub-section (2) of section 68 of said Act, read with item (B) of sub-clause (i) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 2 of the Service Tax Rules, 1994, for the specified service;

(b) the invoice, bill or challan, or any other document by whatever name called issued by the service provider to the exporter, on which the exporter intends to avail exemption, shall be issued in the name of the exporter, showing that the exporter is liable to pay the service tax in terms of item (v) of clause (a);

(c) the exporter availing the exemption shall file the return in Form EXP2, every six months of the financial year, within fifteen days of the completion of the said six months;

(d) the exporter shall submit with the half yearly return, after certification, the documents in original specified in clause (b) and the certified copies of the documents specified in column (4) of the said Table;

(e) the documents enclosed with the return shall contain a certification from the exporter or the authorised person, to the effect that taxable service to which the document pertains, has been received and used for export of goods by mentioning the specific shipping bill number on the said document.

(f) where the exporter is a proprietorship concern or partnership firm, the documents enclosed with the return shall be certified by the exporter himself and where the exporter

is a limited company, the documents enclosed with the return shall be certified by the person authorised by the Board of Directors;

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

Form EXP1

[See item (i) of clause (a) of proviso]

S.No-----

(to be filled in by the office of jurisdictional Assistant / Deputy Commissioner)

To,
The Deputy Commissioner /Assistant Commissioner of Central Excise

Sir,

I/We intend to avail of the exemption from service tax under Notification No. 31/2012-ST, dated 20th June, 2012 in respect of service for transport of the said goods by road, which has been used for export of goods and the relevant particulars are as follows.

1. Name of the exporter.....
2. Service Tax Registration No.....
3. Division Commissionerate
- 4 Membership No. the Export Council.....
- 5 Name of the Export Council.....
6. Address of the registered / head office of exporter.....
7. Tel. No. and e-mail ID of the exporter.....
8. Import -Export Code No.....
9. Details of Bank Account (Name of Bank, branch address and account number).....

I/we undertake that I/we shall comply with the conditions laid down in the said notification and in case of any change in aforementioned particulars; I/We shall intimate the same.

Date:

Place:

Signature and full address of Exporter
(Affix stamp)

Receipt (to be given by office of Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner having jurisdiction) Received Form EXP1 dated ---/---/--- submitted by _____ (name of the exporter). The ~~said~~ intimation is accepted and given acknowledgment No. _____ (S. No. Above)

For Assistant, / Deputy Commissioner
(Stamp)

Form EXP2

[See clause (c) of proviso]

To,

The Deputy Commissioner /Assistant Commissioner of Central Excise

Sir,

I/We have availed of exemption of service tax under Notification No. 31/2012-ST, dated 20th June, 2012 in respect of services, namely, the services provided for transport of said goods in a goods carriage by goods transport agency, and has used the same for export of goods during the period from to..... and the relevant particulars are as follows:-

1. Name of the exporter.....
2. Address of the registered / head office of exporter.....
3. Tel. No. and e-mail ID of the exporter.....
4. Service Tax Registration No.....
5. Division Commissionerate
6. Membership No. Of the Export Council.....
7. Import Export Code No.....
8. Name of the Export Council.....
9. Details of Bank Account (Name of Bank, branch address and account number).....

Table-A

Sr. No.	Details of goods exported (on which exemption of service tax availed) during the six months ending on.....						
	Details of Shipping Bill/ Bill of export (Please enclose self attested copy of Shipping Bill or Bill of Export) and Details of goods exported (in case of exports of more than one commodity, please fill in the proforma, commodity-wise)						
No.	Date	Date of Let export order	Export invoice no	Date	Description of goods exported	Quantity (please mention the unit)	FOB value (in rupees in lakh)

Table- B

Details of specified service used for export of goods, covered under the Shipping Bill or Bill of Export mentioned in Table A in respect of which the exemption has been availed during the six months ending on.....	Details of documents attached showing the use of such service for export, the details of which are mentioned in Table A (self attested)	Total amount of service tax claimed as exemption (rupees in lakhs)
Name of service provider	Address of service provider	Invoice No.

9. Declaration:-

I / We hereby declare that-

(i) I have complied with all the conditions mentioned in Notification No. 31/2012-ST, dated 20th June, 2012;

(ii) the information given in this application form is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the exporter;

(iii) no CENVAT credit of service tax paid on the specified service used for export of said goods taken under the CENVAT Credit Rules, 2004;

(iv) I / we, am/ are enclosing all the required documents. Further, I understand that failure to file the return within stipulated time or non-enclosure of the required document, duly certified, would debar me/us for the refund claimed aforesaid.

Date:.....

Place:.....

**Signature and full address of Exporter
(Affix stamp)**

Enclosures: as above

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 32/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 474(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2007-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2007 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता विकास बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर या किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यगता पार्क द्वारा प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कराधेय सेवाओं को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन उन पर उद्गृहणीय संपूर्ण सेवा कर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :-

1. यह कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क या प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर, जो छूट का फायदा लेना चाहता है, प्रत्येक इनक्यूबेटी से नीचे प्ररूप 2 में प्राप्त जानकारी राहिता इनक्यूबेटर के ब्यौरे नीचे प्ररूप 1 में अपेक्षित जानकारी, छूट प्राप्त करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त को देगा ; और

2. यह कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क या प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर उक्त प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून से पहले उसी शिति में जानकारी देगा।

प्ररूप 1 - प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क द्वारा दी जाने वाली जानकारी

वित्तीय वर्ष में फाइल की गई

(क) प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क का नाम

(ख) पता

(ग) क्या छूट का फायदा पहली बार ले रहा है

(घ) यदि 3 का उत्तर सकारात्मक नहीं है तो वह तारीख जिससे फायदा लिया जा रहा है

(ङ) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	कराधेय सेवा का विवरण	प्रदान की गई कराधेय सेवा का मूल्य
		इनक्यूबेटी को अन्य को

(च) संलग्नक के अनुसार इनक्यूबेटीयों द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे

स्थान

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख

अभिस्वीकृति

मैं, अवधि के लिए प्ररूप 1 की प्राप्ति अभिस्वीकार करता हूँ

स्थान

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और

तारीख

सेवा कर अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम और शासकीय मुद्रा सहित)

प्ररूप 2 - प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क द्वारा
प्रत्येक इनक्यूबेटी से प्राप्त की जाने वाली और प्ररूप 1 के साथ
फाइल की जाने वाली जानकारी

1. इनक्यूबेटी को नाम
2. पता
3. परियोजना के ब्यौरे
4. प्रौद्योगिकी कारबार इनक्यूबेटर/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (इनक्यूबेटर) के साथ
करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख
5. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारबार आवर्त
6. पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	कराधेय सेवा का विवरण	प्रदान की गई सेवा का मूल्य

स्थान

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख

2. यह अधिसूचना तारीख, 2012 से ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 32/2012-Service Tax

G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and in supersession of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification number 9/2007-ST, dated the 1st March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 163 (E), dated the 1st March, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services, provided or to be provided, by a Technology Business Incubator (TBI) or a Science and Technology Entrepreneurship Park (STEP) recognized by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act, subject to following conditions, namely:—

1. that the STEP or the TBI, who intends to avail the exemption, shall furnish the requisite information in Format I below containing the details of the incubator along with the information in Format II below received from each incubatee to the concerned Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, before availing the exemption; and
2. that the STEP or the TBI shall furnish the information in the said Format I and Format II in the same manner before the 30th day of June of each financial year.

Format - I - Information to be furnished by TBI or the STEP

Filed in the financial year _____

- (a) Name of the Technology Business Incubator / Science and Technology Entrepreneurship Park _____
- (b) Address _____
- (c) Whether availing benefit of exemption for first time _____
- (d) If the answer to 3 is not in affirmative, the date from which benefit is being availed _____
- (e) Details of taxable services provided during the previous financial year :—

Sl. No.	Description of Taxable Service	Value of taxable Service Provided	
		To incubatee	To others

(f) Details of Taxable services provided by incubatees as per enclosure _____

Place _____

Date _____

Signature of the authorised person

Acknowledgement

I hereby acknowledge the receipt of Format I for the period _____

Place _____

Date _____

Signature of the Officer of
Central Excise and Service Tax
(with Name and Official seal)

**Format II – Information to be obtained by TBI / STEP from each incubatee and to be filed
along with Format I**

1. Name of the Incubatee _____

2. Address _____

3. Details of the project _____

4. Date of signing agreement with the TBI / STEP (incubator) _____

5. Total business turnover during the previous financial year _____

6. Details of taxable services provided during the previous financial year _____

Sl. No.	Description of Taxable Service	Value of Service Provided

Place _____

Date _____

Signature of the authorized person

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 33/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 475(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजरव विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2005-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2005 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 140(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए से अनधिक कुल मूल्य की कराधेय सेवाओं को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन उन पर उद्गृहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है :

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

- (i) किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के बांड नाम या व्यापार नाम के अधीन चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं है, प्रदान की गई कराधेय सेवाएं ; या
- (ii) कराधेय सेवाओं का उतना मूल्य, जिसकी बाबत ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति में सेवा कर संदर्भ किया जाएगा, सेवा कर नियम, 1994 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, लागू होगी, अर्थात् :-

- (i) कराधेय सेवा के प्रदाता के पास इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट का उपयोग न करने और उसके द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर सेवा कर संदर्भ करने का विकल्प है तथा किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे विकल्प का एक बार प्रयोग करने पर उसको ऐसे वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ;

- (ii) कराधेय सेवा का प्रदाता, सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 या नियम 13 के अधीन किसी ऐसे निवेश सेवाओं पर सेवा कर के सेनवेट प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगा, जिनका प्रयोग उक्त कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन सेवा कर के संदाय से छूट का उपभोग किया जाता है;
- (iii) कराधेय सेवा का प्रदाता, उक्त नियमों के नियम 3 के अधीन उस अवधि के दौरान, जिसमें सेवा प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन सेवा कर के संदाय से छूट का उपभोग करता है, प्राप्त किए गए पूंजीगत माल पर सेनवेट प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगा;
- (iv) कराधेय सेवा का प्रदाता केवल ऐसे निवेशों या निवेश सेवाओं पर, जो उस तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त किए गए हैं, जिसको सेवा प्रदाता सेवा कर संदाय करना आरंभ करता है, सेनवेट प्रत्यय का उपभोग करेगा और जिनका उपयोग ऐसी कराधेय सेवाओं का उपबंध करने के लिए किया गया है, जिनके लिए सेवा कर संदेय है;
- (v) कराधेय सेवा के ऐसे प्रदाता के लिए, जो इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा लेना आरंभ करता है, उस तारीख को जिसको कराधेय सेवा का प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा लेना आरंभ करता है, स्टाक में पड़े या प्रक्रियाधीन ऐसे निवेशों की बाबत उसके द्वारा लिए गए सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम का संदाय करना अपेक्षित होगा;
- (vi) कराधेय सेवा प्रदाता के खाते में उपरै (v) में निर्दिष्ट रकम की कटौती करने के पश्चात् अनुप्रयुक्ति पड़े सेनवेट प्रत्यय के अतिशेष, यदि कोई है, का उपयोग उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) के उपबंध के निवंधनानुसार नहीं किया जाएगा और वे उस तारीख को व्यपगत हो जाएंगे जिसको सेवा प्रदाता इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा लेना आरंभ करता है;
- (vii) जहां कोई कराधेय सेवा प्रदाता एक या अधिक परिसरों से एक या अधिक कराधेय सेवाएं प्रदान करता है वहां इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी सभी कराधेय सेवाओं के कुल मूल्य और ऐसे सभी परिसरों के लिए लागू होगी न कि प्रत्येक परिसर या प्रत्येक सेवा के लिए पृथक् रूप से लागू होगी; और
- (viii) कराधेय सेवा के प्रदाता द्वारा एक या अधिक परिसरों से प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।

3. किसी माल परिवहन अभिकरण द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवा के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा लेने के लिए दस लाख रुपए से अनधिक कुल मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ उक्त वित्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन ऐसा माल परिवहन अभिकरण द्वारा प्रभारित कुल रकम मई प्राप्त किया गया ऐसा संदाय, जिसके लिए सेवा कर संदाय करने के लिए

वह व्यक्ति दायी है, जैसा कि सेवा कर नियम, 1994 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “ब्रांड नाम” या “व्यापार नाम” से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अर्थात् कोई नाम या कोई चिन्ह जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लोगो, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई ऐसा लेख, जिसका प्रयोग ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में या ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपर्युक्त सहित या उसके बिना ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा है;

(ख) “कुल मूल्य” से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रथम क्रमवर्ती बीजकों में प्रभारित कराधेय सेवाओं का कुल योग अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं के मद्दे, जो किसी अन्य अधिसूचना के अधीन उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अंधीन उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट प्राप्त है, जारी किए गए बीजकों में प्रभारित मूल्य नहीं है।”

4. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2012 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 33/2012-Service Tax

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Finance Act), and in supersession of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. number 140(E), dated the 1st March, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services of aggregate value not exceeding ten lakh rupees in any financial year from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to,—

- (i) taxable services provided by a person under a brand name or trade name, whether registered or not, of another person; or
- (ii) such value of taxable services in respect of which service tax shall be paid by such person and in such manner as specified under sub-section (2) of section 68 of the said Finance Act read with Service Tax Rules, 1994.

2. The exemption contained in this notification shall apply subject to the following conditions, namely:-

- (i) the provider of taxable service has the option not to avail the exemption contained in this notification and pay service tax on the taxable services provided by him and such option, once exercised in a financial year, shall not be withdrawn during the remaining part of such financial year;
- (ii) the provider of taxable service shall not avail the CENVAT credit of service tax paid on any input services, under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit Rules, 2004 (herein after referred to as the said rules), used for providing the said taxable service, for which exemption from payment of service tax under this notification is availed;
- (iii) the provider of taxable service shall not avail the CENVAT credit under rule 3 of the said rules, on capital goods received, during the period in which the service provider avails exemption from payment of service tax under this notification;
- (iv) the provider of taxable service shall avail the CENVAT credit only on such inputs or input services received, on or after the date on which the service provider starts paying service tax, and used for the provision of taxable services for which service tax is payable;
- (v) the provider of taxable service who starts availing exemption under this notification shall be required to pay an amount equivalent to the CENVAT credit taken by him, if any, in respect of such inputs lying in stock or in process on the date on which the provider of taxable service starts availing exemption under this notification;
- (vi) the balance of CENVAT credit lying unutilised in the account of the taxable service provider after deducting the amount referred to in sub-paragraph (v), if any, shall not be utilised in terms of provision under sub-rule (4) of rule 3 of the said rules and shall lapse on the day such service provider starts availing the exemption under this notification;
- (vii) where a taxable service provider provides one or more taxable services from one or more premises, the exemption under this notification shall apply to the aggregate value of all such taxable services and from all such premises and not separately for each premises or each services; and
- (viii) the aggregate value of taxable services rendered by a provider of taxable service from one or more premises, does not exceed ten lakh rupees in the preceding financial year.

3. For the purposes of determining aggregate value not exceeding ten lakh rupees, to avail exemption under this notification, in relation to taxable service provided by a goods transport agency, the payment received towards the gross amount charged by such goods

transport agency under section 67 of the said Finance Act for which the person liable for paying service tax is as specified under sub-section (2) of section 68 of the said Finance Act read with Service Tax Rules, 1994, shall not be taken into account.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(A) "brand name" or "trade name" means a brand name or a trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, logo, label, signature, or invented word or writing which is used in relation to such specified services for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified services and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person;

(B) "aggregate value" means the sum total of value of taxable services charged in the first consecutive invoices issued during a financial year but does not include value charged in invoices issued towards such services which are exempt from whole of service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act under any other notification."

4. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 34/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 476(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उन बाटों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	(2)
(1)		
1.	06/2012-सेवा कर, तारीख 17.03.2012 [सा.का.नि. 204 (अ), तारीख 17.03.2012]	
2.	45/2011-सेवा कर, तारीख 12.09.2011 [सा.का.नि. 672(अ), तारीख 12.09.2011]	
3.	42/2011-सेवा कर, तारीख 25.07.2011 [सा.का.नि. 566(अ), तारीख 25.07.2011]	
4.	33/2011-सेवा कर, तारीख 25.04.2011 [सा.का.नि. 341(अ), तारीख 25.04.2011]	
5.	31/2011-सेवा कर, तारीख 25.04.2011 [सा.का.नि. 339 (अ), तारीख 25.04.2011]	
6.	30/2011-सेवा कर, तारीख 25.04.2011 [सा.का.नि. 338 (अ), तारीख 25.04.2011]	
7.	11/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 168 (अ), तारीख 01.03.2011]	
8.	10/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 167 (अ), तारीख 01.03.2011]	

9.	09/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 166 (अ), तारीख 01.03.2011]
10.	08/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 165 (अ), तारीख 01.03.2011]
11.	07/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 164 (अ), तारीख 01.03.2011]
12.	06/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 163 (अ), तारीख 01.03.2011]
13.	05/2011-सेवा कर, तारीख 01.03.2011 [सा.का.नि. 162 (अ), तारीख 01.03.2011]
14.	58/2010-सेवा कर, तारीख 21.12.2010 [सा.का.नि. 996 (अ), तारीख 21.12.2010]
15.	53/2010-सेवा कर, तारीख 21.12.2010 [सा.का.नि. 991 (अ), तारीख 21.12.2010]
16.	50/2010-सेवा कर, तारीख 08.10.2010 [सा.का.नि. 823 (अ), तारीख 08.10.2010]
17.	47/2010-सेवा कर, तारीख 03.09.2010 [सा.का.नि. 727 (अ), तारीख 03.09.2010]
18.	42/2010-सेवा कर, तारीख 28.06.2010 [सा.का.नि. 563 (अ), तारीख 28.06.2010]
19.	41/2010-सेवा कर, तारीख 28.06.2010 [सा.का.नि. 562 (अ), तारीख 28.06.2010]
20.	38/2010-सेवा कर, तारीख 28.06.2010 [सा.का.नि. 559 (अ), तारीख 28.06.2010]
21.	32/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 538 (अ), तारीख 22.06.2010]
22.	31/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 537 (अ), तारीख 22.06.2010]
23.	30/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 536 (अ), तारीख 22.06.2010]
24.	28/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 534 (अ), तारीख 22.06.2010]
25.	27/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 533 (अ), तारीख 22.06.2010]
26.	25/2010-सेवा कर, तारीख 22.06.2010 [सा.का.नि. 531 (अ), तारीख 22.06.2010]
27.	23/2010-सेवा कर, तारीख 29.04.2010 [सा.का.नि. 345 (अ), तारीख 29.04.2010]
28.	13/2010-सेवा कर, तारीख 27.02.2010 [सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 27.02.2010]
29.	12/2010-सेवा कर, तारीख 27.02.2010 [सा.का.नि. 156 (अ), तारीख 27.02.2010]
30.	11/2010-सेवा कर, तारीख 27.02.2010 [सा.का.नि. 155 (अ), तारीख 27.02.2010]
31.	10/2010-सेवा कर, तारीख 27.02.2010 [सा.का.नि. 154 (अ), तारीख 27.02.2010]
32.	08/2010-सेवा कर, तारीख 27.02.2010 [सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 27.02.2010]
33.	42/2009-सेवा कर, तारीख 12.11.2009 [सा.का.नि. 821 (अ), तारीख 12.11.2009]
34.	41/2009-सेवा कर, तारीख 23.10.2009 [सा.का.नि. 776 (अ), तारीख 23.10.2009]
35.	39/2009-सेवा कर, तारीख 23.09.2009 [सा.का.नि. 696 (अ), तारीख 23.09.2009]
36.	33/2009-सेवा कर, तारीख 01.09.2009 [सा.का.नि. 627 (अ), तारीख 01.09.2009]
37.	32/2009-सेवा कर, तारीख 01.09.2009 [सा.का.नि. 626 (अ), तारीख 01.09.2009]
38.	31/2009-सेवा कर, तारीख 01.09.2009 [सा.का.नि. 625 (अ), तारीख 01.09.2009]
39.	30/2009-सेवा कर, तारीख 31.08.2009 [सा.का.नि. 619 (अ), तारीख 31.08.2009]
40.	24/2009-सेवा कर, तारीख 27.07.2009 [सा.का.नि. 551 (अ), तारीख 27.07.2009]
41.	20/2009-सेवा कर, तारीख 07.07.2009 [सा.का.नि. 492 (अ), तारीख 07.07.2009]
42.	19/2009-सेवा कर, तारीख 07.07.2009 [सा.का.नि. 491 (अ), तारीख 07.07.2009]
43.	01/2009-सेवा कर, तारीख 05.01.2009 [सा.का.नि. 10 (अ), तारीख 05.01.2009]
44.	14/2008-सेवा कर, तारीख 01.03.2008 [सा.का.नि. 158 (अ), तारीख 01.03.2008]
45.	13/2008-सेवा कर, तारीख 01.03.2008 [सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 01.03.2008]
46.	34/2007-सेवा कर, तारीख 23.05.2007 [सा.का.नि. 387 (अ), तारीख 23.05.2007]

47.	33/2007-सेवा कर, तारीख 23.05.2007 [सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 23.05.2007]
48.	25/2007-सेवा कर, तारीख 22.05.2007 [सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 22.05.2007]
49.	12/2007-सेवा कर, तारीख 01.03.2007 [सा.का.नि. 166 (अ), तारीख 01.03.2007]
50.	11/2007-सेवा कर, तारीख 01.03.2007 [सा.का.नि. 165 (अ), तारीख 01.03.2007]
51.	10/2007-सेवा कर, तारीख 01.03.2007 [सा.का.नि. 164 (अ), तारीख 01.03.2007]
52.	08/2007-सेवा कर, तारीख 01.03.2007 [सा.का.नि. 162 (अ), तारीख 01.03.2007]
53.	22/2006-सेवा कर, तारीख 31.05.2006 [सा.का.नि. 328 (अ), तारीख 31.05.2006]
54.	06/2006-सेवा कर, तारीख 01.03.2006 [सा.का.नि. 120 (अ), तारीख 01.03.2006]
55.	04/2006-सेवा कर, तारीख 01.03.2006 [सा.का.नि. 118 (अ), तारीख 01.03.2006]
56.	01/2006-सेवा कर, तारीख 01.03.2006 [सा.का.नि. 115 (अ), तारीख 01.03.2006]
57.	29/2005-सेवा कर, तारीख 15.07.2005 [सा.का.नि. 477 (अ), तारीख 15.07.2005]
58.	21/2005-सेवा कर, तारीख 07.06.2005 [सा.का.नि. 363 (अ), तारीख 07.06.2005]
59.	17/2005-सेवा कर, तारीख 07.06.2005 [सा.का.नि. 359 (अ), तारीख 07.06.2005]
60.	08/2005-सेवा कर, तारीख 01.03.2005 [सा.का.नि. 142 (अ), तारीख 01.03.2005]
61.	34/2004-सेवा कर, तारीख 03.12.2004 [सा.का.नि. 789 (अ), तारीख 03.12.2004]
62.	33/2004-सेवा कर, तारीख 03.12.2004 [सा.का.नि. 788 (अ), तारीख 03.12.2004]
63.	29/2004-सेवा कर, तारीख 22.09.2004 [सा.का.नि. 632 (अ), तारीख 22.09.2004]
64.	24/2004-सेवा कर, तारीख 10.09.2004 [सा.का.नि. 598 (अ), तारीख 10.09.2004]
65.	17/2004-सेवा कर, तारीख 10.09.2004 [सा.का.नि. 591 (अ), तारीख 10.09.2004]
66.	14/2004-सेवा कर, तारीख 10.09.2004 [सा.का.नि. 588 (अ), तारीख 10.09.2004]
67.	13/2004-सेवा कर, तारीख 10.09.2004 [सा.का.नि. 587 (अ), तारीख 10.09.2004]
68.	16/2003-सेवा कर, तारीख 11.07.2003 [सा.का.नि. 542 (अ), तारीख 11.07.2003]
69.	14/2003-सेवा कर, तारीख 20.06.2003 [सा.का.नि. 505 (अ), तारीख 20.06.2003]
70.	13/2003-सेवा कर, तारीख 20.06.2003 [सा.का.नि. 504 (अ), तारीख 20.06.2003]
71.	12/2003-सेवा कर, तारीख 20.06.2003 [सा.का.नि. 503 (अ), तारीख 20.06.2003]
72.	10/2003-सेवा कर, तारीख 20.06.2003 [सा.का.नि. 501 (अ), तारीख 20.06.2003]
73.	18/2002-सेवा कर, तारीख 16.12.2002 [सा.का.नि. 823 (अ), तारीख 16.12.2002]
74.	16/2002-सेवा कर, तारीख 02.08.2002 [सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 02.08.2002]
75.	10/2002-सेवा कर, तारीख 01.08.2002 [सा.का.नि. (अ), तारीख 01.08.2002]
76.	04/2000-सेवा कर, तारीख 31.07.2000 [सा.का.नि. 643 (अ), तारीख 31.07.2000]
77.	03/2000-सेवा कर, तारीख 06.07.2000 [सा.का.नि. 588 (अ), तारीख 06.07.2000]
78.	02/2000-सेवा कर, तारीख 01.03.2000 [सा.का.नि. 210 (अ), तारीख 01.03.2000]
79.	22/1997-सेवा कर, तारीख 26.06.1997 [सा.का.नि. 348 (अ), तारीख 26.06.1997]
80.	12/1997-सेवा कर, तारीख 14.02.1997 [सा.का.नि. 74 (अ), तारीख 14.02.1997]
81.	03/1994-सेवा कर, तारीख 30.06.1994 [सा.का.नि. 555 (अ), तारीख 30.06.1994]

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2012-टॉआरसू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 34/2012-Service Tax

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such recession namely:-

TABLE

SL. NO. (1)	NOTIFICATION NO. AND DATE (2)
1.	06/2012- Service Tax, dated 17-03-2012.[G.S.R. 204(E), dated 17-03-2012]
2.	45/2011 - Service Tax, dated 12-09-2011.[G.S.R. 672(E), dated 12-09-2011]
3.	42/2011 - Service Tax, dated 25-07-2011.[G.S.R. 566(E), dated 25-07-2011]
4.	33/2011 - Service Tax, dated 25-04-2011.[G.S.R. 341(E) dated 25-04-2011]
5.	31/2011 - Service Tax, dated 25-04-2011.[G.S.R. 339(E) dated 25-04-2011]
6.	30/2011 - Service Tax, dated 25-04-2011.[G.S.R. 338(E) dated 25-04-2011]
7.	11/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011 [G.S.R 168(E) dated 01-03-2011]
8.	10/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011 .[G.S.R.167(E) dated 01-03-2011]
9.	09/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011. [G.S.R.166(E) dated 01-03-2011]
10.	08/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011. [G.S.R.165(E) dated 01-03-2011]
11.	07/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011. [G.S.R.164(E) dated 01-03-2011]
12.	06/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011. [G.S.R. 163(E) dated 01-03-2011]
13.	05/2011 - Service Tax, dated 01-03-2011. [G.S.R. 162(E) dated 01-03-2011]
14.	58/2010 - Service Tax, dated 21-12-2010. [G.S.R.996(E) dated 21-12-2010]
15.	53/2010 - Service Tax, dated 21-12-2010. [G.S.R.991(E) dated 21-12-2010]
16.	50/2010 - Service Tax, dated 08-10-2010. [G.S.R.823(E) dated 08-10-2010]
17.	47/2010 - Service Tax, dated 03-09-2010. [G.S.R 727(E) dated 03-09-2010]
18.	42/2010 - Service Tax, dated 28-06-2010. [G.S.R.563(E) dated 28-06-2010]
19.	41/2010 - Service Tax, dated 28-06-2010. [G.S.R.562(E) dated 28-06-2010]
20.	38/2010 - Service Tax, dated 28-06-2010. [G.S.R.559(E) dated 28-06-2010]
21.	32/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R.538(E) dated 22-06-2010]
22.	31/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R.537(E) dated 22-06-2010]
23.	30/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R.536(E) dated 22-06-2010]
24.	28/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R.534(E) dated 22-06-2010]
25.	27/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R.533(E) dated 22-06-2010]
26.	25/2010 - Service Tax, dated 22-06-2010. [G.S.R. 531(E)dated 22-06-2010]
27.	23/2010 - Service Tax, dated 29-04-2010. [G.S.R.345(E) dated 29-04-2010]
28.	13/2010 - Service Tax, dated 27-02-2010. [G.S.R.157(E) dated 27-02-2010]
29.	12/2010 - Service Tax, dated 27-02-2010. [G.S.R.156(E) dated 27-02-2010]
30.	11/2010 - Service Tax, dated 27-02-2010. [G.S.R.155(E) dated 27-02-2010]
31.	10/2010 - Service Tax, dated 27-02-2010. [G.S.R.154(E) dated 27-02-2010]
32.	08/2010 - Service Tax, dated 27-02-2010. [G.S.R.152(E) dated 27-02-2010]
33.	42/2009 - Service Tax, dated 12-11-2009. [G.S.R.821(E) dated 12-11-2009]

34.	41/2009 - Service Tax, dated 23-10-2009. [G.S.R.776(E) dated 23-10-2009]
35.	39/2009 - Service Tax, dated 23-09-2009. [G.S.R.696(E) dated 23-09-2009]
36.	33/2009- Service Tax, dated 1-9-2009. [G.S.R.627(E) dated 1-9-2009]
37.	32/2009 - Service Tax, dated 1-09-2009. [G.S.R.626(E) dated 1-9-2009]
38.	31/2009 - Service Tax, dated 1-09-2009. [G.S.R.625(E) dated 1-9-2009]
39.	30/2009 - Service Tax, dated 31-08-2009. [G.S.R.619(E) dated 31-08-2009]
40.	24/2009- Service Tax, dated 27-7-2009. [G.S.R.551(E) dated 27-7-2009]
41.	20/2009 - Service Tax, dated 07-07-2009. [G.S.R.492(E) dated 07-07-2009]
42.	19/2009 - Service Tax, dated 07-07-2009. [G.S.R.491(E) dated 07-07-2009]
43.	01/2009 - Service Tax, dated 05-01-2009. [G.S.R.10(E) dated 05-01-2009]
44.	14/2008 - Service Tax, dated 01-03-2008. [G.S.R.158(E) dated 01-03-2008]
45.	13/2008- Service Tax, dated 01-03-2008. [G.S.R.157(E) dated 01-03-2008]
46.	34/2007 - Service Tax, dated 23-05-2007. [G.S.R.387(E) dated 23-05-2007]
47.	33/2007 - Service Tax, dated 23-05-2007. [G.S.R.386(E) dated 23-05-2007]
48.	25/2007- Service Tax, dated 22-05-2007. [G.S.R.371(E) dated 22-05-2007]
49.	12/2007- Service Tax dated 01-03-2007. [G.S.R.166(E) dated 01-03-2007]
50.	11/2007- Service Tax dated 01-03-2007. [G.S.R.165(E) dated 01-03-2007]
51.	10/2007- Service Tax dated 01-03-2007. [G.S.R.164(E) dated 01-03-2007]
52.	08/2007- Service Tax dated 01-03-2007. [G.S.R.162(E) dated 01-03-2007]
53.	22/2006- Service Tax, dated 31-05-2006. [G.S.R.328(E) dated 31-05-2006]
54.	06/2006- Service Tax, dated 01-03-2006. [G.S.R.120(E) dated 01-03-2006]
55.	04/2006- Service Tax, dated 01-03-2006. [G.S.R.118(E) dated 01-03-2006]
56.	01/2006- Service Tax, dated 01-03-2006. [G.S.R.115(E) dated 01-03-2006]
57.	29/2005- Service Tax, dated 15-07-2005. [G.S.R.477(E) dated 15-07-2005]
58.	21/2005- Service Tax, dated 07-06-2005. [G.S.R.363(E) dated 07-06-2005]
59.	17/2005- Service Tax, dated 07-06-2005. [G.S.R.359(E) dated 07-06-2005]
60.	08/2005- Service Tax, dated 01-03-2005. [G.S.R.142(E) dated 01-03-2005]
61.	34/2004- Service Tax, dated 03-12-2004. [G.S.R.789(E) dated 03-12-2004]
62.	33/2004- Service Tax, dated 3-12-2004. [G.S.R.788(E) dated 3-12-2004]
63.	29/2004- Service Tax, dated 22-09-2004. [G.S.R.632(E) dated 22-09-2004]
64.	24/2004- Service Tax, dated 10-09-2004. [G.S.R.598(E) dated 10-09-2004]
65.	17/2004- Service Tax, dated 10-09-2004. [G.S.R.591(E) dated 10-09-2004]
66.	14/2004- Service Tax, dated 10-09-2004. [G.S.R.588(E) dated 10-09-2004]
67.	13/2004- Service Tax, dated 10-09-2004. [G.S.R.587(E) dated 10-09-2004]
68.	16/2003- Service Tax, dated 11-07-2003. [G.S.R.542(E) dated 11-07-2003]
69.	14/2003- Service Tax, dated 20-06-2003. [G.S.R.505(E) dated 20-06-2003]
70.	13/2003- Service Tax, dated 20-06-2003. [G.S.R.504(E) dated 20-06-2003]
71.	12/2003- Service Tax, dated 20-06-2003. [G.S.R.503(E) dated 20-06-2003]
72.	10/2003- Service Tax, dated 20-06-2003. [G.S.R.502(E) dated 20-06-2003]
73.	18/2002- Service Tax, dated 16-12-2002. [G.S.R.823(E) dated 16-12-2002]
74.	16/2002- Service Tax, dated 02-08-2002. [G.S.R.546(E) dated 02-08-2002]
75.	10/2002- Service Tax, dated 01-08-2002. [G.S.R.538(E) dated 01-08-2002]
76.	4/2000- Service Tax, dated 31-07-2000. [G.S.R.643(E) dated 31-07-2000]
77.	3/2000- Service Tax, dated 06-07-2000. [G.S.R.588(E) dated 06-07-2000]

78.	2/2000- Service Tax, dated 01-03-2000. [G.S.R.210(E) dated 01-03-2000]
79.	22/1997- Service Tax, dated 26-06-1997. [G.S.R. 348(E) dated 26-06-1997]
80.	12/1997- Service Tax, dated 14-02-1997. [G.S.R.74(E) dated 14-02-1997]
81.	03/1994- Service Tax, dated 30-06-1994. [G.S.R.555(E) dated 30-06-1994]

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 35/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 477(अ)।—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 और धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2007-सेवा कर, तारीख 22 मई, 2007 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 378 (अ), तारीख 22 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिनका किए जाने से लोप किया गया था।

2. यह अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरस्य]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 35/2012-Service Tax

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/ 2007 – Service Tax, dated the 22nd May, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide number G.S.R. 378(E), dated the 22nd May 2007, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 36/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 478(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) (32 का 1994) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेवा कर नियमावली, 1994 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, नामशः—

1. (1) ये नियम, सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 कहे जा सकेंगे।
- (2) ये जुलाई, 2012 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।
2. सेवाकर नियमावली, 1994 में (जिन्हें इसके बाद मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में,-

(i) उप खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित तीन उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः—
“(खख) “बैंकिंग कंपनी” का वही अर्थ है, जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में आबंटित किया गया है;

“(खग) “निकाय कारपोरेट” का वही अर्थ है, जो इसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (7) में आबंटित किया गया है;

“(खघ) “वित्तीय संस्थाओं” का वही अर्थ है, जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I के खंड (ग) में आबंटित किया गया है;

(ii) उप खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः—
“(गक) “मालवाहक” का वही अर्थ है, जो इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (14) में आबंटित किया गया है;

(iii) उप खंड (गख) के बाद, निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः—
“(गखक) “बीमा एजेंट” का वही अर्थ है, जो इसे बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (10) में आबंटित किया गया है;

(iv) उप खंड (गग) के बाद, निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः—
“(गखक) “जीवन बीमा व्यवसाय” का वही अर्थ है, जो इसे बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (11) में आबंटित किया गया है;

(v) उप खंड (गख) के बाद, निम्नलिखित तीन उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः—“(गड) “प्रावधान का स्थान” वह स्थान होगा जो सेवाकर नियमावली 2012 के द्वारा प्रावधान के स्थान के रूप में निर्धारित किया जाए;

“(खच) “गैर-वित्तीय संस्थाओं” का वही अर्थ है, जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I के खंड (च) में आवंटित किया गया है;

(vi) उप धारा (घ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः—

“(घ) “सेवाकर अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति”, -

(i) अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के तहत अधिसूचित कराधेय सेवाओं के संदर्भ में, का तात्पर्य:-

(क) बीमा कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति को किसी किसी बीमा एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संदर्भ में, सेवा का प्राप्तकर्ता।

(ख) किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा सड़क से माल के परिवहन के संबंध में उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा, जहां भाड़ा अदा करने वाला व्यक्ति है,—

(I) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के तहत पंजीकृत या अभिशासित कोई कारखाना;

(II) भारत के किसी भी भाग में समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)

या उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत या अभिशासित कोई कारखाना;

(III) किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई सहकारी समिति;

(IV) उत्पादशुल्केय किसी माल का डीलर, जो केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन किसी नियम के तहत पंजीकृत है;

(V) किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निकाय निगम;

(VI) कोई साझेदारी फर्म चाहे वह किसी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं जिसमें व्यक्तियों के एसोसिएशन शामिल हैं; एन.पी. कोई व्यक्ति जो किसी मालवाहक में सड़क मार्ग से ऐसे माल के परिवहन के लिए खुद अर्थवा अपने एजेंट के माध्यम से भाड़ा अदा करता है या अदा करने का जिम्मेदार है।

बशर्ते ऐसी सेवा का प्रदाता यदि ऐसा व्यक्ति किसी गैर-कराधेय क्षेत्र में स्थित है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी ऐसी सेवा का प्रदाता ।

(ग) प्रायोजन के माध्यम से कराधेय क्षेत्र में स्थित किसी निगम या साझेदारी फर्म को उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संदर्भ में, सेवा का प्राप्तकर्ता;

(घ) मध्यस्थिता अधिकरण या किसी निजी वकील द्वारा कराधेय क्षेत्र में स्थित किसी कारोबारी संगठन को उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संदर्भ में, सेवा का प्राप्तकर्ता;

(ङ.) अचल संपत्ति को छोड़कर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कराधेय क्षेत्र में स्थित किसी कारोबारी संगठन को उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संदर्भ में, सेवा का प्राप्तकर्ता;

(च) निम्नलिखित तरीके से उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवाओं के संदर्भ में :-

(क) यात्रियों को ढोने के लिए बनी कोई मोटरवाहन किसी ऐसे व्यक्ति को किराए पर देना जो ऐसे ही कारोबार में संलग्न नहीं है, या

(ख) किसी प्रयोजन के लिए जनशक्ति की आपूर्ति, या

(ग) निर्माण संविदा के निष्पादन में सेवा भाग-

किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या साझेदारी फर्म, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, जिसमें कराधेय क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के एसोसिएशन शामिल हैं, द्वारा किसी जिसमें कराधेय क्षेत्र में स्थित कारोबारी संगठन को जो निकाय निगम के रूप में पंजीकृत है, अर्थात् सेवा प्राप्तकर्ता और सेवा प्रदाता, दोनों, अधिनियम की धारा (68) की उपधारा (2) के तहत अधिसूचित सीमा तक, क्रमशः प्रत्येक के लिए।

(ङ.) किसी गैर-कराधेय क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त और कराधेय क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति को प्राप्त उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संदर्भ में, का तात्पर्य है सेवा का प्राप्तकर्ता;

(ii) उप खंड (i) से इतर किसी मामले में, सेवा प्रदाता है।";

(vii) उप खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः-

"(घघ) "अचल संपत्ति का अवधारण" का अर्थ अचल संपत्ति का अवधारण करके उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा या ऐसे अवधारण के संबंध में कोई सेवा है।"

(viii) उप खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित उप खंड जोड़े जाएंगे, नामशः-

"(च) "जनशक्ति की आपूर्ति" का अर्थ अस्थायी रूप से या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को उसके अधीन या अधीक्षण में काम कराने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति है।"

3. मूल नियमावली के नियम 4 में, उप नियम (1) में, जहां कहीं भी शब्द और अक्षर "धारा 66", आएंगे, उन्हें शब्दों और अक्षरों "धारा 66ख" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
4. मूल नियमावली की धारा 4क में,-

(A) उप नियम (1) में,-

(i) “उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने वाले” शब्दों को, “उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराने के लिए सहमत” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप खंड (iii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“(iii) उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा का विवरण और मूल्य; तथा”;

(iii) प्रथम परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“शर्त यह है कि यदि कराधेय सेवा का प्रदाता कोई बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्था है जो किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान कर रही है, तो यथा मामला कोई बीजक, या बिल अथवा चालान में कोई प्रलेख जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, क्रम संख्या डाली गयी हो या नहीं, चाहे कराधेय सेवा प्राप्तकर्ता व्यक्ति का पता डाला गया हो या नहीं लेकिन इस उप नियम के तहत अपेक्षित अन्य सूचनाएं ऐसे प्रलेख में शामिल हों :”;

(iv) चौथे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“यह भी शर्त यह है कि यदि कराधेय सेवा का प्रदाता कोई बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्था हो जो किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान कर रही हो, तो जिस अवधि में यथा मामला बीजक, बिल या चालान जारी किया जाएगा, वह पेंतालिस दिन होगा:”;

(v) पांचवे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“शर्त यह है कि यदि कराधेय सेवा का प्रदाता यात्रियों के परिवहन की सेवा प्रदान कर रही है, तो यथा मामला कोई बीजक, या बिल अथवा चालान में किसी भी स्वरूप में टिकट शामिल होगा चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, सेवा प्रदाता की पंजीकरण संख्या तथा सेवा प्राप्तकर्ता व्यक्ति का पता डाला गया हो या नहीं लेकिन इस उप नियम के तहत अपेक्षित अन्य सूचनाएं ऐसे प्रलेख में शामिल हों :”;

(x) उप नियम (2) में, प्रथम परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:-

“शर्त यह है कि यदि निविष्ट सेवा का वितरक बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्था का कोई कार्यालय है जो किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान कर रही है, तो यथा मामला कोई बीजक, या बिल अथवा चालान में कोई प्रलेख जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, क्रम संख्या डाली गयी हो या नहीं, लेकिन इस उप नियम के तहत अपेक्षित अन्य सूचनाएं ऐसे प्रलेख में शामिल हों :”;

5. मूल नियमावली के नियम 5 में, उप नियम (2) में, खंड (i) में उप खंड (क) में “निम्न प्रतिस्थापित अर्थात्:- (क) किसी सेवा का प्रदाता;
6. मूल नियमावली के नियम 5(ख) को छोड़ दिया जाएगा;
7. मूल नियमावली के नियम 6 में,-

- (1) उप नियम (1) में,-

(i) तीसरे परंतुक को छोड़ दिया जाएगा;
 (ii) इस प्रकार संशोधित तीसरे परंतुक के बाद, चौथे परंतुक में, “उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने वाले” शब्दों को, “उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराने के लिए सहमत” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (2) उप नियम (4ख) में, शब्दों और मदों “वर्गीकरण” को छोड़ दिया जाएगा;

- (3) उप नियम (4ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“(4ग) उप नियम (4), (4क) और (4ख) में किसी बात के होते हुए भी, चाहे अचल संपत्ति का अवधारण करने की सेवा के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने यथा मामला किसी महीने या तिमाही में अधिसूचना संख्या @@@-सेवाकर, दिनांक t@@@ के निबंधनों के तहत उस अवधि में संपत्ति के अवधारण के लिए दिए जाने वाले कुल प्रभार से संपत्ति कर में कटौती न मिलने के कारण, केंद्र सरकार की साथ में कर दायित्व से अधिक भुगतान कर दिया हो, तो वह ऐसे संपत्ति कर के भुगतान से एक साल के भीतर अपने सेवाकर दायित्व से अधिक किए गए भुगतान को समायोजित करा सकता है और ऐसे समायोजन के ब्यौरे ऐसे समायोजन के घंट्रह दिन के भीतर उस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को सूचित किए जाएंगे, जिसका सेवा प्रदाता पर क्षेत्राधिकार है।”;

- (4) उप नियम (7-क) में, “एयर ट्रेल एजेंट” शब्दों के बाद, “हवाई यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग” शब्द प्रविष्ट किए जाएंगे तथा शब्दों और अक्षरों “धारा 66”, को शब्दों और अक्षरों “धारा 66ख” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (5) उप नियम (7क) में, जहां कहीं भी शब्द और अंक “धारा 66”, आएंगे, उन्हें शब्दों और अंक “धारा 66ख” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (6) उप नियम (7ख) ये कोष्ठक से आरंभ होने वाले अंश के लिए अंकों, अक्षरों तथा शब्द, (7ख) भुगतान हेतु जिम्मेवार व्यक्ति तथा अधिनियम के अध्याय V के साथ समाप्त होने वाले शब्दों तथा अंकों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

“(7B) धन परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास इस अधिनियम के धारा 66ख में विनिर्दिष्ट दरों पर सेवाकर अदा करने के बजाय सेवाकर दायित्व निभाने की दिशा में निम्नलिखित दरों पर संगणित धनराशि के बराबर अदा करने का विकल्प होगा।”

(7) उप नियम (7ग) में,-

(i) कोष्ठक, अंकों शब्दों से आरम्भ होने वाले अंश "(7ग) वितरक" से शुरू और "कथित अधिनियम के अध्याय V की धारा 66:" से समाप्त होने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

"(7ग) लॉटरी के संवर्धन, विपणन, संगठन या किसी और तरीके से सहायता करने वाले सेवाकर अदा करने के लिए जिम्मेदार वितरक, बिक्री एजेंट के पास इस अधिनियम के अध्याय V की धारा 66ख में विनिर्दिष्ट दरों पर सेवाकर अदा करने के बजाय नीचे की सारणी 2 में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त सारणी के कॉलम (3) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धनराशि अदा करने का विकल्प होगा:"

(ii) तीसरे परंतुक में, "कथित उप खंड के तहत सेवा" शब्दों को, "ऐसी सेवा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8. मूल नियमावली की नियम 6 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, नामश:-

"नियम 6क. सेवाओं का निर्यात: (1) उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध कराने के लिए सहमत किसी सेवा को सेवा का निर्यात माना जाएगा, जब,-

- (क) सेवा प्रदाता कराधीय क्षेत्र में स्थित हो, और
- (ख) सेवा प्रदाता भारत के बाहर स्थित हो; और
- (ग) उस सेवा का नकारात्मक सूची में उल्लेख नहीं है; और
- (घ) सेवा के प्रावधान का स्थान भारत के बाहर स्थित है; और
- (ङ.) ऐसी सेवा का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है, और
- (च) सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता इस अधिनियम की धारा 65ख के धारा 44 की व्याख्या 2 की मट संख्या 2 के नजरिए से किसी सुस्पष्ट व्यक्ति की केवल स्थापनाएं नहीं हैं

(2) जब किसी सेवा का निर्यात किया जाता है, केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा यथा मामला उपलब्ध करायी गयी सेवा में प्रयुक्त निविष्टि सेवाओं या निविष्टियों को छूट दे सकती है तथा ऐसी छूट ऐसे रक्षोपायों, शर्तों और सीमाओं की अधीन होगी, जो केंद्र सरकार अधिसूचना से विनिर्दिष्ट करे।"

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.2/94-सेवाकर, दिनांक 28 जून, 1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.आ.546 (अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत प्रकाशित किया गया था और इससे अंतिम संशोधन सा.का.आ. 201 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2012-सेवाकर, दिनांक 17 मार्च, 2012 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 36/2012-Service Tax

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2012.
2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
 - (i) after sub-clause (b), the following three sub-clauses shall be inserted, namely:—
“(bb) “banking company” has the meaning assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
“(bc) “body corporate” has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
“(bd) “financial institution” has the meaning assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);”
 - (ii) after sub-clause (c), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
“(c1a) “goods carriage” has the meaning assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);”
 - (iii) after sub-clause (cb), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
“(cba) “insurance agent” has the meaning assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);”
 - (iv) after sub-clause (cc), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

‘(cca)“legal service” means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority;

(ccb) “life insurance business” has the meaning assigned to it in clause (11) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(ccc) “non banking financial company” has the meaning assigned to it in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(v) for sub-clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“(d) “person liable for paying service tax”, -

(i) in respect of the taxable services notified under sub-section (2) of section 68 of the Act, means,-

(A) in relation to service provided or agreed to be provided by an insurance agent to any person carrying on the insurance business, the recipient of the service.

(B) in relation to service provided or agreed to be provided by a goods transport agency in respect of transportation of goods by road, where the person liable to pay freight is,—

(I) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948 (63 of 1948);

(II) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India;

(III) any co-operative society established by or under any law;

(IV) any dealer of excisable goods, who is registered under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder;

(V) any body corporate established, by or under any law; or

(VI) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons;

~~any person who pays or is liable to pay freight either himself or through his agent for the transportation of such goods by road in a goods carriage:~~

Provided that when such person is located in a non-taxable territory, the provider of such service shall be liable to pay service tax.

- (C) in relation to service provided or agreed to be provided by way of sponsorship to anybody corporate or partnership firm located in the taxable territory, the recipient of such service;
- (D) in relation to service provided or agreed to be provided by,-
 - (I) an arbitral tribunal, or
 - (II) an individual advocate or a firm of advocates by way of legal services, to any business entity located in the taxable territory, the recipient of such service;
- (E) in relation to support services provided or agreed to be provided by Government or local authority except,-
 - (a) renting of immovable property, and
 - (b) services specified sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994,
to any business entity located in the taxable territory, the recipient of such service;
- (F) in relation to services provided or agreed to be provided by way of :
 - (a) renting of a motor vehicle designed to carry passengers, to any person who is not engaged in a similar business; or
 - (b) supply of manpower for any purpose; or
 - (c) service portion in execution of a works contract-
by any individual, Hindu Undivided Family or partnership firm, whether registered or not, including association of persons, located in the taxable territory to a business entity registered as a body corporate, located in the taxable territory, both the service provider and the service recipient to the extent notified under sub-section (2) of section 68 of the Act, for each respectively.
- (G) in relation to any taxable service provided or agreed to be provided by any person which is located in a non-taxable territory and received by any person located in the taxable territory, the recipient of such service;

(ii) in a case other than sub-clause (i), means the provider of service.”

(vi) after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

‘(dd) “place of provision” shall be the place, as determined by Place of Provision of Services Rules 2012;’

(vii) after sub-clause (e), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

‘(f) “renting of immovable property” means any service provided or agreed to be provided by renting of immovable property or any other service in relation to such renting.

‘(g) “supply of manpower” means supply of manpower, temporarily or otherwise, to another person to work under his superintendence or control.’

3. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (1), for the word and figures “section 66”, the word, figures and letter “section 66B” shall be substituted;
4. In the principal rules, in rule 4A,—
 - (A) in sub-rule (1),—
 - (i) for the words “provided or to be provided”, the words “provided or agreed to be provided” shall be substituted;
 - (ii) for clause (iii), the following shall be substituted, namely:—
“(iii) description and value of taxable service provided or agreed to be provided; and”,
 - (iii) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that in case the provider of taxable service is a banking company or a financial institution including a non-banking financial company providing service to any person, an invoice, a bill or, as the case may be, challan shall include any document, by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing address of the person receiving taxable service but containing other information in such documents as required under this sub-rule :”;
 - (iv) for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided also that in case the provider of taxable service is a banking company or a financial institution including a non-banking financial company

providing service to any person, the period within which the invoice, bill or challan, as the case may be, is to be issued, shall be forty-five days:”;

(v) for the fifth proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in case the provider of taxable service is providing the service of transport of passenger, an invoice, a bill or as the case may be, challan shall include ticket in any form by whatever name called and whether or not containing registration number of the provider of service and address of the recipient of service but containing other information in such documents as required under this sub-rule”;

(B) in sub-rule (2), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that in case the input service distributor is an office of a banking company or a financial institution including a non-banking financial company providing service to any person an invoice, a bill or, as the case may be, challan shall include any document, by whatever name called, whether or not serially numbered but containing other information in such documents as required under this sub-rule:”;

5. In the principal rules, in rule 5, in sub-rule (2), in clause (i), for sub-clause (a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) providing of any service;”

6. In the principal rules, rule 5B, shall be omitted;

7. In the principal rules, in rule 6,-

(1) in sub-rule (1),-

(i) the third proviso shall be omitted;

(ii) after the third proviso as so amended, in the fourth proviso, for the words “provided or to be provided”, the words “provided or agreed to be provided” shall be substituted;

(2) in sub-rule (4B), the word “classification,” shall be omitted;

(3) for sub-rule (4C), the following shall be substituted, namely:-

“(4C) Notwithstanding anything contained in sub-rules (4), (4A) and (4B), where the person liable to pay service tax in respect of service of renting of

immovable property has paid to the credit of Central Government any amount in excess of the amount required to be paid towards service tax liability for a month or quarter, as the case may be, on account of non-availment of deduction of property tax paid in terms of notification No. 29/2012-Service Tax , dated the 20th June, 2012, from the gross amount charged for renting of the immovable property for the said period at the time of payment of service tax, the assessee may adjust such excess amount paid by him against his service tax liability within one year from the date of payment of such property tax and the details of such adjustment shall be intimated to the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the service provider within a period of fifteen days from the date of such adjustment.”;

- (4) in sub-rule (7),-
 - (a) after the words “to the services”, the words “of booking of tickets for travel by air” shall be inserted;
 - (b) for the word and figures “section 66”, the word, figures and letter “section 66B” shall be substituted;
- (5) in sub rule (7A), for the word and figures “section 66”, the word, figures and letter “section 66B” shall be substituted;
- (6) in sub-rule (7B), for the portion beginning with the brackets, figure, letter and words, “(7B) The person liable to pay” and ending with the words and figures “Chapter V of the Act, namely :”, the following shall be substituted, namely:-

“(7B) The person liable to pay service tax in relation to purchase or sale of foreign currency, including money changing, shall have the option to pay an amount calculated at the following rate towards discharge of his service tax liability instead of paying service tax at the rate specified in section 66B of Chapter V of the Act, namely :”
- (7) in the sub-rule (7C),-
 - (i) for the portion beginning with the brackets, figure, letter and words, “(7C) The distributor” and ending with the words, figures and letters “section 66 of Chapter V of the said Act:”, the following shall be substituted, namely:-

“(7C) The distributor or selling agent, liable to pay service tax for the taxable service of promotion, marketing, organising or in any other manner assisting in organising lottery, shall have the option to pay an amount at the rate specified in column (2) of the Table given below, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, instead of paying service tax at the rate specified in section 66B of Chapter V of the said Act :—

(ii) in the third proviso, for the words “service under the said sub-clause”, the words “such service” shall be substituted;

8. In the principal rules, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

“RULE 6A. Export of services.— (1) The provision of any service provided or agreed to be provided shall be treated as export of service when,

- (a) the provider of service is located in the taxable territory ,
- (b) the recipient of service is located outside India,
- (c) the service is not a service specified in the section 66D of the Act,
- (d) the place of provision of the service is outside India,
- (e) the payment for such service has been received by the provider of service in convertible foreign exchange, and
- (f) the provider of service and recipient of service are not merely establishments of a distinct person in accordance with item (b) of Explanation 2 of clause (44) of section 65B of the Act

(2) Where any service is exported, the Central Government may, by notification, grant rebate of service tax or duty paid on input services or inputs, as the case may be, used in providing such service and the rebate shall be allowed subject to such safeguards, conditions and limitations, as may be specified, by the Central Government, by notification.”

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 2/94-ST, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and was last amended by notification No. 3/2012-Service Tax, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R. 201 (E), dated the 17th March, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 37/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (कक) और (जजज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कराधान बिन्दु नियम, 2011 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम, 2012 है।
(ख) ये तारीख 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे।
2. कराधान बिन्दु नियम, 2011 में,—
(क) नियम 2 में, उपनियम (ख) और (च) का लोप किया जायेगा।
(ख) शब्द “उपलब्ध या उपलब्ध कराया जाना चाहिए” जहां कहीं भी है, के स्थान पर शब्द “उपलब्ध या सहमति से उपलब्ध कराया जाना चाहिए” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]
राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 18/2011-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 175 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2012-सेवाकर, तारीख 17 मार्च, 2012 सा.का.नि. 202 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 37/2012-Service Tax

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (hh) of sub- section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Point of Taxation Rules, 2011, namely:—

1. (a) These rules may be called the Point of Taxation (Amendment) Rules, 2012.
(b) They shall come into force on the 1st day of July, 2012.

2. In the Point of Taxation Rules, 2011,-

- (a) in rule 2, sub-rules (b) and (f) shall be omitted.
- (b) for the words, “provided or to be provided” wherever they occur, the words “provided or agreed to be provided” shall be substituted.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 18/2011 - Service Tax, dated 1-3-2011 vide number G.S.R. 175 (E), dated the 1st March, 2011 and was last amended by notification No. 4/2012-Service Tax, dated the 17th March, 2012[G.S.R.202 (E), dated the 17th March, 2012].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 38/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 तथा 94 द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2011-सेवा कर, तारीख 1 अप्रैल, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 293 (अ), तारीख, 1 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षर “वित्त अधिनियम की धारा 65 (105) के खंडों में निर्दिष्ट (यथ), (यथयज), (यथयभ), (यथयप) और (यथययक)” के स्थान पर “दूरसंचार सेवा और कार्य संविद् सेवा के भाग में निर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना 28/2011-सेवा कर, तारीख 1 अप्रैल, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 293 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 38/2012-Service Tax

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.28/2011-Service Tax, dated the 1st April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 293(E), dated the 1st April, 2011, namely:—

In the said notification, for the words, brackets, letters and figures “referred to in clauses (zzq), (zzzh), (zzzx), (zzzu) and (zzzza) of section 65(105) of the Finance Act” the words “of telecommunication service and service portion in execution of a works contract” shall be substituted.

2. This notification shall come into force come into force from the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 28/2011 - Service Tax, dated 1st April, 2011 vide number G.S.R. 293 (E), dated the 1st April, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 39/2012-सेवा कर

साकानि. 481(अ) सेवाकर नियमावली, 1994 (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से सन्दर्भित किया गया है) के नियम 6 के में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि नेपाल और भूटान के अलावा किसी भी अन्य देश को उत्पाद शुल्केय आदानों पर भुगतान किये गये सम्पूर्ण शुल्क से या सभी आदान सेवाओं ((एतश्मिन् पश्चात् जिसे आदान सेवाओं से सन्दर्भित किया गया है) पर भुगतान किये गये सम्पूर्ण सेवाकर या उपकर, जिनका प्रयोग उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निर्यातित सेवा को बदान करने में किया गया है, से एतश्मिन् पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों, सीमाओं और प्रक्रियाओं के अधीन, छूट प्रदान करती है,

यथा:-

2. शर्तें और सीमाएँ:-

(क) कि सेवा को उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निर्यातित किया गया है।

(ख) कि आदानों पर शुल्क, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया है।

बशर्ते कि यदि व्यक्ति किसी आदान सेवा के लिए भुगतान करने के लिए स्वयं दायी है तो उसे सेवाकर और उपकर का भुगतान केवल सरकार को करना चाहिये था।

(ग) अनुजेय शुल्क, सेवाकर उपकर से छूट की कुल राशि एक हजार रुपये से कम नहीं है।

(घ) जिस आदान और आदान सेवा पर छूट का दावा किया गया है उस पर कोई सेनेट क्रेडिट न लिया गया हो।

(इ.) कि यदि:-

- (i) शुल्क या, जैसी भी स्थिति हो, सेवाकर और उपकर, जिसपर छूट का दावा किया गया है, का भुगतान नहीं किया गया है; या
- (ii) सेवा, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, का निर्यात नहीं हुआ है; या
- (iii) आदानों या आदान सेवाओं, जिनपर छूट का दावा किया गया है, पर सेनेट क्रेडिट प्राप्त कर लिया गया है, तो दी गई छूट, यदि कोई हो, ब्याज समेत, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73 और धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार, वापस ली जा सकती है।

3. प्रक्रिया

3.1 घोषणा करना- निर्यात की जाने वाली सेवा का प्रदाता, सेवा के निर्यात की तारीख से पहले, क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ अपनी घोषणा दर्ज करायेगा जिसमें सेवा, जिसका कि निर्यात किया जाना है, के बारे में निम्नलिखित विवरण देगा-

(क) आदानों, जिसका कि निर्यात की जाने वाली सेवा को प्रदान करने में वास्तव में प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी, का विवरण, मात्रा, मूल्य, शुल्क की दर और शुल्केय राशि :

(ख) आदान सेवाओं, जिसका निर्यात की जाने वाली सेवा को प्रदान करने में प्रयोग करने की वास्तव में जरूरत पड़ेगी, का विवरण, मूल्य और भुगतान योग्य सेवाकर या उपकर की राशि।

3.2 घोषणा का सत्यापन - सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, यदि जरूरी हुआ तो, ऐसी सेवा के निर्यात के पहले दर्जे की गई घोषणा का, कोई सुसंगत जानकारी मांग कर या आदानों का नमूना लेकर सत्यापन करेगा और यदि ऐसे सत्यापन के बाद सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, या उपायुक्त, सीमा शुल्क इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इसमें शुल्क या, जैसी भी स्थिति हो, सेवाकर और उपकर के अपवंचन की कोई संभावना नहीं है, तो वह घोषणा को स्वीकार कर सकता है।

3.3 आदान सामग्री की अधिप्राप्ति और आदान सेवाओं की प्राप्ति निर्यात की जाने वाली सेवा का प्रदाता :-

(I) निर्यात की जाने वाली सेवा को प्रदान करने में प्रयोग हेतु आवश्यक आदानों को, सीधे की कंपनी से या ऐसे किसी डीलर से, जो सेनेट क्रेडिट रुल्स, 2004 के प्रयोजनार्थ पंजीकृत है, प्राप्त कर सकेगा और साथ में ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के अंतर्गत जारी किये गये बीजक को भी प्राप्त कर सकेगा।

(II) आदान सेवाओं, जो कि निर्यात की जाने वाली सेवा को प्रदान करने में प्रयोग किये जाने के लिए आवश्यक है, और बीजक, या बिल या, जैसी भी स्थिति हो, चालान, जो कि सेवाकर नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया हो, को प्राप्त करेगा।

3.4 छूट के लिये दावा का प्रस्तुत किया जाना

क (i) आदानों पर भुगतान किये गये शुल्क पर या आदान सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवाकर या उपकर पर छूट के लिए दावा क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ, सेवाओं का निर्यात किये जाने के बाद, किया जा सकता है:

(ii) ऐसे आवेदन के साथ संलग्न होंगे-

(क) बीजक जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के अंतर्गत जारी किया गया है, या चालान सेवाओं का बिल या, जैसी भी स्थिति हो, चालान, जो कि सेवाकर नियमावली, 1994 के अंतर्गत जारी किया गया हो, जिनके बारे में छूट के लिए दावा किया गया है।

(ख) निर्यात की गई सेवा के एवज में किये गये भुगतान, आदानों पर शुल्क और आदान सेवाओं, जिनका निर्यातित सेवा को प्रदान करने में प्रयोग किया गया है, पर सेवाकर या उपकर, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, की प्राप्ति का दस्तावेजी प्रमाण;

(ग) यह घोषणा कि ऐसी सेवा को उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निर्यातित किया गया है, साथ में ही ऐसे निर्यात का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज।

(ख) क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, घोषणा पर ध्यान देने के बाद यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किया गया दावा सही है, पूर्ण या आंशिक छूट की स्वीकृति दे सकता है।

स्पष्टीकरण 1- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "सेवाकर या उपकर" से अभिप्राय,

(क) ऐसे सेवाकर से हैं जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66 या 66 ख के अंतर्गत लगाया जाता है;

(ख) कर योग्य सेवा पर लगाये जाने वाले उपकर से हैं जो कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 95 के साथ पठित धारा 91 के अंतर्गत लगाया जाता है, और

(ग) कर योग्य सेवाओं पर लगाये जाने वाले द्वितीयक या उच्च शिक्षा उपकर से हैं जिसे वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 के साथ पठित धारा 136 के अंतर्गत लगाया जाता है।

(घ) स्पष्टीकरण- 2 इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "शुल्क" से अभिप्राय ऐसे उत्पाद शुल्क से हैं जो निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत लगाया जाता है यथा:-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1)

(ख) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58)

(ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त निर्मित वस्तुएं), अधिनियम 1978 (1978 का 40)

(घ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क जिसे वित्त अधिनियम 2001 (2001 का 14), वित्त अधिनियम 2003 (2003 का 32) की धारा 169 के द्वारा यथा संशोधित, की धारा 136 के अंतर्गत, वित्त अधिनियम 2004 (2004 का 13) की धारा 3 के अंतर्गत और यथा और आगे संशोधित वित्त अधिनियम 2005 (2005 का 18) की धारा 123 के अंतर्गत लगाया जाता है।

(ङ) वित्त अधिनियम के अंतर्गत संग्रहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

(च) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे वित्त अधिनियम 2003 (2003 का 32) की धारा 157 के अंतर्गत लगाया जाता है।

(छ) उत्पाद शुल्क माल पर लगाया जाने वाला शिक्षा उपकर, जिसे वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 93 के साथ पठित धारा 91 के अंतर्गत लगाया जाता है।

(ज) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अंतर्गत लगाया जाता है।

(झ) उत्पाद शुल्केय माल पर लगाया जाने वाला द्वितीयक या उच्च शिक्षा उपकर जिसे वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 138 के साथ पठित धारा 136 के अंतर्गत लगाया जाता है।

अनुबंध

फार्म ए एस टी.आर- 2

(आदानों पर भुगतान किये गये शुल्क पर और आदान सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवाकर और उपकर पर हस्त के लिए दावा करने हेतु आवेदन)

(भाग क : आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

दिनांक :

स्थान :

सेवा में,

सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
(पूरा डाक पता)

महोदया/महोदय,

मैं/हम (दावा करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम), पंजीकरण सं.
अवस्थिति (पंजीकृत परिसर का पता) एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ करते हैं कि मैंने/हमने सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 के अंतर्गत को (देश का नाम जिसको सेवा का निर्यात किया गया है) सेवा (सेवा का नाम) का निर्यात किया है और सेवाकर जिसकी राशि (सेवाकर की राशि रूपये में) और शिक्षा उपकर जिसकी राशि (उपकर की राशि रूपये में) है का आदान पर भुगतान कर दिया है।

2. मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ करते हैं कि निर्यात की गई ऐसी सेवा के एवज में पूरा भुगतान (भुगतान की रसीद का व्यौरा) भारत में प्राप्त हो गया है।

3. मैं/हम यह अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं कि सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 के अंतर्गत मेरे/हमारे द्वारा निर्यातित सेवा को प्रदान करने मैं प्रयुक्त आदानों और आदान सेवाओं पर भुगतान किये गये शुल्क, सेवाकर और उपकर पर शीघ्रातिशीघ्र छूट प्रदान की जाय। छूट के लिए इस दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं—

- 1.
- 2.
- 3.

घोषणा -

(क) हम, एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमने आदान और आदान सेवा, जिस पर छूट का दावा किया गया है, पर कोई सेनेट क्रेडिट नहीं प्राप्त किया है।

(ख) हमें इसके लिए आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सी.सं. दिनांक के तहत अधिसूचना सं., दिनांक के अंतर्गत काम करने की अनुमति मिल गई है।

(सेवा प्रदाता या उसके प्राधिकृत एजेन्ट का हस्ताक्षर तथा नाम, दिनांक सहित)

(भाग ख : स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

छूट के दावे की प्रमिल्ली तारीख.....

छूट के दावे की स्वीकृति की तारीख

दावा किये गये छूट की राशि रुपये

स्वीकृत छूट की राशि रुपये

यदि दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के श्वेतर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो संक्षेप में इसके कारणों को दर्शाया जाय।

स्थानः

तारीखः

सहायक आयुक्त/ उपायुक्त,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का हस्ताक्षर

4- यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2012 से प्रवर्त्तन में आयेगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 39/2012-Service Tax

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby directs that there shall be granted rebate of the whole of the duty paid on excisable inputs or the whole of the service tax and cess paid on all input services (herein after referred to as 'input services'), used in providing service exported in terms of rule 6A of the said rules, to any country other than Nepal and Bhutan, subject to the conditions, limitations and procedures specified hereinafter,-

2. Conditions and limitations:-

- (a) that the service has been exported in terms of rule 6A of the said rules;
- (b) that the duty on the inputs, rebate of which has been claimed, has been paid to the supplier;
- (c) that the service tax and cess, rebate of which has been claimed, have been paid on the input services to the provider of service;

Provided if the person is himself is liable to pay for any input services; he should have paid the service tax and cess to the Central Government.

- (d) the total amount of rebate of duty, service tax and cess admissible is not less than one thousand rupees;
- (e) no CENVAT credit has been availed of on inputs and input services on which rebate has been claimed; and
- (f) that in case,-
 - (i) the duty or, as the case may be, service tax and cess, rebate of which has been claimed, has not been paid; or
 - (ii) the service, rebate for which has been claimed, has not been exported; or
 - (iii) CENVAT credit has been availed on inputs and input services on which rebate has been claimed,

the rebate paid, if any, shall be recoverable with interest in accordance with the provisions of section 73 and section 75 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)

3. Procedure.

3.1 Filing of Declaration.- The provider of service to be exported shall, prior to date of export of service, file a declaration with the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, specifying the service intended to be exported with,-

- (a) description, quantity, value, rate of duty and the amount of duty payable on inputs actually required to be used in providing service to be exported;
- (b) description, value and the amount of service tax and cess payable on input services actually required to be used in providing service to be exported.

3.2 Verification of declaration.- The Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall verify the correctness of the declaration filed prior to such export of service, if necessary, by calling for any relevant information or samples of inputs and if after such verification, the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise is satisfied that there is no likelihood of evasion of duty, or as the case may be, service tax and cess, he may accept the declaration.

3.3 Procurement of input materials and receipt of input services.- The provider of service to be exported shall,-

- (i) obtain the inputs required for use in providing service to be exported, directly

from a registered factory or from a dealer registered for the purposes of the CENVAT Credit Rules, 2004 accompanied by invoices issued under the Central Excise Rules, 2002;

(ii) receive the input services required for use in providing service to be exported and an invoice, a bill or, as the case may be, a challan issued under the provisions of Service Tax Rules, 1994.

3.4 Presentation of claim for rebate.—

(a) (i) claim of rebate of the duty paid on the inputs or the service tax and cess paid on input services shall be filed with the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, after the service has been exported;

(ii) such application shall be accompanied by,—

(a) invoices for inputs issued under the Central Excise Rules, 2002 and invoice, a bill, or as the case may be, a challan for input services issued under the Service Tax Rules, 1994, in respect of which rebate is claimed;

(b) documentary evidence of receipt of payment against service exported, payment of duty on inputs and service tax and cess on input services used for providing service exported, rebate of which is claimed;

(c) a declaration that such service, has been exported in terms of rule 6A of the said rules, along with documents evidencing such export.

(b) The jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having regard to the declaration, if satisfied that the claim is in order, shall sanction the rebate either in whole or in part.

Explanation 1.—For the purposes of this notification “service tax and cess” means,—

(a) service tax leviable under section 66 or section 66B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);

(b) education cess on taxable service levied under section 91 read with section 95 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004); and

(c) Secondary and Higher Education Cess on taxable services levied under section 136 read with section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007).

Explanation 2.—For the purposes of this notification “duty” means, duties of excise leviable under the following enactments, namely:-

(a) the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(b) the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

(c) the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);

(d) National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), as amended by section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), section 3 of the Finance Act, 2004 (13 of 2004) and further amended by section 123 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005);

(e) special duty of excise collected under a Finance Act;

(f) additional duty of excise as levied under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003);

(g) Education Cess on excisable goods as levied under section 91 read with section 93 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004); and

(h) the additional duty of excise leviable under section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005).

(i) the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under section 136 read with section 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007).

Annexure**FORM ASTR-2****(Application for filing a claim of rebate of duty paid on inputs, service tax and cess paid on input services)**

(PART A: To be filled by the applicant)

Date.....

Place.....

To,

Assistant Commissioner of Central Excise/Deputy Commissioner of Central Excise
..... (full postal address).

Madam/Sir,

I/We....., (name of the person claiming rebate) holding service tax registration No., located in.....
(address of the registered premises) hereby declare that I/We have exported
..... service (name of the service) under rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 to(name of the country to which service has been exported), and service tax amounting to (amount in rupees of service tax) and education cess amounting to (amount in rupees of cess) has been paid on input services and duty amounting to (amount in rupees of duty) has been paid on inputs.

2. I/We also declare that the payment against such service exported has already been received in India in full..... (details of receipt of payment).

3. I/We request that the rebate of the duty, service tax and cess on inputs and input services used in providing service exported by me/us in terms of rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 may be granted at the earliest. The following documents are enclosed in support of this claim for rebate.

- 1.
- 2.
- 3.

Declaration:

(a) We hereby certify that we have not availed CENVAT credit on inputs and input services on which rebate has been claimed.

(b) We have been granted permission by Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, vide C. No. _____, dated _____ for working under notification No. _____, dated _____.

(Signature and name of the service provider or his authorised agent with date)

(PART B: To be filled by the sanctioning authority)

Date of receipt of the rebate claim: _____

Date of sanction of the rebate claim: _____

Amount of rebate claimed: Rs. _____

Amount of rebate sanctioned: Rs. _____

If the claim is not processed within 15 days of the receipt of the claim, indicated briefly reasons for delay.

Place:

Date:

Signature of the Assistant Commissioner/
Deputy Commissioner of Central Excise.

4. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 40/2012-सेवा कर

सा.का.नि. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 की उपधारा (3) और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 95 की उपधारा (3) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2011 सेवा कर तारीख 1 मार्च, 2011 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 174(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कराधेय सेवाओं किसी विशेष आर्थिक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष आर्थिक जोन कहा गया है) में अवस्थित किसी इकाई या प्राधिकृत प्रचालन के लिए विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता द्वारा प्राप्त वित्त अधिनियम, 1944 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन सेवा कर से प्रभार्य कराधेय सेवाओं को उदग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात् :—

(क) यह कि छूट किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई या प्राधिकृत प्रचालन के लिए विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर के प्रतिदाय के रूप में दी जाएगी :

परंतु जहां प्राधिकृत प्रचालन के लिए प्राप्त और उपयोग की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं का विशेष आर्थिक जोन के भीतर ही पूर्णतः उपयोग किया जाता है वहां ऐसी सेवाओं या प्रदाता या किसी ऐसी सेवाओं का प्राप्तकर्ता प्रतिवर्तित प्रभार के आधार पर इस अधिसूचना के निबंधनों में प्रतिदाय के तौर पर छूट का दावा करने के लिए, यथास्थिति, विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या यूनिट की बजाय आरंभ से ही सेवा कर का संदाय न करने का विकल्प होगा ।

रप्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “पूर्णतया उपयोग की गई” अभिव्यक्ति से प्राधिकृत प्रचालन के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के किसी विकासकर्ता या यूनिट द्वारा प्राप्त कराधेय विनिर्दिष्ट सेवाएं अभिप्रेत हैं, यदि इन सेवाओं का प्रबंध करने का स्थान सेवा प्रबंध स्थान नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीओपी नियम से गी जाना जाता है) के निबंधनानुसार यथा अवधारित विशेष आर्थिक जोन में है ।

(i) पीओपी नियम के नियम 4 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए, एसाईजेड के भीतर जहां सेवाएं वास्तव में प्रदर्शन कर रही हैं; और

(ii) पीओपी नियम के नियम 5 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए, एसईजेड के भीतर जहां संपत्ति स्थित है या स्थित होने का इशाद है, और

(iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) के अंतर्गत के अलावा अन्य सेवाओं के संबंध में, प्राप्तकर्ता एसईजेड में संचालन के अलावा किसी भी अन्य व्यापार का संचालन नहीं करता है

(ख) जहां विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट सेवाओं का पूर्णतः उपभोग विशेष आर्थिक जोन के भीतर नहीं किया जाता है अर्थात् विशेष आर्थिक जोन की यूनिट की प्राधिकृत संक्रियाओं और घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट के बीच साझा की गई है वहां प्रतिदाय, उस दी गई अवधि के लिए जिसके बारे में दावा है कुल व्यापारावर्त तक निर्यात व्यापारावर्त के अनुपात की सीमा तक निर्बंधित किया जाएगा, अर्थात्

(माल का निर्यात व्यापारावर्त एसईजेड x सेवाओं पर दिया गया रोवाकर रांपूर्ण इकाई द्वारा सेवाएं)

खपत हुई सेवाओं के सिवाय (एसईजेड और डीटीए दोनों के लिए)

कुल व्यापारावर्त

स्पष्टीकरण, - शर्त (ख) के प्रयोजन के लिए-

(क) “प्रतिदाय रकम” से अधिकतम प्रतिदाय, जो अवधि के लिए मंजूर हो सकता है, अभिप्रेत है।

(ख) “माल का निर्यात व्यापारावर्त” अवधि के दौरान निकारी अंतिम उत्पाद और मध्यवधि उत्पाद का मूल्य अभिप्रेत है;

(ग) “रोवाओं के निर्यात व्यापारावर्त” से निम्नलिखित रीति से सांगणित निर्यात रोवा का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात्:

सेवाओं का निर्यात व्यापारावर्त निर्यात सेवाओं की सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संवाय निर्यात सेवाएं जिसके उपबंध उसके लिए पूरे किए गए हैं, जिसके लिए संवाय सुसंगत अवधि के लिए किसी पूर्व अवधि में अग्रिम के रूप में प्राप्त किया गया है उसके लिए निर्यात रोवाओं के लिए प्राप्त अग्रिम, जिसके लिए सेवा का उपबंध सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं हुआ है;

(ड) “कुल व्यापारावर्त” से

(क) संबंधित अवधि के दौरान, निकारी सभी उत्पाद शुल्क्य माल, जिसके अंतर्गत छूट प्राप्त माल, शुल्क्य माल और उत्पाद शुल्क्य मालों का निर्यात भी है;

(ख) उम्र खंड (ग) के निबंधनानुसार अवधारित सेवाओं का निर्यात व्यापारावर्त और सुसंगत अवधि के दौरान सभी अन्य सेवाओं का मूल्य; और

(ग) छूट के दावे के प्रयोजन के लिए एसईजेड इकाई और डेवलेपर के लिए सेवाओं की सूची जो कि सेवाकर के लिए उत्तरदायी हैं और जिनका अनुभोदन अधिकृत संचालन समिति द्वारा मान्यता लेना अनिवार्य है (जिसे इसमें इसके पश्चात निर्दिष्ट सेवाओं के रूप में जाना जाता है)

(घ) नये सिरे से छूट का दावा करने के लिए ऐसा विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट जो अपना निजी या विशेष आर्थिक जोन संक्रियाओं से भिन्न कोई कारबार नहीं करता है,

छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए उपरोक्त शर्त (ग) के अधीन सूची अभिप्राप्त करने के अतिरिक्त विशेष आर्थिक जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप क-1 में उस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा ; ऐसा विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट जो अपना निजी या विशेष आर्थिक जोन संक्रियाओं से भिन्न कोई कारबार नहीं करता है, छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए प्ररूप क-1 में उस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(ङ) छूट का दावा करने वाला कोई विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट यह घोषणा करेगा कि विनिर्दिष्ट सेवाएं जिनपर वह छूट और/या प्रतिदाय का दावा किया है, का वस्तुतः उपयोग प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए किया गया है ;

(च) छूट का दावा करने वाला कोई विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट ने वस्तुतः बीजक, बिल या यथास्थिति, चालान जिसके अंतर्गत उक्त कर अदा करने के दायी व्यक्ति को संदेय सेवा कर या वित्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, प्रतिवर्त प्रभार के अधीन संदेय सेवा कर की रकम भी है, में उपदर्शित रकम का संदाय किया है ;

(छ) किसी विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर का कोई केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन नहीं लिया गया है ;

(ज) डीटीए में पूर्णतः उपभोग की गई सेवाओं जैसा कि शर्त (क) के स्पष्टीकरण के खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है प्रतिदाय नहीं होगा ;

(झ) विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट जो इस अधिसूचना के अधीन छूट और/या प्रतिदाय का फायदा उठाना चाहता है, विनिर्दिष्ट सेवाओं की प्राप्ति और उपयोग का उचित लेखा बनाए रखेगा जिसपर विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए छूट का दावा किया गया है ।

3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के फायदे का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, अर्थात् :-

(क) विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट जिसने वित्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन सेवा कर संदत्त किया है, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करके छूट का लाभ उठाएगा ;

(ख) विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या इसके अधीन बनाए गए नियम या उक्त वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) या इसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन निर्धारिति के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप क-2 में यथास्थिति, विशेष आर्थिक जोन या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या विकासकर्ता या यूनिट के मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त को प्रतिदाय का दावा फाइल करेगा ;

(ग) विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट, जो खंड (ख) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इस अधिसूचना के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने के पहले इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप क-3 में यथास्थिति, विशेष आर्थिक जोन या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या विकासकर्ता या यूनिट के मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाले

यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त के पास एक घोषणा फाइल करेगा ;

(घ) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रस्तुप क-3 में उक्त घोषणा की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर खंड (ग) में निर्दिष्ट विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट को सेवा कर कोड सं. आबंटित करेगा ;

(ङ) प्रतिदाय का दावा उस मास की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर फाइल किया जाएगा जिसमें सेवा कर का वास्तविक संदाय ऐसे विकासकर्ता या यूनिट द्वारा रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाता को दिया गया है या ऐसी विस्तारित अवधि जो यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अनुज्ञात करे ;

(च) प्रतिदाय दावा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होंगे, अर्थात् :-

(i) विनिर्दिष्ट सेवाओं की सूची की एक प्रति जो अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए अपेक्षित हैं ; जहां लागू हो 2(ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज अर्थात् प्रस्तुप क-1 में घोषणा ;

(ii) मूल रूप में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए संदाय और संदर्भ सेवा कर के सबूत के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाता द्वारा विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन की यूनिट के नाम से वित्त अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योगों के अनुसार जारी चालान या यथास्थिति, बीजक या बिल ;

(iii) विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन के यूनिट द्वारा ऐसी छूट का दावा करने के लिए इस आशय की घोषणा कि -

(क) विनिर्दिष्ट सेवाएं जिसपर सेवा कर के प्रतिदाय का दावा किया गया है, का वस्तुतः उपयोग विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए किया गया है ;

(ख) प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्राप्त और उपयोग की गई विनिर्दिष्ट रोवाओं का उचित लेखा विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन के यूनिट द्वारा बनाए रखा गया है और उसको, मांग पर प्रतिदाय को मजूर करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ग) ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर को उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाता द्वारा जारी बीजक या बिल या यथास्थिति, चालान पर आधारित प्रतिदाय के रूप में दावा किए गए रोवा कर के संदाय के सबूत के रूप में विकासकर्ता या यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे या दस्तावेज सभी तरह से सत्य और सही हैं ;

(छ) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त यह सत्यापित करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर का प्रतिदाय करेगा कि -

(i) प्रतिदाय दावा सभी प्रकार से पूरा है ; और

(ii) प्ररूप क-2 और समर्थित दस्तावेजों में दी गई सूचना विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं में अंतर्वर्लित सेवा कर का ठीक-ठीक उल्लेख किया गया है जिसका प्रतिदाय के रूप में दावा किया गया है और सेवा प्रदाता को वस्तुतः संदत्त किया गया है;

(ज) सेवा प्रदाता, इस अधिसूचना द्वारा अनुदत्त छूट के अधीन “पूर्णतः उपभोग की गई” प्रवर्ग के अधीन आने वाली विनिर्दिष्ट सेवाएं पैरा 2 के उपपैरा (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और इसके अतिरिक्त जहां कहीं लागू हो, पैरा 2 के उपपैरा (ग) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज अर्थात् प्ररूप क-1 में घोषणा को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए किसी विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट को उपलब्ध कराएगा;

(झ) जहां विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर का कोई प्रतिदाय, चाहे जो कारण हो गलत ढंग से किया गया है वहां ऐसा प्रतिदाय किया जाने वाला सेवा कर वित्त अधिनियमख. 1994 (1994 का 32) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार वसूलनीय होगा मानो यह गलत ढंग से प्रतिदाय किए गए सेवा कर की वसूली है।

4. इस अधिसूचना में प्रयुक्त और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) या इसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्द और पद इस अधिसूचना के अधीन सेवा कर के प्रतिदाय के संबंध में, जहां तक संभव हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह विशेष आर्थिक जोन के संबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए कानूनी संपरीक्षक से ऐसा चार्टर्ड अकाउन्टेंट निर्दिष्ट है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन के यूनिट के वार्षिक लेखे की संपरीक्षा करता है।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2012 को ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

प्ररूप क-1

नए सिरे से छूट का दावा करने वाले ऐसे विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन की यूनिट द्वारा अधिसूचना सं..... तारीख [पैरा 2(घ) देखें]

- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का नाम :
- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का पता और दूरभाष तथा ई भेल:
- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का स्थाई खाता संख्या :
- आयात और निर्यात कोड संख्या :
- अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर प्रभाग :
- सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या/सेवा कर कोड :
- घोषणा : मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि-
 - इस आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा हर प्रकार से पूरी है और मैं विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं;
 - मैं/हम विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्राप्त और प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाएं जो विशेष आर्थिक जोन की अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित है, का उचित लेखा रखूंगा/रखेंगे; मैं/हम सभी युक्तियुक्त समय पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को निरीक्षण या संवीक्षा के लिए ऐसे लेखों और संबद्ध अभिलेखों को उपलब्ध कराऊंगा/कराएंगे।

(iii) मैं/हम विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विनिर्दिष्ट सेवाओं का उपयोग करूंगा/करेंगे/उपयोग किया है ।

(iv) मैं/हम एसईजेड में कराधेय सेवा या विनिर्माण उपलब्ध कराने के अलावा अपना या कोई अन्य कारबार नहीं करता है/नहीं करते हैं ; (जहां यह सद लागू नहीं है, उसके अनुरूप घोषणा पत्र जमा करें)

(v) मुझे/हमें यह ज्ञात है कि घोषणा, अधिसूचना तारीख में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विधिमान्य है और शर्तों के अधीन है ।

(vi) मैं/हम निम्नलिखित डीटीए सेवा प्रदाता(ओं) जो नए सिरे से छूट का लाभ लेना चाहते हैं :

क्रम सं.	डीटीए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा (सेवाओं) का/ विवरण	डीटीए सेवा प्रदाताओं जो विशेष आर्थिक जोन प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विनिर्दिष्ट सेवा (सेवाएं) उपलब्ध कराता है	नाम और पता	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर (मोहर सहित)

तारीख :

स्थान :

मैंने उपरोक्त घोषणा को सत्यापित किया है ; यह सही है

विशेष आर्थिक जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी का हस्ताक्षर, तारीख और मोहर (विनिर्दिष्ट अधिकारी अभिलेख के प्रयोजन के लिए सत्यापित घोषणा की एक प्रति रखेगा)

प्ररूप क-2

विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए आवेदन

[पैरा 2(ख) देखें]

सेवा में

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/ सेवा कर सहायक/उपायुक्त
..... प्रभाग आयुक्त कार्यालय

महोदय,

मैं/हम रु. (शब्दों में) प्रतिदाय का,

(क) विशेष आर्थिक जोन की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त 'पूर्णतः उपभोग की गई' विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर की बाबत ' [..... रुपए] दावा करता हूं/करते हैं

(ख) उन सेवाओं से भिन्न, जिनका पूर्णतः उपभोग विशेष आर्थिक जोन की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए किया गया है, विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर की बाबत रुपए] दावा करता हूं/करते हैं ।

1. विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का नाम :
2. विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का पता और दूरभाष तथा ई-मेल :
3. रजिस्ट्रीकृत/मुख्यालय का पता और दूरभाष तथा ई-मेल :
4. विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का स्थाई खाता संख्या :
5. अस्यात और निर्यात कोड संख्या :
6. अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर प्रभाग :
7. सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या / सेवा कर कोड :
8. बैंक खाता (बैंक, शाखा का पता, खाता संख्या) से संबंधित सूचना जिसमें प्रतिदाय रकम प्रत्यय/निक्षेपित की जाए :
9. दावाकृत सेवा कर प्रतिदाय के संबंध में व्यौरे :

9.1 'पूर्णतः उपभोग की गई' विनिर्दिष्ट सेवाओं से उद्भूत प्रतिदाय :

सारणी-क

सं.	यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित व्यौरे	प्रतिदाय के रूप में	विशेष आर्थिक जोन						
विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत रांकियाओं में प्रयुक्त करार्धेय सेवा का विवरण (वीजक के अनुसार)	सेवा करने का नाम	सेवा करने की सेवा संख्या	वीजक/बिल/संलग्न सारीख करार्धेय सेवा का गूल्य (रूपए)	संदर्भ करने का गूल्य (रूपए)	सेवा करने की रकम (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकरण शामिल हैं)	सेवा करने की रकम (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकरण शामिल हैं)	दावाकृत सेवा करने की रकम (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकरण शामिल हैं)	दावाकृत सेवा करने की रकम (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकरण शामिल हैं)	दावाकृत सेवा करने की रकम (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकरण शामिल हैं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
			कुल						

9.2 'पूर्णतः उपभोग की गई' सेवाओं से भिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं से उद्भूत प्रतिदाय ;
मैं/हमें -

(क) विशेष आर्थिक जोन से निर्यातित अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्ता

(ख) विशेष आर्थिक जोन से निर्यातित निर्गत सेवाओं को उपलब्ध कराने में प्रयुक्ता

‘पूर्णतः उपभोग की गई’ सेवाओं से भिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदर्भ सेवा कर के प्रतिदाय का अनुरोध करता हूं/करते हैं

मैं/हम उपरोक्त प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए सारणी ‘ख’ और सारणी ‘ग’ में निम्नलिखित रात्य और सही विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

सारणी-ख

सं.	उस अवधि जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है के दौरान धरेलू ऐरिफ़ क्षेत्र यूनिट की साझा में विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाएं	सेवा कर के संदर्भ/के राष्ट्रीय रूप में						
		विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं में प्रयुक्त कराधीय सेवा का विवरण (बीजक के अनुसार)	सेवा प्रदाता का नाम और पता	सेवा करने कराता सेवा करने कराता रजिस्ट्री करणे से	बीजक/बिल/ चालान (मूल रालग्न)	संख्या	तारीख	कारधीय सेवा का गूल्य (रूपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

सारणी-ग

ब्यौरे	उस अवधि का ब्यौरा जिससे बीजक संबंधित है और प्रतिदाय का दावा किया गया है		
	विशेष आर्थिक जोन यूनिट (यूनिटों) का निर्यात व्यापारावर्त	डीटीए यूनिट (यूनिटों) का व्यापारावर्त	कुल व्यापारावर्त
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	
(क)			
(ख)			
(ग)		
कुल (क)+(ख)+(ग)=(घ)			

उपरोक्त सांख्यिकीय सारणी के संकलन के लिए निर्देश :

- (i) विशेष आर्थिक जोन के निर्यात व्यापारावर्त के परिकलन के लिए मालों के निर्यात की दशा में शिपिंग बिल या निर्यात बिल में उपलब्ध एफओबी मूल्य हिसाब में लिया जाना चाहिए जो सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा इस आशय से सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया है कि मालों का वस्तुतः निर्यात किया गया है ;
- (ii) विशेष आर्थिक जोन के निर्यात व्यापारावर्त के परिकलन के लिए सेवाओं के निर्यात की दशा में निर्यात की गई निर्गत सेवाओं का मूल्य निर्यात आगमों की वसूली को प्रमाणित करने वाले बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर किया जाएगा ;
- (iii) सारणी ग के साथ सारणी ख के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावाकृत सेवा कर की रकम : रुपए
- (iv) विशेष आर्थिक जोन यूनिट के कानूनी संपरीक्षक द्वारा सारणी ग में भरी गई विशिष्टियों की बातों की सत्यता का सत्यापन और प्रमाणन किया जाना चाहिए

10. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि—

- (i) प्रतिदाय के इस आवेदन में दी गई जानकारी सत्य, सही तथा हर प्रकार से पूरी है और मैं सेवा कर के प्रदाय के लिए इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं ;
- (ii) विशेष आर्थिक जोन की अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित विनिर्दिष्ट सेवाएं जिनके लिए छूट या प्रतिदाय का दावा किया गया है, का वास्तविक रूप से उपयोग विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं में किया गया है ;
- (iii) प्रतिदाय, विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक रूप से संदत्त सेवा कर पर ही दावा किया गया है ; हमने उपरोक्त दस्तावेजों/सूचना के आधार पर पहले सेवा कर का दावा नहीं किया है और न ही कोई प्रतिदाय प्राप्त किया है ;
- (iv) हमने केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर का कोई केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया है ;
- (v) ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर उपदर्शित करते हुए सेवा प्रदाता के बीजक, बिल या चालान के अनुसार प्रतिदाय के रूप में दावा किए जाने वाले सेवा कर के संदाय के सबूत के रूप में दिए गए खाते या दस्तावेज सभी तरह से सत्य और सही हैं ;

(vi) विशेष आर्थिक जोन में प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए उस विनिर्दिष्ट सेवा की प्राप्ति और उपयोग का उचित लेखा, जिस पर छूट या प्रतिदाय का दावा किया गया है, बनाए रखा गया है और मांग करने पर उसको प्रतिदाय अनुमोदन करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

हस्ताक्षर और नाम
(स्वत्वधारी/प्रबंधक भागीदार/विशेष आर्थिक जोन यूनिट के प्रबंध
निदेशक/विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति)
पूरा पता, दूरभाष और ई-मेल सहित

तारीख :

स्थान :

प्ररूप क-3

सेवा कर कोड अभिप्राप्त करने की घोषणा

[पैरा 3(ग) देखें]

- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का नाम :
- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का पता और दूरभाष तथा ई-मेल :
- रजिस्ट्रीकृत गुरुत्वालय का पता :
- विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का राई खाता संख्या :
- आयात और निर्यात कोड संख्या :
- अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/रोधा कर प्रभाग :
- सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या/सेवा कर कोड :
- बैंक खाता (बैंक, शाखा का पता, खाता संख्या) के व्यौरे :
- (क) विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता का गठन |रवामित्व/भागीदारी/रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सीमित कंपनी/रजिस्ट्रीकृत पब्लिक सीमित कंपनी/अन्य (विनिर्दिष्ट करें) |
- (ख) स्वामी/भागीदार/निदेशक (निदेशकों) का नाम, पता, दूरभाष संख्या,
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, पदनाम और पता.....
- मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि—
 - इस आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा हर प्रकार से पूरी है और मैं विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विकासकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ :
 - मै/हम विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए प्राप्त और प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सेवाएं जो विशेष आर्थिक जोन की अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित हैं, का उचित लेखा रखूँगा/रखेंगे ; और किसाम को, सभी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण या संवीक्षा के लिए ऐरो लेखों और संबद्ध अभिलेखों/को उपलब्ध कराऊंगा/कराएंगे ।
 - मै/हम विशेष आर्थिक जोन की प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विनिर्दिष्ट सेवाओं का उपयोग करूँगा/करेंगे/उपयोग किया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर (प्रेरण सहित)

तारीख :

स्थान :

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

No. 40/2012-Service Tax

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act) read with sub-section 3 of section 95 of Finance (No.2), Act, 2004 (23 of 2004) and sub-section 3 of section 140 of the Finance Act, 2007(22 of 2007) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2011-Service Tax, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.174(E), dated the 1st March, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the services on which service tax is leviable under section 66B of the said Act, received by a unit located in a Special Economic Zone (hereinafter referred to as SEZ) or Developer of SEZ and used for the authorised operations, from the whole of the service tax, education cess and secondary and higher education cess leviable thereon.

2. The exemption contained in this notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the exemption shall be provided by way of refund of service tax paid on the specified services received by a unit located in a SEZ or the developer of SEZ and used for the authorised operations:

Provided that where the specified services received in SEZ and used for the authorised operations are wholly consumed within the SEZ, the person liable to pay service tax has the option not to pay the service tax *ab initio* instead of the SEZ unit or the developer claiming exemption by way of refund in terms of this notification.

Explanation.— For the purposes of this notification, the expression “wholly consumed” refers to such specified services received by the unit of a SEZ or the developer and used for the authorised operations, where the place of provision determinable in accordance with the Place of Provision of Services Rules, 2012(hereinafter referred as the POP Rules) is as under:-

- (i) in respect of services specified in rule 4 of the POP Rules, the place where the services are actually performed is within the SEZ ; or
- (ii) in respect of services specified in rule 5 of the POP Rules, the place where the property is located or intended to be located is within the SEZ; or
- (iii) in respect of services other than those falling under clauses (i) and (ii), the recipient does not own or carry on any business other than the operations in SEZ;

(b) where the specified services received by the unit of a SEZ or developer are not wholly consumed within SEZ, maximum refund shall be restricted to the extent of the ratio of export turnover of goods and services multiplied by the service tax paid on services other than wholly consumed services to the total turnover for the given period to which the claim relates, i.e.,

$$\frac{(\text{Export turnover of goods} + \text{Services of SEZ Unit/Developer})}{\text{Total turnover for the period}} \times \frac{\text{Service tax paid on services}}{\text{other than wholly consumed Services (both for SEZ and DTA)}}$$

Refund amount =

Total turnover for the period

Explanation.- For the purposes of condition (b),-

- (A) "refund amount" means the maximum refund that is admissible for the period;
- (B) "export turnover of goods" means the value of final products and intermediate products cleared during the relevant period and exported;
- (C) "export turnover of services" means the value of the export service calculated in the following manner, namely:-

Export turnover of services = payments received during the relevant period for export services + export services whose provision has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period – advances received for export services for which the provision of service has not been completed during the relevant period;

- (D) "total turnover" means sum total of the value of-

- (a) all excisable goods cleared during the relevant period including exempted goods, dutiable goods and excisable goods exported;
- (b) export turnover of services determined in terms of clause (C) and the value of all other services, during the relevant period; and
- (c) for the purpose of claiming exemption, the Unit of a SEZ or developer shall obtain a list of services that are liable to service tax as are required for the authorised operations approved

by the Approval Committee (hereinafter referred to as the specified services) of the concerned SEZ;

- (d) for the purpose of claiming *ab initio* exemption, the unit of a SEZ or developer shall furnish a declaration in Form A-1, verified by the Specified Officer of the SEZ, in addition to the list specified under condition (c); the unit of a SEZ or developer who does not own or carry on any business other than the operations in SEZ, shall declare to that effect in Form A-1;
- (e) the unit of a SEZ or developer claiming the exemption shall declare that the specified services on which exemption and/ or refund is claimed, have been used for the authorised operations;
- (f) the unit of a SEZ or developer claiming the exemption by way of refund, should have paid the amount indicated in the invoice, bill or as the case may be, challan, including the service tax payable, to the person liable to pay the said tax or the amount of service tax payable under reverse charge, as the case may be, under the provisions of the said Act;
- (g) no CENVAT credit of service tax paid on the specified services used for the authorised operations in a SEZ has been taken under the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (h) no refund shall be available on services wholly consumed for operations in the Domestic Tariff Area (DTA) worked out in the same manner as clauses (i) and (ii) of the explanation to condition (a);
- (i) exemption or refund of service tax paid on the specified services other than wholly consumed services used for the authorised operations in a SEZ shall not be claimed except under this notification;
- (j) the unit of a SEZ or developer, who intends to avail exemption and or refund under this notification, shall maintain proper account of receipt and use of the specified services on which exemption is claimed, for authorised operations in the SEZ.

3. The following procedure should be adopted for claiming the benefit of the exemption contained in this notification, namely:-

- (a) the unit of a SEZ or developer, who has paid the service tax leviable under section 66B of the said Act shall avail the exemption by filling a claim for refund of service tax paid on specified services used for the authorised operations;
- (b) the unit of a SEZ or developer who is registered as an assessee under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, or the said Act or the rules made thereunder, shall file the claim for refund to the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the SEZ or

registered office or the head office of the SEZ unit or developer, as the case may be, in Form A-2;

(c) the unit of a SEZ or developer who is not so registered under the provisions referred to in clause (b), shall, before filing a claim for refund under this notification, file a declaration with the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the SEZ or registered office or the head office of the SEZ unit or developer, as the case may be, in Form A-3;

(d) the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall, after due verification, allot a service tax code number to the unit of a SEZ or developer, referred to in clause (c), within seven days from the date of receipt of the said declaration, in Form A-3;

(e) claim for refund shall be filed, within one year from the end of the month in which actual payment of service tax was made by such developer or unit, to the registered service provider or such extended period as the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall permit;

(f) the refund claim shall be accompanied by the following documents, namely:-

(i) a copy of the list of specified services as are required for the authorized operations in the SEZ, as approved by the Approval Committee; wherever applicable, a copy of the declaration made in Form A-1;

(ii) invoice or a bill or as the case may be, a challan, issued in accordance with the provisions of the said Act or rules made thereunder, in the name of the unit of a SEZ or developer, by the registered service provider, along with proof of payment for such specified services used for the authorised operations and service tax paid, in original;

(iii) a declaration by the unit of a SEZ or developer, claiming such exemption, to the effect that—

(A) the specified services on which refund of service tax claimed, has been used for the authorized operations in the SEZ;

(B) proper account of the specified services received and used for the authorised operations are maintained by the developer or unit of the SEZ and the same shall be produced to the officer sanctioning refund, on demand;

(C) accounts or documents furnished by the unit of a SEZ or developer as proof of payment of service tax claimed as refund, based on the invoice, or bill , or as the case may be challan issued by the registered service provider indicating the service tax paid on such specified services, are true and correct in all respects;

(g) the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, after verifying that,-

- (i) the refund claim is complete in all respects;
- (ii) the information furnished in Form A-2 and in supporting documents correctly indicate the service tax involved in the specified services used for the authorised operations in the SEZ, which is claimed as refund, and has been actually paid to the service provider,

shall refund the service tax paid on the specified services;

(h) a service provider shall provide the specified services falling under wholly consumed category, under *ab initio* exemption granted by this notification, to a unit of a SEZ or developer, for authorised operations, subject to the submission of list specified in condition (c) under paragraph 2 and a declaration in Form A-1;

(i) where any refund of service tax paid on specified services is erroneously refunded for any reasons whatsoever, such service tax refunded shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under, as if it is recovery of service tax erroneously refunded;

4. Words and expressions used in this notification and defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) or the rules made thereunder, shall apply, so far as may be, in relation to refund of service tax under this notification as they apply in relation to a SEZ.

Explanation.- For the purposes of this notification, "statutory auditor" refers to a Chartered Accountant who audits the annual accounts of the unit of a SEZ or developer for the purposes of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Income tax Act, 1961(43 of 1961).

5. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2012.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

FORM A-1

DECLARATION BY THE UNIT OF A SEZ OR DEVELOPER FOR AVALING *AB INITIO* EXEMPTION UNDER NOTIFICATION No. _____ DATED _____
 [Refer condition (d) under paragraph 2]

1. Name of the SEZ Unit/Developer:
2. Address of the SEZ Unit/Developer with Telephone and Email:
3. Permanent Account Number(PAN) of the SEZ Unit/Developer:
4. Import and Export Code Number:
5. Jurisdictional Central Excise/Service Tax Division:
6. Service Tax Registration Number/Service Tax Code:
7. Declaration: I/We hereby declare that-
 - (i) The information given in this application form is true, correct and complete in every respect and I am authorised to sign on behalf of the SEZ Unit/Developer;
 - (ii) I/We maintain proper account of specified services, as approved by the Approval Committee of SEZ, received and used for authorised operations in SEZ; I/we shall make available such accounts and related records, at all reasonable times, to the jurisdictional Central Excise Officers for inspection or scrutiny.
 - (iii) I/We shall use/have used specified services for authorised operations in the SEZ.
 - (iv) I/We declare that we do not own or carry on any business other than the operations in SEZ [*where this item is not applicable, declaration may be submitted after striking out the inapplicable portion*];
 - (v) I/We are aware that the Declaration is valid only for the purpose specified in Notification _____ dated _____ and is subject to fulfillment of conditions.
 - (vi) I/We intend to claim *ab initio* exemption from the following service provider(s) in the Domestic Tariff Area(DTA):

Sl.No.	specified service(s) to be received from the DTA service provider(s)	DTA Service provider(s) who provide(s) the specified service(s), for SEZ authorised operations		
		Name and address	Service	Tax Registration No.
(1)	(2)	(3)	(4)	

Signature and Name of Authorised Person with stamp

Date:

Place:

I have verified the above Declaration; it is correct

Signature, date and stamp of the Specified Officer of the SEZ (Specified Officer shall retain a copy of the verified Declaration, for the purpose of record)

FORM A-2

**APPLICATION FOR CLAIMING REFUND OF SERVICE TAX PAID ON SPECIFIED SERVICES
USED FOR AUTHORISED OPERATIONS IN SEZ**

To _____ The Assistant/Deputy Commissioner of Central Excise/Service Tax _____ Division, _____ Commissionerate

Sir.

I/We claim refund of Rs..... (Rupees in words)

(a) in respect of service tax paid on 'wholly consumed' specified services used for the authorized operations in SEZ, as approved by the Approval Committee of the _____ SEZ [Rupees _____]

(b) in respect of service tax paid on specified services, other than those that are wholly consumed, used for the authorized operations of SEZ Unit/Developer, as approved by the Approval Committee of the _____ SEZ [Rupees _____].

1. Name of the SEZ Unit/Developer:
2. Address of the SEZ Unit/Developer with Telephone and Email:
3. Address of the Registered/Head Office with Telephone and Email:
4. Permanent Account Number(PAN) of the SEZ Unit/Developer:
5. Import and Export Code Number:
6. Jurisdictional Central Excise/Service Tax Division:
7. Service Tax Registration Number/Service Tax Code:
8. Information regarding Bank Account (Bank, Address of Branch, Account Number) in which refund amount should be credited/to be deposited:
9. Details regarding Service Tax refund claimed:
- 9.1 Refund arising out of 'wholly consumed' specified services:

Table-A

9.2. Refunds arising out of specified services, other than those are 'wholly consumed':

I/We request refund of service tax paid on specified services, other than those that are 'wholly consumed',-

- (a) used in the manufacture of final products exported from SEZ
- (b) used in providing output services exported from SEZ

I/We furnish following true and correct particulars, in Tables 'B' and 'C', for the purpose of above refund:

TABLE-B

No.	Specified services other than those that are 'wholly consumed', used for authorised operations by SEZ Unit/Developer, during the period for which refund is claimed						Document enclosed as proof of payment of service tax (sl.no and date of invoice/ bill / challan)	
	Description of taxable service(as per the invoice) used in the authorized operations of SEZ	Name and address of Service Provider	Service Tax Registration Number of Service Provider	Invoice/Bill/Challan (original enclosed)		Amount of Service tax paid (including education cess) (Rupees)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
TOTAL								

TABLE-C

Details	Details for the period to which the invoices pertain and refund is claimed		
	Export turnover of SEZ Unit(s)/Developer	Service tax paid on input services other than wholly consumed services	Total turnover
	(1)	(2)	(3)
Goods (a)		---	
Output services (b)		---	
Others(Bought out goods sold) (c)	---	---	
Total (a)+(b)+(c)=(d)			

Instructions for compilation of the above statistical table:

- (i) To calculate the export turnover of SEZ, in the case of export of goods, FOB value provided in Shipping Bills or Bills of Export, should be taken into account, which have been duly certified by the officer of customs to the effect that the goods have been exported;
- (ii) To calculate the export turnover of SEZ, in the case of export of services, value of output services exported shall be on the basis of certificates issued by the bank certifying the realization of export proceeds.
- (iii) Amount of service tax claimed as refund, under Table B read with Table C: Rupees
- (iv) Particulars filled in the Table C should be verified and certified as true by the statutory auditor of the SEZ Unit/Developer

10. I/We Declare that—

- (i) information given in this application for refund is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign this application for refund of service tax;
- (ii) the specified services, as approved by the Approval Committee of SEZ, on which exemption/refund is claimed are actually used for the authorised operations in a SEZ;
- (iii) refund is being claimed only on the service tax actually paid on the specified services used for the authorised operations in a SEZ; refund of service tax has not been claimed or received earlier, on the basis of above documents/information;
- (iv) We have not taken any CENVAT credit of service tax paid on the specified services under the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (v) accounts or documents furnished as proof of payment of service tax being claimed as refund, as per the invoice, bill or challan of the service provider indicating the service tax paid on such specified services, are true and correct in all respects;
- (vi) proper account of receipt and use of the specified services on which exemption/refund is claimed, for the authorised operations in the SEZ, is maintained and the same shall be produced to the Officer sanctioning refund, on demand.

Signature and name
(of proprietor/managing partner/
person authorised by managing director of SEZ Unit/Developer)
with complete address, telephone and e-mail

Date:

Place:

FORM A-3

DECLARATION FOR OBTAINING SERVICE TAX CODE
[Refer clause (c) under paragraph 3]

1. Name of the SEZ Unit/Developer:
2. Address of the SEZ Unit/Developer with Telephone and Email:
3. Address of the Registered/Head Office:
4. Permanent Account Number(PAN) of the SEZ Unit/Developer:
5. Import and Export Code Number:
6. Jurisdictional Central Excise/Service Tax Division:
7. Service Tax Registration Number/Service tax Code:
8. Details of Bank Account (Bank, Address of Branch, Account Number)
9. (a) Constitution of SEZ Unit/Developer [proprietorship/partnership/Registered Private Limited Company/Registered Public Limited Company/Others(specify)]
 (b) Name, Address, Telephone number of Proprietor/partner/director(s)
10. Name, designation and address of the authorised signatory/signatories
11. I/We hereby declare that-
 - (i) The information given in this application form is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the SEZ Unit/Developer;
 - (ii) I/We shall maintain proper account of specified services as approved by the Approval Committee of SEZ, received and used for authorised operations in SEZ; and shall make available such accounts and related records, at all reasonable times, to the Department for inspection or scrutiny.
 - (iii) I/We shall use/have used specified services for authorised operations in the SEZ.

Signature and Name of Authorised Person with stamp

Date:

Place:

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सं. 28/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

साक्षा.नि. 483(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताती है, अर्थात् :

- 1 (1) इन नियमों को सेनेट क्रेडिट (छठवा संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जा सकता है।
- (2) ये जुलाई, 2012 से लागू होंगे।
- 2 सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 (इसके बाद यहाँ आगे उक्त नियमावली में कहा गया है) में, नियम 2 में-

 - (क) खंड (क) में,-
 - (i) उपखंड (क) में, यह (viii) में, "उनकी चेसिस शब्द के बाद" परंतु डंपर एवं टियर समेत" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उपखंड (ख) के लिए निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
 - (ख) सेवा प्रदाता के नाम में पंजीकृत उनकी चेसिस समेत माल के परिवहन के लिए अधिस्थापित मोटर वाहन, जब निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जाए ;
 - (i) ऐसे मोटर वाहन की किराएदारी की आउटपुट सेवा प्रदान करना; या
 - (ii) आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट एवं पूँजी माल का परिवहन;

अथवा

(iii) कूरियर एजेंसी की आउटपुट सेवा प्रदान करना;

(iii) उपखंड (ग) के लिए निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

(ग) सेवा प्रदाता के नाम में पंजीकृत उनकी चेसिस समेत यात्री ढोने के लिए अभिस्थापित मोटर वाहन, जब निम्नलिखित की आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाए;

(i) यात्रियों का परिवहन; अथवा

(ii) ऐसे मोटर वाहन को किसाए घर देना; अथवा

(iii) मोटर चालन कौशल प्रदान करना

(ख) खंड (ड) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;

(ड) "छूट प्राप्त सेवा" का अर्थ है;

(1) कराधेय सेवा के लिए उसपर लगाए जाने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट पाया है; अथवा

(2) सेवा जिस पर वित्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत कोई सेवाकर नहीं लगा सकता है; अथवा

(3) कराधेय सेवा जिसके आंशिक संख्या को इस शर्त पर छूट प्राप्त है कि ऐसी कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट एवं आउटपुट सेवाओं का कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा;

किंतु ऐसी सेवा शामिल नहीं होगी जो सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 की पुष्टि से निर्यात की जाती है

(ग) खंड (ट) में, उपखंड (ख) के लिए निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

(क) भवन या सिविल संरचना की निर्माण संविदा या उसके भाग का निर्माण या निष्पादन ; या

(ख) अधिनियम की धारा 66 ड. के खंड (ख) के अंतर्गत यथा सूचीबद्ध निर्माण संविदा या निर्माण सेवा के निष्पादन में सेवा के प्रावधान को छोड़ कर पूँजी माल के अवलंब के लिए नींव डालना या संरचनाएं बनाना ।

(घ) खंड (1) में, -

(i) "कराधेय सेवा" शब्द के लिए "आउटपुट सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (ii) में, "किंतु संवाएं शामिल नहीं हैं" शब्द के लिए "किंतु शामिल नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उपखंड (क) के लिए निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्

"(क) वित्त अधिनियम की धारा 66ड. के खंड (ख) के अंतर्गत सेवा समेत (इसके बाद यहाँ आगे विनिर्दिट सेवाएं कहा गया है) निर्माण संविदा एवं निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा अथवा, जहाँ तक उनका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है-

(क) भवन या सिविल संरचना की निर्माण संविदा या उसके भाग का निर्माण या निष्पादन; संख्या

(ख) एक या अधिक विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रावधन को छोड़कर पूँजी माल के अवलंब के लिए नींव डालना या संरचनाएं बनाना; अथवा

(ग) उपखंड (ख) में, "बिना अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ओ) और (जेडजेडजेड जे) में विनिर्दिष्ट" कोष्ठक, अक्षर एवं आंकड़ा शब्द के लिए "मोटर वाहन किराएदारी के रूप में प्रदत्त सेवाएं" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपखंड (खक) के लिए निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्

"(खक) सामान्य व्यवसाय, सर्विसिंग, भरम्भत एवं अनुरक्षण की सेवा, यदि वे मोटर वाहन से संबंधित हैं जो पूँजी माल नहीं हैं, सिवाय इसके कि जब निम्नलिखित द्वारा प्रयुक्त किया जाए-

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्मित मोटर वाहन के संबंध में मोटर वाहन का विनिर्माता; अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा बीमाकृत या पुनः बीमाकृत मोटर वाहन के संबंध में बीमा कम्पनी, अथवा"

(ड.) खंड (पी) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(पी) "आउटपुट सर्विस का अर्थ कराधेय भूभाग में स्थित सेवा प्रदाता प्राप्त प्रदत्त किसी सेवा से है किंतु ऐसी सेवा शामिल नहीं होगी-

(1) जो वित्त अधिनियम की धारा 66 घ में विनिर्दिष्ट है, भवानी

(2) जहाँ संपूर्ण सेवाकर सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा संबंध है;

(3) उक्त नियमावली के नियम 3 में;

(क) उपनियम (1) में,-

(i) 'कराधेय सेवा प्रदाता', जहाँ ये आते हैं, शब्द के लिए "आउटपुट सेवा प्रदाता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद (ixa) के बाद, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् "(ixb) वित्त अधिनियम की धरा 66 ख के अंतर्गत कराधेय सेवा";

(iii) मद (xi) के बाद, मद (i) में, " का परिसर शब्द के लिए "द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उक्त नियमावली के उपनियम (4) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"स्पष्टीकरण"- सेनेट क्रेडिट ऐसी सेवाओं के संबंध में सेवाकर के भुगतान के लिए प्रयुक्त नहीं जा सकती जहाँ कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति सेवा प्राप्तकर्ता है"

(ग) उप नियम (5ख) के परंतुक में, "कराधेय सेवाओं" शब्द के लिए "आउटपुट सेवाएं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

4. नियम-5 में,-

(i) उपनियम (2) में, दूसरे परंतुक में, "सेवा नियीत नियमावली, 2005" के शब्दों एवं आंकड़ों के लिए "सेवाकर नियमावली, 1994" के शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण-1 में, "सेवा नियीत नियमावली, 2005 के प्रावधान" के शब्दों एवं आंकड़ों के लिए, जहाँ भुगतान प्राप्त किया जाता है या नहीं प्राप्त किया जाता है, "सेवाकर नियमावली, 1994 का नियम 6क" के शब्द, आंकड़े एवं अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

5. उक्त नियमावली में, नियम-5क के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगा, अर्थात्:

“5ख. प्रतिवर्ते प्रभार आधार पर कराधेय सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं को सेनेट क्रेडिट की वापसी- वित्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाता तथा ऐसी आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान के लिए इनपुट एवं आउटपुट सेवाओं पर प्राप्त सेनेट क्रेडिट का उपयोग करने में असमर्थ सेवा प्रदाताओं को राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किसी कार्यविधि, सुरक्षापार्यां, शर्तों एवं सीमाओं के अधीन ऐसी अप्रयुक्त सेनेट क्रेडिट का प्रतिदाय अनुमत होगा ।

6. उक्त नियमावली में, नियम-6 में,-

(i) सीमांत शीर्षक में, “कराधेय सेवा प्रदाता” शब्द के लिए “आउटपुट सेवा प्रदाता” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (3) में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“किंतु रेल द्वारा माल या यात्रियों के परिवहन के मामले में खंड (i) के अंतर्गत संदत्त की जाने वाली राशि छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के दो प्रतिशत की राशि के बराबर होगी ।”

(iii) उपनियम (3क) में, खंड (क), (ख), (ग) और (छ) में, “कराधेय” शब्द के लिए, जहां ये आते हैं, “आउटपुट” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपनियम (3ख) में, “वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 के उपखंड (जेडेएम) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाएं प्रदान करना” शब्द, कोष्ठक, अक्षर एवं आंकड़ों के लिए “जमा, कृण या अग्रिम प्रदान करने के रूप में सेवाएं प्रदान करने के रूप में शामिल” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) उपनियम 3(घ) में, स्पष्टीकरण-1 के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण 1- उपनियम-3 तथा 3क के प्रयोजनार्थ “मूल्य”, -

(क) का वही अर्थ होगा जो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित वित्त अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत इसका अर्थ निर्धारित है या यथास्थिति इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3,4 या 4क के अंतर्गत इसका मूल्य निर्धारित है;

(ख) कराधेय सेवा के मामले में, जब सेवाकर नियमावली 1994 के नियम छ के उपनियम 7,7क, 7ख या 7ग के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया गया है, वह मूल्य होगा जिस पर ऐसे दर से संबंधित छूट अधिसूचना, यदि कोई हो, के साथ पठित वित्त

अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत सेवाकर की दर, जब सेवाकर की गणना के लिए प्रयुक्त होने पर कर की उसी राशि के रूप में परिणत होती है जो प्राप्त किए गए विकल्प के अंतर्गत परिणित की जाती है, अथवा

(ग) ट्रेडिंग के मामले में, बेचे गए माल के बिक्री मूल्य तथा लागत (उनके क्रय के लिए किए गए व्यय को शामिल किए बिना सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित) के बीच अंतर या बेचे गए माल की लागत का दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

(घ) प्रतिभूतियों के व्यापार के मामले में, व्यापार की गई प्रतिभूतियों की बिक्री मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच अंतर या व्यापार की गई प्रतिभूतियों के क्रय मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

(ङ.) जमा, ऋण या अधिम प्रदान करने के रूप में सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं होगा, जहां तक ब्याज या बद्दा के रूप में प्रतिफल का प्रतिनिधित्व होता है।

(vi) उपनियम (6क) के लिए, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“(7) उपनियम (1),(2),(3) और (4) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को या उनके अधिकृत प्रधालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक को सेवाकर के भुगतान के बिना या जब सेवा का निर्यात किया जाता है, कराधेय सेवाएं प्रदान की जाती हैं,

(8) इस नियम के प्रयोगनार्थ, प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत सेवा उस समय छूट प्राप्त सेवा नहीं होगी जब:

(क) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों को सेवा पूरी करती है और सेवा के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाना है; और

(ख) ऐसा भुगतान-प्रावधान की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत हो सकती है, प्राप्त नहीं की गई है।”

7. उक्त नियमावली में, नियम-7 में, -

(i) खंड (घ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(घ) एक से अधिक यूनिट में प्रयुक्त सेवा के लिए सेवाकर की क्रेडिट संबंधित यूनिट की संगत अवधि के दौरान सभी यूनिटों, जिनसे सेवा उस अवधि के दौरान संबंधित है, दे-

टर्नओवर के कुल योग के यथानुपात के आधार पर वितरित की जाएगी ।”

(ii) स्पष्टीकरण 2 के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण 3- (क) संगत अवधि उस माह से पिछला माह होगी जिसके दौरान सेनेट क्रेडिट वितरित की जाती है ।

(ख) यदि इसकी कोई यूनिट सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8 के प्रावधान के अनुसार तिमाही आधार पर कर या शुल्क का भुगतान करती है, तो संगत अवधि उस तिमाही से पिछली तिमाही होगी जिसके दौरान सेनेट क्रेडिट का वितरण किया जाता है ।

(ग) ऐसे कर निर्धारिती के मामले में जिसका उक्त अवधि में कोई कुल टर्नओवर नहीं है, इनपुट सेवा वितरक ऐसी संगत अवधि की समाप्ति के बाद ही किसी क्रेडिट का वितरण करेगा जिसमें उसकी यूनिटों का कुल टर्नओवर उपलब्ध है ।”

8. उक्त नियमावली में, नियम 9 में, उपनियम (2) में, परंतुक में, “कराधेय सेवा प्रदाता” शब्द के लिए “आउटपुट सेवा प्रदाता” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. उक्त नियमावली में, नियम 13 में, “कराधेय सेवा” जहां ये आते हैं, शब्द के लिए आउटपुट सेवा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियमावली अधिसूचना सं0 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै0टै0), दिनांक 10 सितम्बर, 2004, सं0 सा0का0नि0 600(अ), दि0 10 सितम्बर, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित हुई तथा अधिसूचना सं0 25/2012-के030शु0 (गै0टै0), दिनांक 8 मई, 2004 के तहत सं0 सा0का0नि0 (अ), दि0 8 मई, 2012 के तहत आखिरी बार संशोधित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012.

No. 28/2012-Central Excise (N.T.)

GSR. 483(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2012.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—
 - (a) in clause (a),—
 - (i) in sub-clause (A), in item(viii), after the words, “their chassis” the words “but including dumper and tippers” shall be inserted;
 - (ii) for sub-clause (B), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(B) motor vehicle designed for transportation of goods including their chassis registered in the name of the service provider, when used for—

 - (i) providing an output service of renting of such motor vehicle; or
 - (ii) transportation of inputs and capital goods used for providing an output service; or
 - (iii) providing an output service of courier agency”
 - (iii) for sub-clause (C), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(C) motor vehicle designed to carry passengers including their chassis, registered in the name of the provider of service, when used for providing output service of—

 - (i) transportation of passengers; or
 - (ii) renting of such motor vehicle; or
 - (iii) imparting motor driving skills”
 - (b) for clause (e), the following shall be substituted, namely:—

‘(e) “exempted service” means a—

(1) taxable service which is exempt from the whole of the service tax leviable thereon; or

(2) service, on which no service tax is leviable under section 66B of the Finance Act; or

(3) taxable service whose part of value is exempted on the condition that no credit of inputs and input services, used for providing such taxable service, shall be taken;

but shall not include a service which is exported in terms of rule 6A of the Service Tax Rules, 1994.

(c) in clause (k), for sub clause (B), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(B) any goods used for -

(a) construction or execution of works contract of a building or a civil structure or a part thereof; or

(b) laying of foundation or making of structures for support of capital goods, except for the provision of service portion in the execution of a works contract or construction service as listed under clause (b) of section 66E of the Act;”

(d) in clause (l),-

(i) for the words “taxable service”, the words “output service” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the words “but excludes services”, the words “but excludes” shall be substituted;

(iii) for sub-clause (A), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(A) service portion in the execution of a works contract and construction services including service listed under clause (b) of section 66E of the Finance Act (hereinafter referred as specified services) in so far as they are used for -

(a) construction or execution of works contract of a building or a civil structure or a part thereof; or

(b) laying of foundation or making of structures for support of capital goods, except for the provision of one or more of the specified services; or”;

(iv) in sub-clause (B), for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-clauses (o) and (zzzzj) of clause (105) of section 65 of the Finance Act”, the words “services provided by way of renting of a motor vehicle” shall be substituted;

(v) for sub-clause (BA), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(BA) service of general insurance business, servicing, repair and maintenance, in so far as they relate to a motor vehicle which is not a capital goods, except when used by -

(a) a manufacturer of a motor vehicle in respect of a motor vehicle manufactured by such person ; or

(b) an insurance company in respect of a motor vehicle insured or reinsured by such person; or";

(e) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:-

'(p) "output service" means any service provided by a provider of service located in the taxable territory but shall not include a service,-

(1) specified in section 66D of the Finance Act; or

(2) where the whole of service tax is liable to be paid by the recipient of service.'

3. In rule 3 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words, "provider of taxable service", wherever they occur, the word " provider of output service" shall be substituted;

(ii) after item (ixa), the following item shall be inserted, namely:-

"(ixb) the service tax leviable under section 66B of the Finance Act";

(iii) after item (xi), in item (i), for the words "premises of" the words "by" shall be substituted;

(b) after sub-rule (4) of the said rules, following shall be inserted, namely:-

"Explanation. - CENVAT credit cannot be used for payment of service tax in respect of services where the person liable to pay tax is the service recipient"

(c) in the proviso to sub-rule (5B), for the words "taxable services" the words "output services" shall be substituted;

4. In rule 5,-

(i) in sub-rule (2), in the second proviso, for the words and figures "Export of Services Rules, 2005" the words and figures, "Service Tax Rules, 1994" shall be substituted;

(ii) in Explanation 1, for the words and figures "the provisions of Export of Services Rules, 2005, whether the payment is received or not" the words, figures and letter "rule 6A of the Service Tax Rules 1994" shall be substituted;

5. In the said rules, after rule 5A, the following rule shall be inserted, namely:-

" 5B. Refund of CENVAT credit to service providers providing services taxed on reverse charge basis.- A provider of service providing services notified under sub-section (2) of section 68 of the Finance Act and being unable to utilise the CENVAT credit availed on inputs and input

services for payment of service tax on such output services, shall be allowed refund of such unutilised CENVAT credit subject to procedure, safeguards, conditions and limitations, as may be specified by the Board by notification in the Official Gazette.

6. In the said rules, in rule 6,-

- (i) in the marginal heading, for the words “ provider of taxable service” the words, “ provider of output service” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of transportation of goods or passengers by rail the amount required to be paid under clause (i) shall be an amount equal to 2 per cent. of value of the exempted services.”

- (iii) in sub-rule (3A), in clauses (a), (b), (c) and (h), for the words “taxable” wherever they occur, the words, “output” shall be substituted;
- (iv) in sub-rule 3(B), for the words, brackets, letters and figures “providing taxable service specified in sub-clause (zm) of clause (105) of section 65 of the Finance Act” the words, “engaged in providing services by way of extending deposits, loans or advances” shall be substituted;
- (v) in sub-rule 3(D), for the Explanation I, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation I. - “Value” for the purpose of sub-rules (3) and (3A),—

- (a) shall have the same meaning as assigned to it under section 67 of the Finance Act, read with rules made thereunder or, as the case may be, the value determined under section 3, 4 or 4A of the Excise Act, read with rules made thereunder;
- (b) in the case of a taxable service, when the option available under sub-rules (7),(7A),(7B) or (7C) of rule 6 of the Service Tax Rules, 1994, has been availed, shall be the value on which the rate of service tax under section 66B of the Finance Act, read with an exemption notification, if any, relating to such rate, when applied for calculation of service tax results in the same amount of tax as calculated under the option availed; or
- (c) in case of trading, shall be the difference between the sale price and the cost of goods sold (determined as per the generally accepted accounting principles without including the expenses incurred towards their purchase) or ten per cent of the cost of goods sold, whichever is more.

(d) in case of trading of securities, shall be the difference between the sale price and the purchase price of the securities traded or one per cent. of the purchase price of the securities traded, whichever is more.

(e) shall not include the value of services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount;”

(vi) for sub-rule (6A), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(7) The provisions of sub-rules (1), (2), (3) and (4) shall not be applicable in case the taxable services are provided, without payment of service tax, to a unit in a Special Economic Zone or to a developer of a Special Economic Zone for their authorised operations or when a service is exported,

(8) For the purpose of this rule, a service provided or agreed to be provided shall not be an exempted service when:-

(a) the service satisfies the conditions specified under rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 and the payment for the service is to be received in convertible foreign currency; and

(b) such payment has not been received for a period of six months or such extended period as may be allowed from time-to-time by the Reserve Bank of India, from the date of provision.”

7. In the said rules, in rule 7,-

(i) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) credit of service tax attributable to service used in more than one unit shall be distributed *pro rata* on the basis of the turnover during the relevant period of the concerned unit to the sum total of the turnover of all the units to which the service relates during the same period.”

(ii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation 3. - (a) The relevant period shall be the month previous to the month during which the CENVAT credit is distributed.

(b) In case if any of its unit pays tax or duty on quarterly basis as provided in rule 6 of Service Tax Rules, 1994 or rule 8 of Central Excise Rules, 2002 then the relevant period shall be the quarter previous to the quarter during which the CENVAT credit is distributed.

(c) In case of an assessee who does not have any total turnover in the said period, the input service distributor shall distribute any credit only after the end of such relevant period wherein the total turnover of its units is available.”

8. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), in the proviso, for the words, "provider of taxable service", the words "provider of output service" shall be substituted;
9. In the said rules, in rule 13, for the words "taxable service" wherever they occur, the words, "output service" shall be substituted.

[F. No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note :-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, vide notification number 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004] and was last amended vide notification number 25/2012- Central Excise (N.T.), dated the 8th May, 2012, vide number G.S.R. 341 (E), dated the 8th May, 2012.